बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 18 अंक 20

ट्रंप के कदम और मंदी का जोखिम

इस वर्ष जनवरी में अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद से नीतियां चुनने के मामले में डॉनल्ड ट्रंप इतना आगे-पीछे हुए हैं कि बाजार भ्रम में पड़ गया है। अमेरिका के कुछ सबसे करीबी व्यापार साझेदारों पर शुल्क लगाया गया और फिर या तो हटा दिया गया या टाल दिया गया। कुछ लोगों को अब भी संदेह है कि ट्रंप वाकई शुल्क लगाना चाहते हैं या बातचीत में अपनी शर्तें मनवाने के लिए शुल्क की धमकी भर दे रहे हैं। कोई नहीं जानता कि ये शुल्क कब लगेंगे, कितनी हद तक लगेंगे और लगेंगे भी या नहीं। इसीलिए यह अनुमान लगाना भी मुश्किल हो गया है कि किसी खास क्षेत्र या पूरी अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर इनका क्या असर होगा। यही बात हौसला पस्त कर रही है। अमेरिका में कुछ लोगों को तो अचानक हौसला पस्त होने और लोगों की धारणा बदलने से मंदी आने का डर भी सताने लगा है। न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व के पास मंदी की संभावना का पैमाना है, जो मंदी के सभी अनुमानों को इकट्ठा कर बताता है। अगस्त 2025 में यह सूचकांक अब तक के तीसरे सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया और ऐसा दशकों बाद हुआ। इससे पहले उसने 1970 के दशक के मध्य में और 1980 के दशक के आरंभ में इतनी ऊंचाई छुई थी। दोनों ही मौकों पर अमेरिका में उत्पादन घट गया था। बॉन्ड यील्ड भी कैलेंडर वर्ष की बची अवधि के लिए ऐसी ही चिंता जता रही है। दो साल में परिपक्व होने वाले अमेरिकी बॉन्ड पर यील्ड पिछले कुछ हफ्तों में काफी कम हो गई है। इससे लगता है कि अर्थव्यवस्था धीमी हो जाएगी और फेडरल रिजर्व को दरें घटानी पड़ेंगी।

पिछले साल की उम्मीदों से यह एकदम उलट है। उस वक्त राष्ट्रपति चुनावों के नतीजे आने के बाद यील्ड तेजी से चढ़ी थी। माना जा रहा था कि ट्रंप कारोबार के लिए मददगार नीतियां लाएंगे, जिनसे वृद्धि को सहारा मिलेगा चाहे महंगाई भी बढ़े। उस समय लगा कि पहले करों में कटौती की जाएगी और उसके बाद शुल्क बढ़ाए जाएंगे। मगर ज्यादातर कारोबारी अब ऐसा नहीं मानते। बल्कि कुछ तो खुद राष्ट्रपति से पूछना चाहते हैं कि वह चाहते क्या हैं। रविवार को जब ट्रंप फॉक्स न्यूज पर दिखे तो उनसे सीधे पूछ लिया गया कि उनके कदमों से मंदी आने की कितनी संभावना है और ट्रंप को ऐसी किसी संभावना की परवाह नहीं दिखी। उन्होंने कहा कि भविष्यवाणी करना उन्हें पसंद नहीं है मगर अमेरिकी अर्थव्यवस्था में वह जितने बड़े बदलाव कर रहे हैं, उनके कुछ समय तक तो हलचल रहेगी। पिछले हफ्ते कांग्रेस में अपने संबोधन में भी उन्होंने यही संदेश दिया था और उनके प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों मसलन वाणिज्य मंत्री आदि की बातों से भी यही दिखा। मंत्री ने चेतावनी दी कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को सरकारी व्यय के नशे से छुटकारा दिलाना होगा।

सब जानते हैं कि शुल्क का इस्तेमाल करने से वृद्धि और मुद्रास्फीति पर क्या दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे। परंतु मध्यम अवधि में कुछ सकारात्मक असर भी हो सकते हैं। फिर यह उथलपुथल क्यों? शायद इसलिए क्योंकि अपने कदमों और उनके समय के बारे में बताने में प्रशासन एकदम लचर रहा है। साथ ही कंपनियों तथा निवेशकों को उनके हिसाब से ढलने का पर्याप्त समय भी नहीं दिया गया है। इसकी वजह से नकारात्मकता फैल गई। अर्थव्यवस्थाओं और अमेरिकी बाजारों में माल बेचने वाली कंपनियों जैसे भारत की सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों को आगे के लिए अनुमान लगाते समय मंदी के जोखिम का भी ध्यान रखना होगा। मार्के की बात है कि ट्रंप को दूसरे राष्ट्रपति कार्यकाल में अपने आर्थिक विचारों पर इस कदर यकीन है कि उनके लिए वह मंदी का भी जोखिम उठा सकते हैं। अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने कुछ व्यापार समझौतों पर दोबारा बातचीत की थी और कुछ शुल्क भी लगाए थे मगर इस बार उनके कदम ज्यादा व्यापक हैं और उनके लिए वह मंदी का जोखिम लेने को भी तैयार हैं।

अजय मोहंती

भारत के तकनीकी स्टार्टअप में तेजी

देश में तकनीकी स्टार्टअप में हो रही तेज वृद्धि को कारगर बनाने और उसमें मदद करने के लिए नीतियों में किस तरह के बदलाव की जरूरत है, समझा रहे हैं अजित बालकृष्णन

बिल्कुल सफेद बालों वाले मेरे मित्र बोले, 'हमें एहतियात बरतना होगा कि जरूरत से ज्यादा जोश में मामला बिगड़ न जाए।' मेरे मित्र प्रशासनिक सेवा से अरसे पहले रिटायर हो चुके हैं मगर उससे पहले उन्होंने औद्योगिक नीतियां बनाने वाली लगभग सभी शीर्ष सरकारी संस्थाओं में काम किया था। अब वह मुश्किल से बोल पाते हैं और सीधे चल भी नहीं पाते फिर भी नीतियों से जुड़ा कोई पेच परेशान करे तो मैं फौरन उनके पास पहुंच जाता हूं।

मैंने उनसे पूछा था, 'क्या आपको लगता है कि स्टार्टअप के लिए हमारी केंद्र और राज्य सरकारें जो गजब का उत्साह दिखा रही हैं उससे वाकई देश का बहुत भला होगा?' यह सवाल मैंने इसलिए किया था क्योंकि 1990 के दशक में जब मैं अपनी इंटरनेट स्टार्टअप रेडिफ डॉट कॉम पूरे जुनून के साथ चला रहा था तब भारत सरकार के नीति निर्माताओं ने विनम्रता के साथ मुझे बधाई दी थी, लेकिन उनके चेहरे पर अविश्वास झलक रहा था।

मेरे उन मित्र ने कहा, 'तकनीकी स्टार्टअप भारत की अर्थव्यवस्था के लिए यकीनन शानदार हैं।' उनकी बात सुनकर मैं खुश हो गया मगर तभी उन्होंने गंभीर सूरत के साथ कहा, 'लेकिन उम्मीद है कि यह 'आयात की जगह देसी उत्पादन' वाले बुखार की तरह नहीं है, जो बरबादी के अलावा कुछ नहीं था।' वह 1990 के दशक तक का दौर याद कर रहे थे, जब सरकार ने आयातित वस्तुओं की जगह देश में बनी वस्तुओं का इस्तेमाल बढ़ाने वाली नीतियों को खूब तवज्जो दी थी। इसके लिए ऊंचे शुल्क और दूसरे संरक्षणवादी उपायों का जमकर इस्तेमाल किया गया। कहा जाता है कि इसी वजह से उस दरम्यान भारत की आर्थिक वृद्धि बाकी दुनिया से धीमी रह गई मनमोहन सिंह ने 1991 में वित्त मंत्री बनने के बाद इसे विनाशकारी बताकर खत्म कर दिया।

उनकी बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया, ' क्या हमारी तकनीकी स्टार्टअप की फलती-फूलती दुनिया को कोई तबाह कर सकता है और वैसी ही बरबादी ला सकता है, जैसी आयात के बदले देसी माल की नीतियों से आई थी?'

स्टार्टअप के लिए इतना ज्यादा उत्साह देखकर मैं कल्पना ही नहीं कर पाया कि ऐसा भी हो सकता है। उदाहरण के लिए विश्व आर्थिक मंच की एक रिपोर्ट कहती है, 'पिछले 10 साल में देश में 1,20,000 से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हुई हैं और स्टार्टअप की तीसरी सबसे बड़ी दुनिया यहीं बन गई है।' इस मामले में अमेरिका और चीन ही हमसे आगे हैं। इतना ही नहीं तकरीबन हरेक आईआईटी (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान) और आईआईएम (भारतीय प्रबंध संस्थान) में स्टार्टअप इनक्यूबेशन सेंटर बनाए गए हैं तथा कई शहरों में टेक्नॉलजी पार्क स्थापित किए गए हैं। इसके बाद भारत भर में अटल इनक्यूबेशन सेंटर जैसी संस्थाएं और नैस्कॉम द्वारा चलाए जा रहे इनोवेशन सेंटर हैं। ये प्रयास स्कूलों तक पहुंच गए हैं। छात्रों के बीच नवाचार बढ़ाने के लिए देश के करीब 10,000 स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब बना दी गई हैं।

स्टार्टअप के लिए भारत जिस कदर कोशिश कर रहा है, उसे देखकर मुझे ताज्जुब होता है कि उनके सामने बड़ी चुनौतियां आ भी सकती हैं या नहीं। मैंने तो पत्रिकाओं में लेख लिखने वाले विद्वानों और वेंचर कैपिटल फर्म के साझेदारों को हमेशा से यही कहते सुना है कि नए प्रौद्योगिकीगत नवाचारों के लिए भारत का देसी बाजार बहुत छोटा है।

जब मैंने और भी वेंचर कैपिटल विशेषज्ञों से बात की तब मुझे पता चला कि भारत में तकनीकी स्टार्टअप के लिए बड़े पैमाने पर काम करना मुश्किल क्यों है: सबसे पहली वजह यह है कि देश की बड़ी आबादी पैसावसूल किस्म की है। नई तकनीक उन्हें पसंद आए तो भी उसका किफायती होना जरूरी है। फिर सांस्कृतिक कारण आता है। मसलन भारतीय समाज का एक हिस्सा नई तकनीक तभी अपनाता है, जब वे अच्छी साबित हो जाएं और खूब इस्तेमाल होने लगें। उसके बाद 'वैल्यू फॉर मनी' की मानसिकता आ जाती है यानी मौजूदा तकनीकों से बहुत बेहतर तकनीक होने पर भी वे तभी अपनाएंगे, जब उसकी कीमत भारतीय बाजार के हिसाब से हो।

बाकी विशेषज्ञों ने मुझसे पूछा: आंकड़े बताते हैं कि दुनिया में 90 फीसदी स्टार्टअप नाकाम हो जाती हैं, इस पर क्या कहेंगे? ऐसी स्टार्टअप को मदद देने का हमारा क्या तरीका है? क्या हमारे पास भारत में बनने वाली स्टार्टअप की लंबी कतार को मदद करने के लिए पर्याप्त भारतीय वेंचर कैपिटलिस्ट हैं? क्या हमारी आयकर नीतियां स्टार्टअप निवेश का ख्याल रखती हैं?

यह सब सुनकर और बतौर उद्यमी इनमें से कुछ समस्याओं से खुद रूबरू होने के कारण मुझे देश में एक हाइटेक कामयाबी का एक उदाहरण बरबस ही याद आ जाता है: यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई)। मुंबई में मैं कोलाबा में रहता हूं और जब देखता हूं कि रिक्शा वाले और मछुआरिन सड़क किनारे फल की दुकान पर अपना मोबाइल फोन निकालते हैं और क्यूआर कोड स्कैन कर भुगतान कर देते हैं। यह देखकर मुझे कई बार तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता।

देश में यूपीआई की कामयाबी तकनीक, नीति और सामाजिक आर्थिक कारकों के संगम का शानदार उदाहरण है। यह तकनीकी जीत भर नहीं है बल्कि राजनीतिक अर्थव्यवस्था की भी अहम कामयाबी है, जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। यूपीआई बनाने और चलाने का काम सरकारी कंपनी एनपीसीआई कर रही है, जिसे रिजर्व बैंक और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने गैर लाभकारी संस्था के तौर पर तैयार किया था। यूपीआई की कामयाबी के पीछे बड़ी वजह यही कंपनी है क्योंकि यह गैर लाभकारी है, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की फिराक में लगी निजी कंपनी नहीं।

दूसरी बात, यूपीआई डिजिटल बुनियादी ढांचे की दूसरी पहली आधार, ई-केवाईसी और डिजिलॉकर से जुड़ा है। सरकार ने कैशबैक और छूट के जरिये यूपीआई का खूब प्रचार प्रसार भी किया। इस बात से भी मदद मिली कि यूपीआई को ओपन एपीआई ढांचे पर तैयार किया गया है, जिस कारण कोई भी बैंक या कंपनी यूपीआई से जोड़े जाने लायक ऐप्लिकेशन बना सकती है। सरकार ने शुरू में एक तय रकम से नीचे के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगने दिया था, जिससे व्यापारियों ने इसे हाथोहाथ अपनाया क्योंकि कार्ड मशीन पर उन्हें शुल्क देना पड़ता है। इस तरह नकद पर बहुत निर्भर रहने वाला देश धीरे-धीरे डिजिटल भुगतान की ओर चला गया।

क्या यूपीआई के उदाहरण में हम सबको यह सबक नहीं मिलता है कि अपनी स्टार्टअप को दुनिया भर में सफल कैसे बनाया जाए?

खनिज की बिसात पर भारत पीछे

खनिज एवं अन्य संसाधन खोजने की ललक ही 16वीं शताब्दी से यूरोपीय उपनिवेशवाद के प्रसार की बड़ी वजह रही थी। सोना, हीरा और दूसरे कीमती संसाधनों की खोज में यूरोप के ताकतवर देशों ने दुनिया का चप्पा-चप्पा छान मारा और बाद में एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के कई देशों पर राज करने लगे। उत्तर अमेरिका की खोज भी तब हुई जब स्पेन नई जमीन और संसाधनों की तलाश में निकला।

पुराने दौर का उपनिवेशवाद खत्म हो गया मगर आज भी खनिज एवं ईंधन की लालसा ही भू-राजनीति की दिशा और चाल तय कर रही है। 20वीं सदी की भू-राजनीति काफी हद तक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से ही तय हुई, जो सिलसिला इस सदी में भी चल रहा है। अब स्वच्छ ऊर्जा के लिए जरूरी खनिजों की तलाश युद्ध और गठबंधनों की जमीन तैयार कर रही है। अब तो खनिज के बदले विदेशी सहायता भी मिल रही है।

आज विकसित तथा समृद्ध देश अपने यहां उत्सर्जन घटाने और स्वच्छ ऊर्जा बढ़ाने के लिए विकासशील देशों के खनिज भंडारों का दोहन करने के फेर में हैं। उनकी इन्हीं कोशिशों को 'ग्रीन कॉलोनियलिज्म' या 'ईको कॉलोनियलिज्म' का नाम दिया गया है। लैटिन अमेरिकी और अफ्रीकी देशों में मौजूद लीथियम, कोबाल्ट, निकल और दुर्लभ मृदा तत्वों के भंडार ही आज अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम की दशा-दिशा तय कर रहे हैं। अमेरिका ने यूक्रेन से कहा है कि उसके खनिज भंडार पर टिकाऊ समझौता हो गया तो उसे मिल रही अमेरिकी मदद जारी रहेगी। यह खनिजों की भू-राजनीति का ही उदाहरण है।

पश्चिम के देश हमेशा से ही आवश्यक खनिजों और पेट्रोलियम भंडारों पर कब्जा करने तथा एकाधिकार जमाने की कोशिशों में आगे रहे हैं मगर अब चीन ने भी यह कला सीख ली है। उसके पास भी दुर्लभ खनिजों का बड़ा भंडार है मगर वह दूसरे विकासशील देशों में मौजूद लीथियम, कोबाल्ट, निकल और अन्य खनिजों के भंडार पर कब्जा करने के लिए पूरी शिद्दत से लगा हुआ है।

प्रसेनजित दत्ता

खनिज एवं ऊर्जा से जुड़ी भू-राजनीति में भारत हमेशा से फिसड्डी रहा है। एक के बाद एक सरकारें भारत की ऊर्जा जरूरतें पूरी करने एवं सुरक्षित करने के उपायों पर बड़ी-बड़ी बातें करती आई हैं मगर इस दिशा में कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया है। इक्का-दुक्का कोशिश हुई हैं मगर वे भी कुछ समय बाद रुक गईं। ओएनजीसी के स्वामित्व वाली कंपनी ओएनजीसी विदेश की दुनिया के 15 देशों में तेल-गैस के 35 संभावित भंडारों में भागीदारी है मगर इससे हमारी तेल सुरक्षा में या तेल आयात पर होने वाले खर्च में खास फर्क नहीं दिखा है। निजी क्षेत्र ने भी मामूली दिलचस्पी ही दिखाई है।

भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के लिए लंबे-चौड़े लक्ष्य तो तय कर लिए हैं मगर लग नहीं रहा कि देश के नीति निर्धारकों ने कोई सबक लिया है। भारत खनिज की खोज करने वाले कई समूहों में शामिल है और उन देशों के साथ अलग से बातचीत भी कर रहा है, जिनके पास हरित ऊर्जा के लिए आवश्यक खनिजों का भंडार है। लेकिन न तो उसका तरीका सही है और न ही वह दूर की सोचकर आगे बढ़ रहा है।

खनिज पर फिलहाल चल रही भू-राजनीति में दो मोटे नजरिये साफ दिख रहे हैं। पश्चिम यूरोप के देश और कुछ हद तक अमेरिका अपने भंडारों का इस्तेमाल करने के बजाय गरीब एवं विकासशील देशों के खनिज भंडारों का दोहन करने पर जोर देंगे क्योंकि वे अपने देश में कार्बन उत्सर्जन और पर्यावरण प्रदूषण कम से कम रखना चाहते हैं। उदाहरण के लिए हाल के अध्ययनों से पता चला है कि पश्चिमी यूरोप के तमाम देशों में कोबाल्ट, लीथियम और दुर्लभ मृदा तत्वों के अच्छे भंडार हैं मगर वे उनका इस्तेमाल शायद तभी करेंगे जब तय हो जाएगा कि दूसरे देशों से खनिज नहीं मिल सकते। अमेरिका में भी लीथियम का विशाल भंडार है मगर पर्यावरण की चिंताओं के कारण वह उसका इस्तेमाल करने से कतरा रहा है। राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप इस नीति में बदलाव करते हैं या नहीं इसका पता आगे चलकर ही लगेगा।

खनिज भू-राजनीति पर दूसरा नजरिया चीन वाला है। चीन अपने भंडार का जमकर इस्तेमाल कर रहा है मगर खनिज संपन्न देशों से समझौते भी कर रहा है। कॉन्गो की कोबाल्ट खानों पर चीन का कब्जा इसका अच्छा उदाहरण है। मगर अहम बात यह भी है कि चीन अपने यहां खनिज भंडार ढूंढकर और उनसे खनिज निकालकर दुर्लभ मृदा खनिजों की आपूर्ति में भी आगे बना हुआ है। लीथियम और दूसरे जरूरी खनिजों के प्रसंस्करण से बहुत अधिक प्रदूषण होता है मगर चीन ने अपने यहां इनकी सबसे बड़ी प्रसंस्करण इकाइयां लगाई हैं ताकि दुनिया भर में इनकी आपूर्ति पर उसका दबदबा बना रहे।

भारत ने दोनों में से कोई तरीका नहीं अपनाया है। इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी में लीथियम और कुछ अन्य खनिज इस्तेमाल होते हैं मगर इनके प्रसंस्करण के लिए हमारी क्षमता नहीं के बराबर है। सौर और पवन ऊर्जा के लिए जरूरी दुर्लभ खनिजों के लिए हम काफी हद तक चीन पर निर्भर हैं, जो बड़े जोखिम की बात है। हम अपने देश में खनिज तलाशने में भी पीछे रहे और दूसरे देशों से आपूर्ति के समझौते करने में भी ढीले हैं।

भारत में लीथियम, निकल, दुर्लभ मृदा तत्वों या कोबाल्ट और दूसरे खनिजों के भंडार छोटे हैं या बड़े हैं इसका पता तो तभी चलेगा, जब हम पर्याप्त संसाधनों के साथ इनकी तलाश में जुटेंगे। साथ ही इन खनिजों को तलाशने और निकालने के लिए सही नीतियां होना भी जरूरी है। फिलहाल तो भारत में इन खनिजों के विशाल भंडार होने का कोई सबूत नहीं है मगर भंडार बिल्कुल नहीं होने का भी कोई सबूत नहीं है। इनकी खोज का काम नीतिगत बाधाओं एवं दिलचस्पी की कमी के कारण ही सुस्त है। जिन देशों के पास इन खनिजों के विशाल भंडार हैं उनके साथ समझौते करने में भी भारत काफी पीछे रहा है।

वास्तव में हमें दोनों दिशाओं में कदम उठाने चाहिए। ऐसा नहीं करेंगे तो ऊर्जा आयात पर होने वाला भारी भरकम खर्च नहीं थमेगा और महत्त्वपूर्ण खनिजों के लिए चीन पर हमारी निर्भरता कभी कम या खत्म नहीं होगी। ऊर्जा का अपना अर्थशास्त्र दुरुस्त और सुरक्षित रखने के लिए हमें दूरगामी नजर के साथ लगातार प्रयास करने की जरूरत है।

(लेखक बिजनेसवर्ल्ड और बिजनेस टुडे के संपादक रह चुके हैं तथा संपादकीय परामर्श संस्था प्रोजैक ब्यू के संस्थापक हैं)

आपका पक्ष

कैंसर: शारीरिक, मानसिक और आर्थिक संघर्ष की लड़ाई

कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से भी व्यक्ति और उसके परिवार को प्रभावित करती है। भारत में कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 2022 में भारत में 14 लाख से अधिक नए कैंसर मामले दर्ज किए गए और 9 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। महिलाओं में स्तन कैंसर और पुरुषों में मुख और फेफड़ों के कैंसर के मामले सबसे अधिक हैं। अनियमित जीवनशैली, तंबाकू, शराब और प्रदूषण इसके प्रमुख कारण हैं। सरकारी अस्पतालों में लंबी कतारें और निजी अस्पतालों में अत्यधिक खर्च के कारण गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए इलाज पाना मुश्किल हो जाता है। सरकार को कैंसर का इलाज सस्ता और सुलभ बनाना चाहिए। कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी की दवाइयों की कीमत कम करने के साथ निजी अस्पतालों की मनमानी फीस पर नियंत्रण लगाया जाए। जनता को स्वास्थ्य बीमा योजनाओं से जोड़कर आर्थिक बोझ को कम किया जा सकता है।

राजूराम प्रजापत, नागौर

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 2022 में भारत में कैंसर के 14 लाख मामले दर्ज किए गए और 9 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई

ईवी खरीद पर मिले प्रोत्साहन

ई-वाहनों की कीमतें अपेक्षाकृत अधिक होती हैं। इनकी बिक्री में वृद्धि के लिए सरकारी नीतियों को उपभोक्ताओं के हित में बनाते हुए सब्सिडी और छूट देनी चाहिए। वाहन कंपनियों के लिए नियमों को शिथिल किया जाए। जिससे लागत में कमी हो पाएगी। चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने और चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क बढ़ाने की आवश्यकता है।

रामबाबू सोनी, इंदौर

सस्ती बैटरी पर हो जोर

लंबी अवधि तक चलने वाली बैटरी अगर चलन में आती है तथा फ्री चार्जिंग स्टेशन की उपयुक्त व्यवस्था होगी तो उपभोक्ता का रुझान ई-वाहनों की ओर बढ़ेगा। ई-वाहन बनाने वाली सबसे बड़ी अमेरिकी कंपनी टेस्ला व वियतनाम की ईवी कंपनी विन्फास्ट का भारत में निवेश भी ई-वाहनों को लोकप्रिय बनाएगा। घरेलू कंपनियों को भी समान अवसर व लाभ दिए जाने चाहिए।

विमलेश पगारिया, बदनावर

ईवी की लागत कम हो

देश में ई-वाहन अभी तक लाभदायक नहीं बन पाए हैं। हालांकि बैटरी का विकास अपेक्षा से कहीं अधिक तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन कुल लागत कम करने और पारंपरिक ईंजन वाहनों के साथ समानता प्राप्त करने के लिए रेंज और बुनियादी ढांचे में सुधार करना बाकी है। सरकार को ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बेहतर नीतियां बनानी चाहिए।

धीरेंदु सोमानी, बेंगलूरु

चार्जिंग स्टेशन बढ़ाएं

ई-वाहनों के प्रति लोगों को आकर्षित करने के लिए चार्जिंग स्टेशन और मार्केटिंग बढ़ाने की जरूरत है। इससे संबंधित उद्योगों को सब्सिडी देना भी आवश्यक है। इन वाहनों में आग लगने की घटनाओं को रोकने के उपाय किए जाने चाहिए। चार्जिंग में समय कम लगे और लंबी दूरी तय कर सके ऐसी तकनीक विकसित करने की आवश्यकता है।

शकुंतला महेश नेनावा, इंदौर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

तिब्बती जनक्रांति दिवस की 66वीं वर्षगांठ पर सोमवार को नई दिल्ली में तिब्बती समुदाय के लोगों ने चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। मंगलवार, 11 मार्च 2025

लोकतंत्र को वक़्त मिले

क्या पड़ोसी देश नेपाल एक बार फिर किसी बड़ी उथलपुथल से गुजरने वाला है? यह सवाल इसलिए उठा क्योंकि रविवार को काठमांडू में नेपाल के पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र के पक्ष में बड़ा प्रदर्शन हुआ। न केवल पूर्व राजा के स्वागत में एयरपोर्ट पर हजारों की भीड़ उमड़ी बल्कि राजशाही की वापसी के नारे भी लगाए गए।

पहले से थी तैयारी । खास बात यह कि इस प्रदर्शन को पूरी तरह आकस्मिक या स्वतःस्फूर्त नहीं माना जा सकता। करीब दो महीने से इसकी तैयारी की जा रही थी। पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र इस दौरान नेपाल के अलग-अलग हिस्सों में दर्जनों मंदिरों में गए। राजनीतिक हलकों में इसे देश के दूर-दराज के इलाकों में अपनी लोकप्रियता जांचने की उनकी मुहिम के रूप में देखा जा रहा था।

राजशाही के लिए प्रदर्शन

ओली के खिलाफ नारे । काठमांडू में हुए इस प्रदर्शन में लगाए जाने वाले नारे ज्यादातर तो राजा और राजशाही के समर्थन तक ही सीमित रहे, लेकिन एकाध मामलों में मौजूदा पीएम केपी ओली के खिलाफ भी नारे सुने गए। ओली पूर्व नरेश को सांवैधानिक रूप से यह चुनौती दे चुके हैं कि अगर वे सत्ता में लौटने के इतने ही इच्छुक हैं तो अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनाकर चुनाव लड़ लें।

निशाने पर लोकतंत्र । असल में प्रदर्शन का मकसद अपने पूर्व राजा के प्रति सम्मान प्रदर्शित करना भर नहीं लगता। 2006 में हुए ऐसे ही प्रदर्शनों के बाद नेपाल के तत्कालीन राजा ज्ञानेंद्र को सत्ता छोड़नी पड़ी थी। इसके 2 साल बाद 2008 में नेपाल धर्मनिरपेक्ष गणराज्य घोषित किया गया। ऐसे में अगर राजशाही की वापसी और हिंदुत्व को राजधर्म घोषित करने की मांग सड़कों पर हो रही है, तो साफ है कि यह टकराव आगे चलकर गंभीर रूप ले सकता है।

राजनीतिक अस्थिरता । इसमें दो राय नहीं कि 2008 में गणराज्य घोषित होने के बाद से लोकतंत्र की राह पर नेपाल की यात्रा बाधाओं से भरी रही है। राजनीतिक स्थिरता नहीं कायम की जा सकी। 17 वर्षों की इस अवधि में वहां 13 सरकारें बन चुकी हैं। लेकिन किसी भी देश में लोकतांत्रिक चेतना विकसित होने में वक्त लगता है। सत्ता के लिए राजनीतिक दलों का आपस में झगड़ना किसी भी लोकतंत्र के लिए स्वाभाविक बात है। इसका मतलब यह नहीं माना जा सकता कि लोकतंत्र के अपहरण की स्थिति बनने पर भी वे एक नहीं होंगे।

धूप-छांव

उलझनें कम नहीं

प्रणव प्रियदर्शी

भूख तो हमें महसूस होती थी। दुविधा दूसरी थी। बड़े लोग कहते थे, 'पेट से ज्यादा मत खाओ। जब पेट भरे उससे दो कौर पहले ही खाना छोड़ देना चाहिए।' यह बात बहुत उलझाने वाली थी। पेट में कोई अलार्म तो लगा नहीं है जो बता दे कि अब पेट भरने वाला है और आप खाना बंद कर दें। एक कल्पना यह होती थी कि अगर गले तक का पूरा स्पेस भर जाएगा तो खाना गले से नीचे उतरेगा ही नहीं। तब खाना छोड़ा जा सकता है। लेकिन दो कौर के बाद पेट गले तक भरेगा यह कैसे पता चले। बदन कोई शीशे का पारदर्शी ग्लास तो है नहीं कि दिखता रहे कितना भरा और कितना खाली है। समय के साथ यह उलझन सुलझ गई। कैसे यह तो पता नहीं, लेकिन धीरे-धीरे अहसास हो गया कि अपना शरीर ही बता देता है, भई अब बस करो।

शरीर के विकास के क्रम में ही नई उलझनें भी आती रहीं। मसलन, जब पहली बार चेहरे पर दाढ़ी आई तो लंबे समय तक मैंने उससे किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की। आसपास के लोग कहते कि दाढ़ी बढ़ गई है, बनवाते क्यों नहीं। मैं टाल देता। एक दिन मां के जोर देने पर उसे अपने अंदर का डर बताया कि, 'ब्लेड या उस्तरा फिराने से दाढ़ी के साथ यह चेहरा भी तो छिलेगा।' मां ने डांटते हुए कहा, 'दुनिया भर के सब लोग दाढ़ी बनवाते हैं, किसी का चेहरा नहीं छिलता, तुम्हारा छिल जाएगा? और इतना ही डर लग रहा है तो सैलून में जाकर करवा लो। वहां तो उस्तरे वाले का अनुभवी हाथ कोई गलती नहीं करेगा।'

मन के स्तर पर भी कम उलझनें नहीं आईं। सभी कहते, अंदर से जो सही लगे, वही करना चाहिए। लेकिन हमारी दिक्कत दूसरी थी। कोई सहपाठी लंच ब्रेक के बाद बंक मारकर फिल्म देखने या फुटबॉल मैच देखने का प्रस्ताव रख देता तो सबके अंदर की आवाज उसे सही करार देती। लेकिन क्लास टीचर की बेंत इस बात की परवाह नहीं करती थी कि किसके अंदर की आवाज ने क्या कहा था। वह सटाक-सटाक अपनी आवाज सुनाती। सो, अमूमन हम सब अंदर की आवाज सुनने का रिस्क नहीं उठाते थे। कानों में गूंजती सटाक-सटाक की आवाज ज्यादा स्पष्ट और निर्णायक हुआ करती थी।

बोल वचन

किसे अगोर रहे हो

राहुल पाण्डेय

हममें से हर कोई कुछ न कुछ अगोरता रहता है। किसान है तो बारिश अगोर रहा है, मजदूर है तो मजदूरी। चकोर चांद अगोरता है तो पलाश वसंत। अगोर यानी राह देखना, बाट जोहना, इंतजार करना, देखना, ताकना। लेकिन अगोरना बस इतना ही नहीं है। यह रोकना भी है तो छेंकना भी है। अगोर या अगोरना खड़ी फसल की रखवाली या पहरेदारी करना भी होता है, हालांकि मिथिला में यह किसी भी चीज की रखवाली हो सकती है। यही अगोर जब अवधी से अंगिका में जाता है तो इसका अर्थ जोगना यानी बचाना भी हो जाता है। बुंदेलखंड में यह आगे की भूमि यानी खेत का पहला सिरा है। ब्रज में भी सब कान्हा को खूब अगोरते हैं, क्योंकि वहां भी इसका मूल अर्थ प्रतीक्षा से है, बाट जोहने से है। लेकिन ब्रज में इसका अर्थ बंद करना और छिपाकर रखना भी है। जड में कोटि जतन करि राखति, घूंघट ओट अगोरि। तउ उड़ि मिले बाधिक के खग ज्यों, पलक पांजरा तोरि। यहीं पर इसका एक अर्थ खींचना या आकर्षित करना भी होता है। शब्दकोश में इसके लिए यह उदाहरण दिया है- कनकलता सी आगे ठाढी तन और दृष्टि अगोरति। बात शब्दकोश की चली है तो इंग्लिश के शब्दकोश में इसके लिए एक ही शब्द- waiting है। जाहिर है, इंतजार न तो पहरेदारी होता है, और न ही रिझाना हो सकता है।

ट्रंप एक व्यापारी हैं और उन्हें धंधा चाहिए, उनसे धंधे की भाषा में बात करने में हर्ज़ क्या है

क्या हमें ट्रंप का शुक्रगुज़ार होना चाहिए

संजय खाती

इस वक्त दुनिया की सांस अटकी हुई है। पता नहीं ट्रंप क्या कर डालें। अच्छा है कि भारत ने समय रहते आगे बढ़कर इस मुसीबत का मुकाबला करने का जतन दिखाया है। हालांकि ट्रंप के मिजाज के बारे में कुछ भी पहले से कहना खतरे से खाली नहीं, लेकिन कुछ अनुमान तो लगाए ही जा सकते हैं और कहना होगा कि शायद भविष्य वैसा नहीं है जैसा हमें हमारा डर दिखा रहा है। बहुत मुमकिन है कि आने वाला वक्त भारत के लिए कई पॉजिटिव लेकर आए और ट्रंप असल में हमारे लिए एक अच्छे वक्त का मौका बन जाएं। क्या ट्रंप भारत को उसकी किस्मत से मिलाने की साजिश कर रहे हैं? इन पांच बातों पर गौर करें;

उठो जागो । सरकार इसे अमृतकाल कहती है और भारत का इरादा अगले 22 वर्षों में विकसित देश बनने का है। लेकिन हमें कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि यह मकसद बिना अभूतपूर्व उड़ान भरे मुमकिन है। हकीकत यह है कि क्रिएटिविटी और इनोवेशन के मामले में भारत बहुत ही पीछे है। भारत में ऐसे प्रोडक्ट नहीं हैं, जो दुनिया में बड़ा दबदबा रखते हों। भारतीय कंपनियां ग्लोबल कंपनियों के सामने बेहद छोटी हैं भले ही उनके मालिक दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में ऊपर आते हों। आज भी हमारा जीवन विदेशी कंपनियों और टेक्नॉलजी की उधारी पर टिका हुआ है। एक मिसाल, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की लीजिए। चीन की BYD इलेक्ट्रिक कार मार्केट की बादशाह बनने के करीब है। और भी ऐसे कई उदाहरण आसपास मौजूद हैं। AI के मामले में देखिए। यहां हालात तेजी से अब इसलिए बदले हैं कि चीन के Deepseek ने भारत सहित पूरी दुनिया में इस भंडाफोड़ से सनसनी फैला दी कि बड़े काम के लिए डॉलर का ढेर नहीं तेज दिमाग ज्यादा जरूरी है। तो इस मुद्दे का संबंध ट्रंप से कैसे है? इस तरह कि जब अमेरिका से हमें टैरिफ का मुकाबला करना पड़ेगा तो हम यही कर सकेंगे कि खुद को ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर बनाएं। यानी आसान रास्ते में बेहतर और जुझारू बनने की कोशिश ले जाएगी। यही तब हुआ था जब लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का दौर आया था और कहा जाता था कि बाजार खुलते ही भारत का सफाया हो जाएगा। यही कोविड के बाद हुआ था। आप देखिए कि भारत ने डिफेंस प्रोडक्शन जैसे कई इलाकों में अपनी काबिलियत को कितना बढ़ा लिया है। यानी अगर भारत पर टैरिफ लगते हैं और उससे ट्रेड में फिलहाल कुछ नुकसान होता है, तो भी आगे चलकर हम ज्यादा इनोवेटिव और प्रोडक्टिव होने के थोड़ा मुश्किल लेकिन बहुत जरूरी सफर पर निकल सकते हैं।

भारत के लिए मौके

- अमेरिका की मदद से इनोवेशन में आएगी तेजी
- रूस-अमेरिका की दोस्ती भारत के लिए फायदेमंद
- भारत वापस लौट सकते हैं विदेशी निवेशक
- भारत और अमेरिका दोनों का दुश्मन है चीन

पैसा इधर बनेगा । यह तो रही थोड़ी दूर की बात। अभी तात्कालिक फायदा भी मुमकिन है। आप जानते हैं कि इस वक्त विदेशी निवेशक भारत से निकल रहे हैं, क्योंकि उन्हें अमेरिका में अच्छा माहौल दिख रहा है और भारत की ग्रोथ रेट को लेकर उनके मन में सवाल पैदा हो चुके हैं। लेकिन अभी कुछ दिनों से यह सिलसिला थमता दिख रहा है, क्योंकि ट्रंप की इकॉनमिक्स खुद अमेरिका में सवालों के घेरे में आ रही है। अंदेशा है कि ट्रंप जिस हिसाब से टैरिफ लगा रहे हैं, उससे अमेरिकी इकॉनमी का अच्छा-खासा नुकसान हो सकता है। टैरिफ का मतलब है इनपुट कॉस्ट बढ़ना यानी अमेरिका में चीजें महंगी होने लगेंगी और ओवरऑल महंगाई की दर ऊपर जाएगी। ऐसा होता है तो वहां इंटरेस्ट रेट घटने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी और डॉलर कमजोर होगा, जो कि पिछले दिनों में तेजी से हुआ भी है। यही हाल बॉण्ड का भी होगा। ये बातें अमेरिकी मार्केट को कमजोर करेंगी और वहां जाता हुआ पैसा ठिठक जाएगा। बल्कि हो सकता है कि वह भारत जैसे उभरते हुए बाजार में वापस लौटने लगे। इस बीच अगले कुछ महीनों में भारत की GDP में ठीक-ठाक सुधार दिखने लगे तो फिर से पुराने अच्छे दिनों की वापसी का रास्ता खुल जाएगा। पिछले कुछ दिनों में बाजार में हुई रिकवरी शायद इस बदलाव का संकेत दे रही है।

हम साथ-साथ थे । अभी तीन महीने पहले क्या कोई सोच सकता था कि अमेरिका और रूस आपस में दोस्त बन जाएंगे जबकि यूक्रेन में लड़ाई चल रही होगी? लेकिन ट्रंप ने ऐसी अनहोनी कर दिखाई और भारत के लिए जैसे एक जबरदस्त मौका बैठे-बिठाए हाजिर हो गया। यूक्रेन की लड़ाई शुरू होने के बाद बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने एड़ी-चोटी का जोर लगा लिया था कि भारत, रूस से अपनी दोस्ती को खारिज करे और पूरी तरह अमेरिकी खेमे में पेश हो जाए। ज्यादातर समझदार लोगों को लगता था कि रूस से चिपके रहने में अब कोई भलाई नहीं है और जब अमेरिका मौका दे रहा है तो खुलकर उसके साथ हो लिया जाए। आखिर अमेरिकी दोस्ती के सामने रूस जैसे ढलते हुए सुपर पावर का क्या भविष्य रह जाता है। भारत सरकार ने इसको नजरअंदाज करते हुए काफी दबाव झेल कर रूस से अपना रिश्ता बचाए रखा और आज देखिए कि हम दो सबसे बड़ी ताकतों के साथ बढ़िया रिश्ते में बंधे हुए हैं। इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ। सोचिए, भारत के हितों को कितनी तवज्जो मिलेगी, जब आगे चलकर भी अमेरिका और रूस का यह अलायंस चलता रहेगा।

चाइना फैक्टर । ऐसा लगता है कि ट्रंप के इस रूस प्रेम के पीछे चीन का फैक्टर काम कर रहा है। ट्रंप के मिजाज को लेकर सिर्फ एक ही बात पक्की है कि उन्हें चीन के खिलाफ मोर्चा बनना है। एकदम खुले तरीके से अमेरिका ने चीन को अपना प्रतिद्वंद्वी नंबर वन घोषित कर रखा है और यही एक ऐसी पॉलिसी है जो अमेरिका की दोनों पार्टियों के अजेंडे में है। यानी चार साल बाद ट्रंप की रुखसती के बाद भी इसे चलते रहना है। जाहिर है, इस तरह की मोर्चाबंदी तभी हो सकती है, जब चीन को अकेला कर दिया जाए। अगर उसका रूस के साथ मौजूदा अलायंस बना रहता है तो आगे चलकर अमेरिका के लिए एक साथ दो-दो बड़ी ताकतों से निपटना मुश्किल पड़ सकता है। तमाम घेरेबंदी के बावजूद रूस ने साबित कर दिया है कि वह अमेरिका और यूरोप की ताकत को झुका सकता है। फिर चीन की तो बात ही इससे आगे है। जैसा कि जाहिर है अमेरिका का यह सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी भारत का भी सबसे बड़ा दुश्मन रहा है और आगे भी बना रह सकता है। ऐसे में भारत की अमेरिका के लिए अहमियत किसी भी हाल में बढ़ेगी ही बढ़ेगी। हम धीरे-धीरे इस आशंका को सच साबित होता देख सकते हैं कि ताइवान या किसी दूसरे मामले को लेकर अमेरिका और चीन सीधे टकराव के करीब पहुंच जाएं। जब भी ऐसा होगा भारत की जरूरत पड़ेगी। ट्रंप इस ऐतिहासिक प्रक्रिया को तेज करते हुए नजर आते हैं। बहुत मुमकिन है कि भारत को F16 विमान बेचने का उनका प्रस्ताव इसी दिशा में संकेत करता हो। वरना तो इस विमान को हासिल करने की कोई संभावना भारत के पास थी नहीं।

जुड़े सब बारी-बारी । हमारे विदेश मंत्री ने अभी कहा है कि दुनिया मल्टीपोलर होती जा रही है और यह भारत के लिए अच्छा है। कुछ ही दिनों पहले इसका एक बढ़िया नजारा देखने को मिला जब यूरोपीय यूनियन का लंबा-चौड़ा डेलिगेशन भारत आ पहुंचा। ट्रंप ने जो खलबली मचाई है इसका सबसे बड़ा असर यूरोप पर ही देखने को मिल रहा है। यूरोप के सामने अमेरिका से आजाद होने का चैलेंज है और उसके लिए वहां जबरदस्त तैयारी भी दिख रही है। यूक्रेन को लेकर ब्रिटेन ने मोर्चा संभाल लिया है। फ्रांस और जर्मनी जबरदस्त तरीके से अपनी डिफेंस तैयारी को आगे ले जाने में जुट रहे हैं। यानी दूसरे विश्वयुद्ध के बाद अब जाकर एक ऐसा यूरोप उभरने वाला है जो अमेरिका और चीन के दो ध्रुवों के बीच बराबरी की टक्कर दे सकता है। इस यूरोप को पता है कि भारत उसके लिए कितना जरूरी है। इसीलिए इस तरह की आवाजाही हम आने वाले वक्त में लगातार देखते रहेंगे। एक अच्छी बात यह हो गई है कि यूरोप के सबसे ताकतवर देश फ्रांस से हमने शानदार दोस्ती गांठ रखी है। यानी यूरोप के दिल में भारत की बहुत बड़ी जगह बन चुकी है और यह बात भारत को एक अद्वितीय स्थिति में रखने वाली है, जहां चीन को छोड़कर हर बड़ा खेमा भारत को तवज्जो देने पर मजबूर होगा।

आखिरी बात यह कि सौदेबाज या ट्रांजैक्शनल होना कोई इतनी बुरी बात नहीं है। ट्रंप एक व्यापारी हैं और उन्हें धंधा चाहिए। हम उनके मिजाज को तो बदल नहीं सकते, लेकिन उनसे धंधे की भाषा में ही बात कर लेने में क्या हर्ज है? बल्कि फायदा यह है कि इस तरह की सौदेबाजी में बातें तो साफ-साफ रहती हैं और डिप्लोमैसी की उलझन खत्म हो जाती है। क्या बुरा है कि ट्रंप के साथ सौदेबाजी में कुछ अच्छे सौदे भारत के हाथ भी लग जाएं। दुनिया का कारोबार ऐसे ही चलता है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

वे आज की नारी तो हम भी कल के मर्द हैं

नमिता जोशी

आखिरकार, मुन्ना भाई और सर्किट दिल्ली आ ही गए! स्टेशन पर स्वागत किया दिल्ली के नामी फुकरे ने, जो खुद को वसूली भाई टाइप की चीज समझता था। जैसे ही मुन्ना भाई और सर्किट प्लैटफॉर्म से बाहर निकले, एकदम मेंढक की तरह फुकरे ने उछलते हुए कहा, तू जानता है मेरा बाप कौन है?

मुन्ना भाई एक सेकंड के लिए सिहर गया, अबे, अपुन से आधार कार्ड तो बनवाया नहीं था तूने अपने बाप का! अपुन को क्या मालूम तेरा बाप कौन है? सर्किट ने तुरंत बीच-बचाव किया, भाई, ये दिल्ली वाला है, इसको हर बात पे बाप की भौंस जमाने की आदत है।

खैर, फुकरे ने दोनों को दिल्ली का असली टूर कराने की ठानी। पहला सवाल उठा, रहना किधर, खर्चा-पानी कैसे चलेगा? पूरी ठसक से सर्किट बोला, अगली ट्रेन से रिंकी और उनकी फ्रेंड्स आ रही हैं। लॉटरी का इंतजाम हो रहा है। औरत होने में कितना मजा है भाई! सरकार से 2500 रुपये फ्री मिलने वाले हैं। मुन्ना भाई बोला, मगर मर्द होने में उससे भी डबल मजा है सर्किट, पैसे मिलेंगे रिंकी को और उस पे ऐश करेगा अपुन।

फुकरा चकरा गया, अबे! रिंकी भाभी तुझे अपने पैसे क्यों देंगी? आज की नारी स्वतंत्र है, आत्मनिर्भर है! सर्किट ने हंसते हुए पटका मारा, अबे! आज की नारी है तो क्या हुआ? हम तो आज भी कल वाले मर्द हैं बोले तो पुरुष ही नहीं, महापुरुष हैं!

सर्किट ने आगे बघारा, देख भाई, लड़की पढ़ी-लिखी हो या नहीं, उनको उल्लू बनाना सबसे आसान काम है मर्दों के लिए। उसे बोलेंगे कि 'तू बहुत स्ट्रॉन्ग है, सब कर सकती है।' फिर देख, घर भी वही संभालेगी, नौकरी भी करेगी, स्कीम से मिलने वाले पैसे भी हमें देगी और चाय-नाश्ता से लेकर रात का डिनर भी वही बनाएगी। हम उसको ब्रेव, स्ट्रॉन्ग और सुपरवुमन बोल के चने के झाड़ पे चढ़ा के रखेंगे, उसको पता भी नहीं चलेगा कि वो मजबूत नहीं मजबूर है। मुन्ना भाई बोला, एकदम रापचिक प्लान बनाया है ये मर्दों ने। लेडीज लोग खुद को जो हिम्मत और मजबूत बोल के खुश होती हैं, उनको मालूम भी नहीं चलता कि औरत का हौसला पहले मर्द ही गिराते हैं, फिर वो उठती है तो सोचती है कि वो मजबूत है। ये सीक्रेट तो बस मर्द जात को ही मालूम है कि वो मजबूत नहीं मजबूर है।

फुकरे ने फिर खुजलाया, लेकिन भाई, ये सब सोच के करियो। आजकल लड़कियां भी चालाक हो गई हैं! उनको भड़काने वाली फेमिनिस्ट भी गली-गली दिखने लगी हैं। मुन्ना भाई ने मुस्कुराते हुए कंधे पर हाथ रखा, अरे फुकरे, चिंता न कर! अपुन लोग भेड़िए अंदर से हैं, बाहर से खाल भेड़ की पहन रखी है। टिक जाएंगे। इस बीच, रिंकी की ट्रेन स्टेशन पर पहुंच चुकी थी और दिल्ली की हवा में एक नया घोटाला बनने की महक आने लगी थी!

AI Image

दिल तो पागल है

इस बीच, रिंकी की ट्रेन स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। जैसे ही रिंकी और उसकी फ्रेंड्स ट्रेन से उतरीं, सर्किट ने दौड़कर उनका सामान उठा लिया और एकदम हीरो की तरह मुस्कराते हुए बोला, रिंकी भाभी, अपुन नारी सशक्तिकरण में पूरा विश्वास रखता है। बोले तो लेडीज लोग को हमेशा कंफर्टेबल महसूस कराना चाहिए! रिंकी खुश, वाह सर्किट, तुम तो बड़े जेंटलमैन निकले! मुन्ना भाई ने भी सिर हिलाया, बिलकुल! असली मर्द वही जो औरत की इज्जत करे! फिर साइड में जाकर सर्किट के कान में फुसफुसाया, अपुन की पौ बारह होने वाली है, बस थोड़ा मीठा-मीठा बोल, जल्दी ही भाभी लोगों से फ्री में शॉपिंग करवा लेंगे! तभी रिंकी की फ्रेंड ने पूछा, तुम लोग दिल्ली में क्या काम करने वाले हो? सर्किट ने झट से जवाब दिया, बिजनेस! बहुत बड़ा बिजनेस! देखो, तुम लेडीज लोग बाहर काम करती हो, मेहनत करती हो, पैसा कमाती हो, लेकिन फिर थक जाती हो ना? तो अपुन लोग तुम्हारे मेंटल हेल्थ का ध्यान रखेंगे प्यार, केयर, सपोर्ट से एकदम फ्री में! और तुम्हारे फाइनेंस भी संभाल लेंगे बोले तो पैसे वैसे का हिसाब किताब तुमको कहाँ समझ आयेगा। इसलिए तुम्हारा पैसा कब, किधर इन्वेस्ट करना है, ये तुम को कहां पता। जमाना खराब है, तुमको भी ठग लेगा! तुम कमाई करो बाकी हम संभालेंगे। रिंकी और उसकी सहेलियों ने हंसकर कहा, कितना केयरिंग है, लेकिन उन्हें क्या पता कि ये वही पुरानी चाल थी, औरतों को मीठे बोलों से खुश करके उनके ही पैसों पर ऐश करने वाली! सर्किट ने धीरे से मुन्ना भाई से कहा, भाई, देखा तुमने, लड़की कितनी ही मॉडर्न हो, प्यार में पड़ते ही सब छोड़कर हमारे भरोसे हो जाती हैं।

मन में जैसा होगा भाव, वही बन जाएगा हमारा स्वभाव

बी.के. शर्मा

सभी मनुष्यों का स्वभाव एक समान नहीं होता। अंदर के भाव के अनुसार स्वभाव भी बदलता है। अपने भाव से ही कोई शांत होता है, तो कोई क्रोधी। कोई संतोषी बन जाता है और कोई लोभी। इस तरह गुण या अवगुणों के कारण मनुष्य की पहचान अच्छे या बुरे स्वभाव वाले इंसान की बन जाती है। फिर वह वैसे ही लोगों का संग करने लग जाता है। अपने-अपने स्वभाव के अनुसार ही प्रत्येक मनुष्य इस संसार में आचरण/व्यवहार करता है।

THE SPEAKING TREE
और पढ़ने के लिए देखें
hindi.speakingtree.in

संसार का एक नाम भवसागर भी है। मनुष्य को अपनी भावना के अनुसार ही भव या संसार की प्राप्ति होती रहती है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि के सिद्धांत के अनुसार हमारे भाव ही हमारे भावी जीवन के पथ प्रदर्शक बन जाते हैं। रामचरित मानस में भी आता है, 'जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी।' यानी, श्रीराम को जिस व्यक्ति ने जिस भावना से देखा उसे वह वैसे ही दिखाई देने लगे। मनुष्य जिस विषय, वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति को अपने सुख का कारण मानता है, उससे उसे राग हो जाता है। जिसको वह दुख का कारण मानता है, उससे द्वेष करने लगता है। फिर उसके अंतःकरण में राग-द्वेष के भाव उत्पन्न होने लगते हैं।

राग-द्वेष का स्थूल रूप ही काम और क्रोध है। ऐसी स्थिति में मनुष्य समाज और शास्त्र, मर्यादा, सामर्थ्य, हानि, हिंसा और परिणाम आदि का विचार नहीं करता। मन में आने वाली कामनाओं की पूर्ति करना ही स्वभाव बन जाता है उसका। और जब इसमें बाधा आती है, तो वह क्रोध करने लगता है। दूसरों का हित-अहित, सुख-दुख, लाभ-हानि आदि के विषय में विचार न करके स्वयं तक ही सीमित होकर अपने ही प्राण-पोषण में लगा रहता है। प्राणों का नाम असु है। इसलिए जो मनुष्य केवल अपने ही प्राणों का भरण-पोषण-रक्षण करना चाहते हैं, जिन्हें दूसरों के कष्टों से फर्क नहीं पड़ता, उनको आसुरी स्वभाव कहते हैं। मनुष्य तब तक ही मनुष्य है, जब तक उसका अंतःकरण कर्तव्य-अकर्तव्य के विषय में विवेकपूर्वक निर्णय लेने में समर्थ है।

जिन मनुष्यों के स्वभाव और आचरण में किसी प्रकार भी दूसरों को कष्ट न देना, प्रिय वाणी से दूसरों को सुख देना होता है, वे क्रोध नहीं करते और न ही पीठ पीछे किसी की निंदा करते हैं। ऐसे मनुष्यों को दैवीय स्वभाव वाला कहा जाता है। दूसरे मनुष्यों के लिए वह प्रेरणा देने वाले होते हैं। मनुष्य बाहरी संसार, कामनाओं की पूर्ति, विषय भोग और संग्रह में इतना आसक्त हो गया है कि अपने दोष, स्वभाव और आचरण के बारे में विचार व आत्मचिंतन करने का समय ही नहीं निकाल पाता। खुद को न बदल कर दूसरों को बदलने और ठीक करने में लग जाता है। मनुष्य अपने स्वभाव को बदलने में पूरी तरह स्वतंत्र है। इसके लिए सिर्फ दृढ़ इच्छाशक्ति की जरूरत है। अच्छे मनुष्यों का संग, अच्छी पुस्तकें पढ़ना, स्वार्थ और अभिमान का त्याग, दूसरों के हित की दृष्टि रखना मुश्किल नहीं, आसान है। बस स्वभाव क्रिया और प्रतिक्रिया की जगह संवेदनशीलता को आने दें। आखिरकार ये बातें हमारे ही फायदे में हैं।

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

गुजरात में सक्रियता

10 मार्च का संपादकीय 'क्या चाहते हैं राहुल' पढ़ा। कांग्रेस पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के गढ़ गुजरात में काफी सक्रिय दिख रही हैं। इसके साथ ही इंडिया ब्लॉक में उसकी अहमियत भी बढ़ेगी। यही कारण है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुजरात की न केवल यात्रा कर रहे हैं बल्कि वहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए महत्वपूर्ण बयान भी दे रहे हैं। उन्होंने कई कांग्रेस नेताओं पर BJP से मिलीभगत का भी आरोप लगाया। दरअसल उनका बयान पार्टी में कार्यकर्ताओं को साफ संदेश देता है कि कांग्रेस में रहना है तो उसकी विचारधारा को दिलो-जान से स्वीकार करना होगा। बहरहाल, गुजरात में दो साल बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। पार्टी का अभी से ही राज्य में सक्रिय हो जाना एक अच्छा संकेत है।

पैथर तोमर, किशन गंज

ताकि शांति कायम रहे

पूरा देश जहां क्रिकेट में चैंपियंस ट्रोफी जीतने पर होली से पहले दिवाली सा जश्न मना रहा था, वहीं इंदौर जिले के एक छोटे से शहर महू छावनी में जश्न के दौरान निकल रहे जुलूस पर कुछ उपद्रवी तत्वों ने पत्थर बरसा दिए। कुछ मोहल्ले, गलियों और बाजारों में माहौल बिगड़ गया। कंटोनमेंट से जुड़ा शहर हमेशा शांत रहा है। महू में जन्मे बाबा साहब आंबेडकर ने देश को पुख्ता संविधान दिया। हांकी में शंकर-लक्ष्मण के बेहतरीन गोल ने देश को सिरमौर बनाया। ऐसी प्रतिभाशाली और सकून भरी नगरी में ऐसी अशांति क्यों? विचार करने की जरूरत है।

शकुंतला नेनावा, इंमेल से

nbtedit@timesofindia.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

म्यांमार में चुनाव के संकेत, भारत के लिए राहत की बात- एक खबर - लोकतंत्र की बयार तो अपने साथ सुकून लाती ही है।

सुरभि रावत

आर.एन.आई. नं. 6320/62 वार्षिकियां शुल्कः (विदेश अलग से के लिए संपर्क या अधिक पूछताछ पर) सीबीडीए: स्वतंत्रविभाग बिल्डिंग, सीबीडीए सचिवालय बिल्डिंग के पास दक्षिण सेक्टर ग्रा. 7 नवीनमुंबई नवी मुंबई, महाराष्ट्र 410210 में प्रकाशित तथा **राकेश प्रवीण मिश्र, मालिक तथा प्रकाशक** द्वारा **नवभारत टाइम्स** प्रकाशित कर रहे हैं। पत्र व्यवहार का पता: टाइम्स हाउस, 7, एजेंसी सेक्टर 11, इंस्टीट्यूशनल एरिया सेक्टर-62, नोएडा, उत्तरप्रदेश के मुद्रित। फोन : 2202-2222 फैक्स: 2202-2221, संपादक कार्यालय : टाइम्स बिल्डिंग, प्लॉट नं. 4, सेक्टर 16 ए, फिल्म सिटी, नोएडा - 201301 फोन: 0120-2511111 फैक्स: 0120-2511001 संपादक : विनोद नांबियार ; टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के प्रबंधित कराया कमाकोटी के पत्र एवं संचार के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत प्रकाशित।

राष्ट्रीय संस्करण www.jagran.com
दैनिक जागरण
मंगलवार 11 मार्च, 2025

70 हजार अस्पताल हैं देशभर में, वर्ष 2019 के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार, जिनमें से लगभग 63 प्रतिशत निजी क्षेत्र में हैं, जबकि 37 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र में हैं।

आजकल

स्वास्थ्य व्यवस्था में हो समग्र सुधार

हमारे लिए यह एक बड़ी चिंता का विषय है कि आजादी के साढ़े सात दशक बीतने के बावजूद देश में स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है। हमारी स्वास्थ्य जरूरतों और सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं के बीच में बड़ा अंतर है। उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में कहा है कि राज्य सरकारें किफायती चिकित्सा और बुनियादी ढांचा देने में नाकाम रही हैं। इससे निजी अस्पतालों को बढ़ावा मिल रहा है। इसे रोकने के लिए केंद्र सरकार को दिशानिर्देश बनाना चाहिए। लिहाजा इससे व्यवस्था में सुधार की उम्मीद जगी है

प्रतीकात्मक

लालजी जायसवाल
लोक नीति विश्लेषक

शिक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार एक नागरिक का मूल अधिकार है। हमारे देश में भले ही स्वास्थ्य व्यवस्था का ढांचा तुलनात्मक रूप से निरंतर मजबूत हो रहा है, परंतु सभी तक इसकी पहुंच अभी भी नहीं हो पाई है। राज्य सरकारें इस दिशा में कामयाब नहीं हो पाई हैं, लिहाजा निजी स्वास्थ्य सेवाओं को प्रोत्साहन मिल रहा है। इससे यह महंगी होती जा रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों और उनके परिवारों को अस्पताल की फार्मेसी से महंगी दवाएं और मेडिकल उपकरण खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है। इसलिए ऐसे अस्पतालों पर नकेल कसी जाए। इसे रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को आदेश दिया जाए।

शीर्ष न्यायालय ने राज्य सरकारों से कहा कि वे निजी अस्पतालों को नियंत्रित करें, जो मरीजों को अस्पताल की दुकान से दवाएं खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। खासकर, वे दवाइयां जो किसी और जगह सस्ते में मिल जाती हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार को गाइडलाइन बनाने को भी कहा, ताकि निजी अस्पताल आम लोगों का शोषण न कर सकें। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सभी राज्यों को नोटिस भेजा था, जिनमें से ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों ने जवाब भी दाखिल किए थे। दवाइयों की कीमतों के मुद्दे पर राज्यों ने कहा कि वे केंद्र सरकार पर निर्भर हैं। केंद्र सरकार ही दवाओं की कीमत तय करती है। इसलिए सरकार को चाहिए कि कुछ ऐसी व्यवस्था लेकर आए जिससे निजी अस्पताल आमजन का शोषण न कर सकें।

निगरानी समितियां : निजी अस्पताल को मनमानी पर लगाम लगाने के लिए सरकार को निजी अस्पताल में इलाज की दरें तय करनी चाहिए। इसकी निगरानी के लिए समिति गठित करनी चाहिए, जो अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई करे। यदि अस्पताल तय शुल्क से अधिक वसूले तो मरीज इसकी शिकायत करे। यदि सरकार गंभीर होगी तो अस्पताल भी नियमों का पालन जरूर करेंगे। निजी अस्पतालों का सदैव एक ध्येय वाक्य 'आपका में अवसर' रहा है जिसका वो हर हाल में पालन करते हैं। निजी अस्पतालों के लिए विभिन्न स्तर पर निगरानी समितियां बना कर भी इनकी मनमानी पर रोक लगाई जा सकती है।

सार्वजनिक हो सेवा शुल्क : प्रत्येक अस्पताल को अपने सेवा शुल्क संबंधी जानकारी को सार्वजनिक करना चाहिए। सरकार को इनके लिए एक प्रारूप भी तय करना चाहिए। निजी अस्पताल टेस्ट परीक्षण, भोजन, बेड दवाइयों सुविधाओं के नाम पर बड़ी रकम वसूलते हैं। निजी चिकित्सालय मरीज को जरूरत से ज्यादा दवाएं देते हैं और इन दवाओं की कीमत भी ज्यादा होती है। निजी अस्पतालों की मनमानी पर लगाम कसने के लिए प्रशासन को निगरानी तंत्र मजबूत बनाना चाहिए। साथ ही, गलती करने वाले को कानूनी प्रविधानों के अनुरूप सजा दिलाने की त्वरित कार्रवाई निष्पक्ष रूप से की जानी चाहिए।

वैसे यह बात भी सही है कि मनमानी करने वाले सभी नहीं हैं, किंतु जो भी निजी अस्पताल अनियमितता और मुनाफाखोरी में लिप्त हैं, उनके विरुद्ध समय पर कार्रवाई नहीं होने से अन्य अस्पतालों का भी हौसला बढ़ जाता है। अतः केवल कठोर कार्रवाई की चेतावनियां देते रहने के बजाय प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और वह दिखाई भी देनी चाहिए। तभी वास्तविक रूप में आमजन को चिकित्सकीय शोषण से बचाया जा सकेगा।

व्यावहारिक निर्णय : सरकार को एक विधेयक यह भी लाने के बारे में विचार करना चाहिए कि किसे भी निजी अस्पताल में यदि मरीज की मृत्यु हो जाती है तो उसका सरा मेडिकल बिल माफ कर दिया जाए। इसका एक लाभ यह होगा कि इससे निजी अस्पताल इलाज में लापरवाही नहीं बरतेंगे। इसके बहुत कई फायदे हैं। एक तो डाक्टर अच्छे से काम करेंगे और किसी कारणवश मृत्यु होती है तो प्राइवेट हास्पिटल वाले उसे वेंटिलेटर पर रख कर बिल नहीं बढ़ाएंगे। हालांकि ऐसे मामलों में सरकार को और से निजी अस्पतालों को कुछ सहयोग राशि भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि उन पर आर्थिक बोझ न बढ़े।

देखा गया है कि निजी अस्पताल रोगी के स्वास्थ्य देखभाल, उपचार लागत के बारे में जवाबदेही से बचते हैं। कई बार प्रसव जैसे मामलों को निजी अस्पतालों की ओर भेज दिया जाता है। रोगी के उपचार में घोर लापरवाही और बिल की वसूली में अराजकता जैसे तथ्य अस्पतालों की मनमानी प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। हालांकि ऐसा सभी अस्पतालों या चिकित्सकों पर आरोप नहीं लगाया जा सकता, परंतु अमूमन समाज में जो चित्र देखने को मिलता है, वह लगभग इससे मिलता-जुलता ही है। वैसे इस तरह का निर्णय आसान नहीं है, और इससे कई प्रकार की व्यावहारिक समस्याएं सामने आ सकती हैं। वस्तुतः किसे गंभीर बीमारी से ग्रस्त बुजुर्ग के निधन के मामले में इसे लागू करने में निजी अस्पतालों के सामने एक नया संकट खड़ा हो सकता है। अगर मृत्यु पर बिल माफ जैसे नियम लाया जाता है तो होगा यह कि निजी अस्पताल गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को भर्ती करने से बचेंगे। ऐसे में आम जनता के लिए एक नई समस्या पैदा हो सकती है। लिहाजा सरकार को चाहिए कि पूरा बिल माफ करने की जगह कुछ प्रतिशत की छूट का प्रविधान लागू करना चाहिए, ताकि मृत्यु के बाद उस परिवार को जनहानि के साथ धनहानि न हो सके। फिर भी, इस समस्या का कोई व्यावहारिक समाधान तलाशा जाना चाहिए।

सरकारी अस्पतालों की दशा भी हो दुरुस्त

भारत में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के अपेक्षाकृत स्तरीय न होने के कारण लोग निजी क्षेत्रों की ओर रुख करते हैं। निजी अस्पतालों के महंगे स्वास्थ्य खर्चों का भुगतान करने के कारण प्रतिवर्ष लगभग छह करोड़ लोग यहां गरीबी के चंगुल में फंस रहे हैं। इस मामले में थाइलैंड, क्यूबा और कोस्टारिका ने अलग-अलग तरीके अपनाकर अपने देश में विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा दी हैं। थाइलैंड ने तो इसे संवैधानिक अधिकार बना दिया है और स्वास्थ्य अधिनियम के द्वारा इस क्षेत्र में ढांचागत सुधार किए हैं। हम भी अगर अपने देश की जनता के स्वास्थ्य को उत्तम स्तर तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें पर्याप्त संसाधन जुटाने होंगे। सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति अपने दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदलना होगा। हमारे देश के लगभग 75 प्रतिशत अस्पताल निजी क्षेत्र में हैं। केवल 25 प्रतिशत अस्पताल सरकार द्वारा संचालित किए जाते हैं, जिनमें भी अधिकतर अस्पतालों में डाक्टर, नर्स एवं गुणवत्ता वाले चिकित्सीय संसाधनों का अभाव रहता है। ऐसे में सुविधा एवं संसाधनों से पूर्ण निजी अस्पतालों की मनमानी स्वाभाविक है। इनकी मनमानी भरे रवैये पर नकेल कसने के लिए सरकार को निजी अस्पतालों में हो रही सारी जांचों, उपलब्ध दवाइयों, सर्जरी, परामर्श तथा हो रहे हर प्रकार के इलाज के लिए दरें तय कर देनी चाहिए। निजी अस्पतालों में उपलब्ध आइसीयू बेड, वेंटिलेटर इत्यादि सुविधाओं की यथास्थिति आनलाइन होनी चाहिए। इन नियमों का उल्लंघन करने पर निजी अस्पताल पर कार्रवाई होनी चाहिए।

इसके साथ-साथ सरकार को सरकारी अस्पतालों की संख्या, वहां पर डाक्टरों, नर्सों एवं आधुनिक संसाधनों में वृद्धि पर ध्यान देना चाहिए। कहा जा सकता है कि निजी अस्पतालों में मनमानी होने के कारण सरकारी अस्पतालों में अव्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि देश में सरकारी अस्पताल की कमी है। हमारे देश में सरकारी अस्पतालों की कमी नहीं, बल्कि गुणवत्तायुक्त सुविधा की कमी है। अक्सर देखा जाता है कि सरकारी अस्पतालों में मरीज इधर-उधर भटकते रहते हैं। फिर मजबूरी में मरीजों को निजी अस्पताल की ओर जाना पड़ता है। अगर सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था ठीक कर दी जाए तो हालात बदल सकते हैं। दूसरी मुख्य बात, सरकार को निजी अस्पतालों के शुल्क तय करने चाहिए।

उल्लेखनीय है कि 1972 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता अमेरिका के कैनीथ एरो ने चेताया तो थी कि स्वास्थ्य सेवा को बाजार के हवाले कर देना आम नागरिक के लिए घातक होगा। ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण हो गया है जिसका आनंद कुछ ब्रांडेड अस्पतालों द्वारा उठाया जा रहा है।

इलाज पर होने वाले कुल खर्चे में सरकारी खजाने का हिस्सा महज 25 प्रतिशत है, बाकी का बोझ लोगों की जेब पर पड़ता है। परिणामस्वरूप सलाना तौर पर दस लाख भारतीय साधनों के अभाव में उपचार नहीं करा पाते और उनकी मौत हो जाती है। मेडिकल कांसिल आफ इंडिया द्वारा डाक्टरों के लिए कोड आफ एथिक्स तय किया गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह एक मृत पत्र बनकर रह गया है। कहा तो यह भी जाता है कि कोई डाक्टर जितना अधिक डायग्नोस्टिक टेस्ट की सिफारिश करता है या एक रोगी को आइसीयू में अधिक समय तक रखता है, उतना ही उसके पैसे बनते हैं।

फिलहाल देश के निजी अस्पतालों को ऐसी मनमानी से बचना चाहिए। ऐसा तभी होगा जब सरकार कठोर रूप से ऐसे सभी अस्पतालों पर कार्रवाई करेगी। हमें इस बात को समझना होगा कि किसी भी बीमारी का निराकरण समग्र रूप से किया जा सकता है। भारत को स्वस्थ बनाने का उत्तरदायित्व व्यक्तिगत एवं निजी क्षेत्र के प्रयासों से सरकार को सहयोग देन है। हमारे देश की इस जटिल समस्या की सुलझाने के लिए कोई जादुई मंत्र तो नहीं है, जो क्षणभर में कायापलट कर दे। परंतु ऐसा भी नहीं है कि हम अपेक्षित उपायों को तत्परता से अपनाकर इस समस्या को सुलझा न सकें।

(लालजी जायसवाल)

खरी-खरी

महत्वपूर्ण सवाल

क्षमा जैन

कांग्रेस प्रवक्ता ने रोहित शर्मा के बढ़ते वजन पर टिप्पणी कर दी है। देश के कप्तान को न चाहते हुए भी कुछ दिन और मोटा रहना पड़ेगा। हमें तो इस प्रकरण में विदेशी हाथ नजर आता है। यह हाथ अमेरिका को छोड़कर किसी भी देश का हो सकता है। अमेरिका का दूसरे देशों में हाथ पहुंचाने वाला विभाग बंद किया जा चुका है। यह यूएस एड कहलाता था। प्रवक्ता का बयान आने के बाद से राजनीतिक खेमों में खलबली मची हुई है।

इधर भाजपा स्वाभाविक रूप से यह सिद्ध करने में जुट गई है कि कप्तान साहब एकदम फिट हैं। सुर्योदय सर अगले ट्विंट में गुप्त और मौर्य कालीन चेद्दाओं के चरित्र चित्रण करते हुए बताने वाले हैं कि डेढ़-दो सौ किलो के वे शूरवीर जब दुश्मनों पर आक्रमण करते तो कैसे ग्राहिमा मच जाय करता था। अर्थात युद्ध और क्रिकेट में वजन ज्यादा होने से पराक्रम में बढ़ोतरी होती है। अर्थात विपक्षियों को देश के समृद्ध इतिहास का ज्ञान नहीं है।

प्रणमूल कांग्रेस के एक सांसद द्वारा भी रोहित के मोटापे से सहमति व्यक्त की गई है। इससे यह तो सिद्ध नहीं होता रोहित वाकई मोटे हुए हैं अथवा नहीं, परंतु यह अवश्य सुनिश्चित हो जाता है कि आगामी विधानसभा चुनावों में बंगाल में आइएसडीआइए संगठित दिखने वाला है। अखिलेश सर ने अभी तक रोहित के मोटे होने की पुष्टि नहीं की है। हालांकि इस कारण विपक्षी गठबंधन के प्रति उनकी निष्ठा पर संदेह नहीं किया जा सकता।

तमिलनाडु वाले स्टालिन सर का कहना है कि वे इस मामले में कांग्रेस का समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि बयान हिंदी में दिया गया है। शशि थरूर भी कुछ कहना चाह रहे थे। फिलहाल वे आलाकमान से पूछ रहे हैं कि कांग्रेस में मोदी भूमिका पता लगे तो उस हिसाब से बोलूं। वैसे उन्हें अपनी वाली अंग्रेजी में बात कह देनी चाहिए। किसको समझ आनी है। राजनीतिक दलों में बयान के पक्ष या विरोध में आने की ब्रैकेंग चल ही रही थी कि कांग्रेस ने स्वयं ही प्रवक्ता के बयान से किनारा कर लिया है। नागरिकों पर यह संकट की घड़ी है। इस महत्वपूर्ण सवाल पर उन्हें अब अपना निर्णय स्वयं लेना होगा कि रोहित मोटे हैं या नहीं।

पोस्ट

औरंगजेब की महान दिखाने की मूर्खता में आपने भी कुछ लोगों को कहते सुना होगा कि मुगल और खासकर औरंगजेब ने भारत की अर्थव्यवस्था को धमकाया, अन्यथा भारत कुछ था ही नहीं। सच्चाई यह है कि मुगलों के समय भारत की अर्थव्यवस्था नीचे चली गई थी।

सुशांत सिन्हा@SushantBSinha

पैथियस ट्राफी में भारत की जीत के बाद इंदौर में बड़ा बवाल हुआ। जीत के उपलक्ष में जुलूस निकाल रहे लोगों पर हमला। पत्थरबाजी, आगजनी व तोड़फोड़। आखिर भारत की जीत से किसे समस्या है?

अभय प्रताप सिंह@IAbhay_Pratap

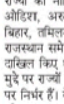

पैथियस ट्राफी जीतकर भारत ने क्रिकेट का अश्वमेध यज्ञ पूरा किया। आलोचनाओं की परवाह किए बिना रोहित शर्मा ने अपनी नेतृत्व क्षमता से भारत को ताज पहनाया। जब रवींद्र जडेजा आठवें क्रम पर उतरते हो तो इससे हमारी बैटिंग की गहराई का पता चलता है। जसप्रीत बुमराह के बिना भी एक बड़ा टूर्नामेंट जीतकर भारत ने अपनी निरंतर बढ़ती ताकत का भी अहसास कराया है।

सुशील दोशी@RealSushiDoshi

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या अमेरिका के टैरिफ वार के बीच चीन के मित्रता प्रस्ताव पर भारत को भरोसा करना चाहिए?

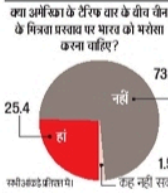

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या रोहित शर्मा का वनडे मुकाबलों से रिटायर न होने का फैसला सही है?

परिणाम जागरण डाटस्टेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

ट्राफी जीती इंडिया दुबई के मैदान,
हाथ मल रहा होस्ट बन अकड़ी पाकिस्तान।
अकड़ी पाकिस्तान था रुसवा किया कराया,
बाहर बैठे आप हाथ कुछ भी न आया।
दर्शक बन कर पाक रह गया पीता काफी,
लाई अपनी टीम खेलकर बढ़िया ट्राफी।

- ओमप्रकाश तिवारी

उत्तम नाथ पाठक
संपादकीय प्रभारी, उमरशेडपुर

ओडिशा डायरी

नए रंग में दिखने लगा ओडिशा

ओडिशा में मोहन चरण माझी की सरकार तीव्र गति से विकास होने के दावे कर रही है। चाहे प्रवासी दिवस के अवसर पर प्रवासी भारतीय सम्मेलन की बात हो या फिर उत्कर्ष ओडिशा का आयोजन हो। इन आयोजनों में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय आए और निवेश के कई समझौते हुए। निश्चित ही इससे ओडिशा विकास की पटरी पर तीव्र गति से दौड़ेगा और बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसका पूरा श्रेय भाजपा सरकार को जाएगा। विकास के साथ तेज गति से कदमताल कर रही मांझी सरकार इसे चिर स्मरणीय स्थापित करने के लिए सार्वजनिक परिवहन के साधनों (बस और बस स्टैंड) समेत सभी सरकारी भवनों-कार्यालयों को गेरुआ रंग में रंग रही है।

ताजा मामला सरकारी स्कूलों के रंग बदले जाने के निर्णय का है। ओडिशा के स्कूल शिक्षा कार्यक्रम (ओएसईपीए) प्राधिकरण की तरफ से राज्य के सभी जिलों को एक आधिकारिक पत्र जारी किया गया है। जिसमें स्पष्ट आदेश दिया गया है कि सरकारी स्कूल की इमारतों के रंग को लेकर जारी अब तक के सभी पुराने निर्देश रद किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री विद्यालय सहित सभी सरकारी स्कूलों में निर्माण, मरम्मत और नवीकरण कार्य के दौरान अनुमोदित रंग कोड नारंगी अपनाने के लिए कहा गया है। स्कूल की दीवारों को नारंगी रंग और किनारों की गहरे नारंगी रंग में रंगा जाना है। पिछली बीजद की सरकार ने अपने पार्टी के झंडे के रंग के अनुरूप हरे और सफेद रंग में स्कूलों को रंगा था।

वहीं मोहन चरण मांझी सरकार ने मुख्यमंत्री छात्र परिछन योजना के तहत माध्यमिक स्कूलों के छात्रों को पोशाक के रंग और डिजाइन में भी बदलाव कर दिया है। पहले पोशाक का रंग सफेद और हरा था, जिसे बदलकर हल्का भूरा और मैरून कर दिया गया है।

ओडिशा में बदला जा रहा है सरकारी बसों का रंग। फाइल

सरकार के साथ रंग में बदलाव : ओडिशा में लगभग ढाई दशक तक रही नवीन पटनायक के नेतृत्व में बीजद सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान लगभग सभी सरकारी भवनों को हरे रंग से रंग दिया था। यहां तक कि कटक स्थित एससीबी मेडिकल कालेज का रंग भी हरा हो गया था। अब मांझी सरकार की तरफ से भवन निर्माण विभाग ने सरकारी भवनों के लिए एक समान रंग कोड बनाया है। इसमें सरकारी भवनों की बाहरी दीवारों की मरम्मत और जीर्णोद्धार से जुड़े कार्यों के दौरान नारंगी रंग का उपयोग किए जाने की बात कही गई है। अभी कुछ समय पहले सार्वजनिक परिवहन के प्रमुख साधन बसों के नाम और रंग को भी बदल दिया गया है। नवीन पटनायक के समय चलाई गई लक्ष्मी बस सेवा को हरे से बदलकर गेरुआ रंग में कर दिया गया। वहां लक्ष्मी बस सेवा की जगह इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री बस सेवा कर दिया गया है।

बीजद के विधायकों का आरोप है कि भाजपा की सरकार के पास कोई नया विजन नहीं है, इसलिए वह केवल पिछले सरकार के काम और नाम के निशान को मिटाने में जुटी है। लेकिन वह सफल नहीं होगी, क्योंकि नवीन पटनायक ने जितने काम कर दिए हैं, उतना भाजपा के लिए करना संभव नहीं है। बीजद सरकार की सबसे बेहतरीन योजनाओं में से एक मानी जाने वाली बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना (बीएसकेवाइ) को भाजपा ने गोपालबंधु जन आरोग्य योजना कर दिया। इसे केंद्र सरकार की पीएम जन आरोग्य योजना और बीएसकेवाइ को मिलाकर बनाया गया है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री एवं विपक्ष के नेता नवीन पटनायक ने बीते दिनों इस संदर्भ में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था कि उनकी 40 योजनाओं के नाम बदल दिए गए हैं। इनमें सबसे प्रमुख बीएसकेवाइ को गोपालबंधु जन आरोग्य योजना नाम दे दिया गया। वहीं कालिया योजना को सीएम किसान योजना बना दिया, अमा ओडिशा नवीन ओडिशा को विकसित गांव विकसित ओडिशा कर दिया गया। मिलेट मिशन को श्री अन्न अभियान। बीजू सेतु योजना से सेतु बंधना योजना, बीजू पक्का घर योजना को ओत्थेदय गृह योजना कर दिया गया। मेक इन ओडिशा को उत्कर्ष उत्कल कर दिया गया। ऐसे कई उदाहरण हैं। इनके अलावा सड़क पर लगे दिशा-सूचक बोर्ड को भी भगवा रंग में रंग दिया गया है।

खैर यह प्रचलन तो अधिकांश राज्यों में है कि सरकार बदलने के बाद सरकारी भवनों का रंग व योजनाओं का नाम बदला जाता है। इसलिए इसे नया शगल कहना सही नहीं होगा। वैसे इन बदलावों के बीच सीएम मोहन चरण मांझी प्रदेश में विकास की कितनी बयार बहा सकते हैं या लोगों के जीवन में कितना बदलाव ला सकते हैं, यह तो भविष्य में पता चलेगा, क्योंकि उन्हें अपनी पार्टी के अंदर से ही फिलहाल कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

मंथन

हिंदी का राजनीतिक विरोध

तमिलनाडु में पिछले कुछ समय से एक बार फिर हिंदी विरोध के राजनीतिक स्वर मुखर हैं। अगले साल यहां विधानसभा चुनाव है, लिहाजा डीएमके ने अभी से भाजपा के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है

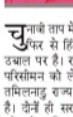

विनय ठाकुर
वरिष्ठ पत्रकार

चुनावी ताप में तमिलनाडु में एक बार फिर से हिंदी को लेकर राजनीति उबाल पर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और परिसीमन को लेकर केंद्र सरकार और तमिलनाडु राज्य सरकार आमने-सामने हैं। दोनों ही सरकारें अपने अपने रुख को लोक हितकारी साबित करने के लिए अपने-अपने तर्क, व्याख्या को मजबूती से लोगों के सामने परोसने में लगी हैं। राज्य सरकार इसे केंद्र सरकार द्वारा ब्लैकमेल करार देकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बहाने हिंदी लादने का प्रयास बता रही है तो वहीं केंद्र सरकार इसे राजनीतिक लाभ के लिए संविधान और राष्ट्रीय हित विरोधी कार्य करार दे रही है। अपना पक्ष मजबूत करने के लिए हिंदी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के समर्थन में भाजपा द्वारा स्कूलों बच्चों के हस्ताक्षर हासिल करने का अभियान चला रही है। डीएमके द्वारा इस अभियान को बच्चों पर अत्याचार बताकर गिरफ्तारी की जा रही है। पर असली लड़ाई अलग पहचान की है जो आर्य बनाम द्रविड़ और उत्तर बनाम दक्षिण के इंद्र के सहारे अपना आकार ग्रहण करती रही है।

वस्तुतः यह संघर्ष प्रक्रिया आजादी के पहले से ही 1937 से ही चल रही है। इसे जन्म देने में तत्कालीन मुख्यमंत्री राजगोपालाचारी द्वारा वहां के सामाजिक राजनीतिक यथार्थ की अनदेखी व अपने मुकाबले विरोधियों के राजनीतिक चातुर्य व संगठन क्षमता को कम करके आंकना रहा है। इस संघर्ष के परिणामस्वरूप हिंदी को उत्तर व ब्राह्मणवादी वर्चस्व के साथ जोड़ दिया गया। वर्ष 1937 में हिंदी को स्कूलों में अनिवार्य करने और 15 हजार हिंदी शिक्षकों की नियुक्ति के निर्णय को ब्राह्मणों के वर्चस्व को मजबूत करने के साथ जोड़ने आसान था, क्योंकि उस दौर में वहां प्रशासन और शैक्षणिक जगत पर ब्राह्मणों का अत्यधिक वर्चस्व था और राजगोपालाचारी के ब्राह्मण होने के कारण द्रविड़ राजनीति के लिए ऐसा करना अपेक्षाकृत आसान था।

बहुभाषा परंपरा : तमिलनाडु के कुछ इलाकों में एक साथ चार-पांच भाषाएं बोली जाती हैं। खासकर होसूर, कोयंबटूर जैसे इलाकों में। तंजौर में मराठी की ऐतिहासिक उपस्थिति की वजह से वहां बहुभाषी शैली की परंपरा रही है। तमिलनाडु के कई राजनीतिज्ञ तेलुगु भाषी हैं तो यहां गुजरातियों की भी अच्छी खासी संख्या है। मदुरै कामराज विश्वविद्यालय में हाल के दिनों तक मलयालम भाषा का विभाग था जिसका खर्च केरल द्वारा उठाया जाता था। केरल के राजधानी में प्रशासनिक उच्च पदों पर तमिल ब्राह्मणों का वर्चस्व रहा था और व्यावसायिक कारणों से दक्षिण तमिलनाडु में मलयालम सामान्य तौर पर समझी व बोली जाने वाली भाषा है।

भाषाई विविधता और भाषा की राजनीतिक ताकत की परख करुणानिधि के पास थी और इसीलिए अपने आरंभिक राजनीतिक जीवन के एक महत्वपूर्ण चुनाव में जब वह त्रिची से चुनाव लड़ रहे थे तो वहां तेलुगु भाषी लोगों के व्यापक प्रभाव को देखते हुए उन्होंने चुनाव प्रचार का काम एक तेलुगु भाषी को सौंपा था।

सामाजिक न्याय की राजनीति : तमिलनाडु में बाद के दौर में सामाजिक न्याय की राजनीति का आरंभ हुआ और कई जातियां सही मायने में सत्ता संरचना में हाशिये से निकलकर ऊपरी पायदानों पर आईं। अन्य राज्यों की तरह सशक्तीकरण केवल राजनीतिक नहीं हुआ, बल्कि आर्थिक और शैक्षणिक भी हुआ। ब्राह्मणों का वर्चस्व राजनीतिक क्षेत्र में तो समाप्त हुआ ही, अन्य क्षेत्रों में भी वे हाशिये पर आ गए। जब आर्थिक आधार पर पीड़ित होने का तर्क अपनी प्रासंगिकता खो चुका है, वहां एक अलग पहचान के आधार पर संरक्षक की मजबूत भूमिका वाली राजनीति के लिए विरोध का एक प्रमुख बिंदु हिंदी बन गई। विडंबना यह है कि इस नीति का पूरा फायदा केरल से आने वाले छात्रों को मिलता है जो सरकारी एवं शैक्षणिक प्रतिष्ठानों में हिंदी एवं राजभाषा से जुड़े सभी निर्युक्तियों में लाभकारी स्थिति में रहते हैं। जनसंख्या दर में कमी आने के असर आर्थिक स्तर पर साफ दिखने लगा है कि यहां के श्रम बाजार में तमिल श्रमिकों की उपस्थिति घटने लगी है। यहां संगठित और असंगठित दोनों ही क्षेत्रों में गैर तमिल श्रमिकों की उपस्थिति देखने को मिल रही है।

भाजपा विरोध का बड़ा केंद्र : तमिलनाडु भाजपा विरोध का सबसे बड़ा केंद्र है, जहां भाजपा अपने प्रसर के लिए कठिन संघर्ष में जुझ रही है। अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए परिसीमन को लेकर तमिलनाडु एक सख्त मोर्चा बनाने के लिए अन्य दक्षिणी राज्यों के साथ संवाद स्थापित कर रहा है। अन्य दक्षिणी राज्यों की तुलना में तमिलनाडु की राजनीति का राष्ट्रीय राजनीति के साथ आरंभ से ही एक अलग प्रकार का रिश्ता रहा है। राष्ट्रीय राजनीति में अपने मजबूत हस्तक्षेप के लिए यहां के राजनीतिक दल केंद्र में स्थित सत्ताधारी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन बनाते रहे हैं, अनेक बार किंगमेकर की भूमिका लेते रहे हैं।

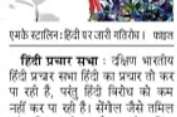
एमके स्टालिन: हिंदी पर जारी सियासी। फाइल

हिंदी प्रचार सभा : दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचार सभा हिंदी का प्रचार तो कर पा रही है, परंतु हिंदी विरोध को कम नहीं कर पा रही है। सेंगैल जैसी तमिल सांस्कृतिक प्रतीक और कार्ड तमिल संगमम के जरिये केंद्र सरकार इसका प्रयास कर रही है, परंतु यह दीर्घकालीन प्रक्रिया है। स्थानीय दलों के सहयोग के बगैर केंद्र की राह कठिन है। डीएमके हिंदी व परिसीमन मामले को इस तरह से सुलगाए रखना चाहती है कि केंद्र को कोई स्थानीय राजनीतिक सहयोगी न मिले। डीएमके का ओबीसी राजनीति के माध्यम से द्रविड़ राजनीति पर एकाधिकार है। अगले साल तमिलनाडु में चुनाव है और डीएमके व भाजपा दोनों ही कोई मौका नहीं चूकना चाहते।

****

दैनिक जागरण
धैर्य का परिणाम सदैव सुखद होता है

शिक्षा नीति पर रार

जैसा अंदेशा था, वैसा ही हुआ। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत हंगामे से हुई। तिन मूर्ति पर हंगामा हुआ, उनमें नई शिक्षा नीति भी है। इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं कि नई शिक्षा नीति को दलगत राजनीतिक हितों से जोड़कर देखा जा रहा है और कुछ राज्यों की ओर से केवल इसलिए उसका विरोध किया जा रहा है, ताकि लोगों की भावनाओं को भड़काकर राजनीतिक लाभ उठाया जा सके। नई शिक्षा नीति का सबसे अधिक विरोध तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की ओर से किया जा रहा है। इस विरोध के पीछे क्षुद्र राजनीति है। स्टालिन को सबसे अधिक आपत्ति नई शिक्षा नीति के त्रिभाषा फार्मूले पर है। यह फार्मूला नया नहीं है। यह 1968 में ही बन गया था। इसमें यह प्रविधान था कि गैर हिंदी भाषी राज्य अपनी स्थानीय भाषा और अंग्रेजी के साथ तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाएंगे। यह उल्लेखनीय है कि 2020 की नई शिक्षा नीति में हिंदी की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। इसके बाद भी स्टालिन यह शोर मचाने में लगे हुए हैं कि त्रिभाषा फार्मूले के जरिये मोदी सरकार तमिलनाडु पर हिंदी थोपना चाहती है। यह निरा झूठ है और इसका उद्देश्य लोगों को बरगलाना है।

तमिलनाडु में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। स्टालिन इन चुनावों में अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए ही नई शिक्षा नीति का विरोध करने में लगे हुए हैं। समस्या यह है कि इसके लिए वह झूठ बोलने से भी नहीं चूक रहे हैं। संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों के फेर में उन्होंने इतना उग्र रूप धारण कर लिया है कि हिंदी के साथ संस्कृत पर भी आपत्ति जता रहे हैं। हिंदी विरोध के अलावा उन्होंने परिसीमन को लेकर भी यह माहौल बनाना शुरू कर दिया है कि इससे दक्षिण के राज्यों को राजनीतिक क्षति उठानी पड़ेगी। हालांकि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री यह स्पष्ट कर चुके हैं कि परिसीमन से किसी राज्य को कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन स्टालिन ऐसा हो होने का हौवा खड़ा करने में लगे हुए हैं। यह सही है कि लोकसभा सीटों का परिसीमन प्रस्तावित है, लेकिन वह तो तब होगा, जब जनगणना होगी। जब न जनगणना हुई है और न ही यह तय हुआ है कि वह किस आधार पर होगा, तब फिर स्टालिन उसे लेकर लोगों को आशंकित करने में क्यों जुटे हुए हैं? इससे बुरी बात और कोई नहीं कि डीएमके नेता शिक्षा नीति को अपनी सस्ती राजनीति का विषय बनाएं और वह भी झूठ का सहारा लेकर। उन्हें ऐसा करने से रोका जाना चाहिए, क्योंकि त्रिभाषा फार्मूले में हिंदी का उल्लेख तक नहीं है। यदि स्टालिन को यकीन न हो तो वह नई शिक्षा नीति तैयार करने वाली समिति के प्रमुख के. कस्तूरीरंगन से संपर्क करें, जो खुद तमिलियन हैं।

पुलिस के लिए चुनौती

तस्करों के खिलाफ पंजाब पुलिस की ओर से चलाए जा रहे अभियान के बीच सीमा पार से ड्रोन के माध्यम से हेरोइन एवं हथियारों की मंगवाने की घटनाओं का न रुकना गंभीर मामला है। पुलिस की ओर से कई आरोपितों के घर गिराए जा चुके हैं और यह कार्रवाई जारी है। इसके बाद भी यदि तस्करों की सक्रियता बरकरार है तो इसे दुस्साहस ही कहा जाएगा। फिरोजपुर में जहां पाकिस्तान से मंगवाई गई तीन किलो हेरोइन के साथ दो आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है, वहीं अमृतसर में भी एक तस्कर को गिरफ्तार करके उससे दो पिस्तौल बरामद की गई है। यह पिस्तौल भी पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से मंगवाई गई थी। बीएसएफ के मुस्तैद जवान सीमा पार से आने वाले ड्रोनों को फायर करके गिरा देते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ ड्रोन उनकी नजरों से बच जा रहे हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे लोगों पर पैनी नजर रखी जानी चाहिए, जिनकी गतिविधियां संदिग्ध हैं। पुलिस को ऐसे लोगों की पहचान करने के लिए अपना सूचना तंत्र मजबूत करना होगा, जो ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान से हेरोइन एवं हथियार मंगवाते हैं। पाकिस्तान में बैठे तस्करों से जिन लोगों के संबंध हैं यदि उनको सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाता है तो काफी हद तक ड्रोन की गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सकता है। बेशक पुलिस के लिए यह चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन इच्छाशक्ति दिखाई जाए तो तस्करों का नेटवर्क खत्म किया जा सकता है।

> पाकिस्तान में बैठे तस्करों से सीमावर्ती जिलों के जिन लोगों के संबंध हैं उनको सलाखों के पीछे पहुंचाना आवश्यक है

भारत के लिए आपदा में अवसर

भरत झुनझुनवाला

भारत को चाहिए कि ट्रंप द्वारा टैरिफ बढ़ाने से डरने के बजाय अपना निर्यात अन्य देशों में करने के उपाय खोजे

अवधेश राजपूत

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आयातित होने वाले माल पर आयात कर (टैरिफ) बढ़ाने की घोषणा की है। नए कर 2 अप्रैल से प्रभावी हो जाएंगे। ट्रंप को चिंता है कि अमेरिका द्वारा दूसरे देशों से जो माल खरीदा जा रहे हैं, उससे अमेरिकी उद्योग चौपट हो रहे हैं। अमेरिका दूसरे देशों पर निर्भर होता जा रहा है, विशेषकर भारत और चीन पर। ऐसे में ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका में खपत होने वाले माल का अधिकांश उत्पादन देश में ही किया जाए, जिससे अमेरिका दूसरे देशों के शिकंजे से बच सके। इस दिशा में ट्रंप ने पूरान किया है कि दो अप्रैल से वह भारत से आयातित होने वाले माल पर उतना आयात कर लगाएंगे, जितना भारत द्वारा अमेरिका से आयातित होने वाले माल पर लगाया जाता है। ट्रंप का सोच है कि ऊंचे आयात कर लगाने से आयात महंगे हो जाएंगे और इसकी तुलना में घरेलू उत्पादन सस्ता पड़ने लगेगा, जिससे अमेरिका में उद्योग चल निकलेंगे, रोजगार उत्पन्न होंगे और अमेरिकी आर्थिकी स्वावलंबन की ओर बढ़ेगी। हालांकि आयात कर लगाने से व्यापार घाटा कम नहीं होगा। जब आयात अधिक और निर्यात कम हो तो देश का व्यापार घाटे में चला जाता है, जैसे घर के खर्च अधिक और आय कम हो तो परिवार को घाटा झेलना पड़ता है।

आर्थिकी के लिए किसी भी देश की विदेशी मुद्रा बहुत आवश्यक होती है। विदेशी मुद्रा मुख्य रूप से दो स्रोतों से प्राप्त होती है। एक निर्यात और दूसरे, ऋण से। निर्यात और ऋण से मिलने वाली विदेशी मुद्रा का उपयोग आयात भुगतान के लिए किया जाता है। इसमें एक फार्मूला बनता है: निर्यात+ऋण=आयात। स्वाभाविक है कि निर्यात और आयात बराबर तब ही होंगे, जब ऋण शून्य हो जाए। अर्थात व्यापार घाटा तभी शून्य होगा, जब ऋण शून्य हो जाए। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए एक दुकानदार को ऊंचे जीवन स्तर की आदत है। वह ऋण लेकर महंगी कार में घूमता है। ऋण पर ब्याज देने के कारण उसकी दुकान घाटे में चल रही है। ऐसे में यदि वह विक्रय की राशि में से 10 प्रतिशत रकम ऋण पर ब्याज देने के लिए अलग रख दे तो दुकान का घाटा बढ़ेगा। तब 100 रुपये की बिक्री में से दुकान चलाने के लिए केवल 90 रुपये मिलेंगे और दुकान का घाटा बढ़ता जाएगा। जैसे कैंसर के रोगी को दो पिलाने से उपचार नहीं होता और उसे रेडिएशन थेरेपी देनी ही पड़ती है, वैसे ही घाटे के रोगी अमेरिका का आयात कर बढ़ाने से उपचार नहीं होगा। उसे अपने सरकारी खर्च घटाने होंगे। इस दिशा में पहल तो हुई, पर विरोध भी शुरू हो गया है।

अमेरिका का वार्षिक घाटा करीब 1.8 ट्रिलियन (लाख करोड़) डालर का है। इस घाटे की भरपाई के लिए अमेरिकी सरकार भारी मात्रा में ऋण ले रही है। इस ऋण से पिले डालर का उपयोग अमेरिका द्वारा भारत, चीन आदि देशों से माल का आयात करने के लिए किया जा रहा है। इस कारण अमेरिका का व्यापार घाटा बढ़ा हुआ है। इस ऋण से अमेरिकी सरकार अपने नागरिकों को बेरोजगारी भत्ता एवं स्वास्थ्य सेवाएं इत्यादि मुहैया कराती है, जिससे अमेरिकी नागरिक का जीवन स्तर ऊंचा बना हुआ है। जिस प्रकार दुकानदार को ऋण लेकर लक्जरी कार में सैर करने की लत लग जाए तो उसकी दुकान घाटे में चली जाती है, उसी प्रकार अमेरिकी नागरिकों की ऊंचे जीवन स्तर की लत से अमेरिका की दुकानदारी घाटे में चल रही है। जब तक अमेरिकी सरकार ऋण लेती रहेगी, तब तक निश्चित रूप से निर्यात कम और आयात अधिक होंगे और व्यापार घाटा शून्य नहीं हो सकता।

यदि ट्रंप द्वारा आयात कर बढ़ाए जाते हैं तो व्यापार घाटा कम होने के स्थान पर बढ़ेगा। आयात कर बढ़ाने से वस्तुएं महंगी होंगी और आयात घटेंगे। आयात घटने से अमेरिका में चीनी मुद्रा युआन की मांग घटेगी। उसकी मांग कम होने से युआन के दाम गिरेंगे और फिर डालर के दाम बढ़ेंगे। डालर के दाम बढ़ने से अमेरिकी निर्यात दबाव में आएंगे। आयात कर बढ़ाने से आयात कम अवश्य होंगे, पर निर्यात भी घटेंगे और व्यापार घाटा पूर्ववत बना रहेगा। व्यापार घाटे को कम करने का उपाय है कि अमेरिकी सरकार अपने बजट घाटे पर नियंत्रण करे। जब अमेरिकी सरकार विदेशी ऋण लेकर आयात करना बंद कर देगी तब निर्यात और आयात का कांटा बराबर हो जाएगा।

पहले कार्यकाल में भी आयात कर बढ़ाकर ट्रंप घाटे पर नियंत्रण नहीं कर पाए थे, लेकिन यह भी सही है कि ट्रंप के पहले कार्यकाल में चीन से अमेरिका का व्यापार घाटा कम हुआ था, लेकिन वियतनाम और दूसरे देशों से व्यापार घाटा उतना ही बढ़ गया था। ट्रंप बजट घाटे को लेकर भी चिंतित हैं। उन्होंने एलन मस्क को जिम्मेदारी दी है कि वह सरकार में निहित अकुशलताओं को चिह्नित करें और सरकारी फिजूलखर्ची पर नियंत्रण करें, लेकिन यह पहल ऊंट के मुंह में जीरा साबित होगी। इस शोर का उद्देश्य घरेलू वोटर को लुभाना मात्र है। सच यह है कि अमेरिकी जनता अपनी कमाई से अधिक खपत कर रही है। इस ऊंचे जीवन स्तर को पोषित करने के लिए अमेरिका द्वारा भारी मात्रा में ऋण लिया जा रहा है, जिसका तार्किक परिणाम व्यापार घाटा है।

भारत को चाहिए कि ट्रंप द्वारा लगाए जाने वाले आयात कर से डरने के बजाय अपना निर्यात अन्य देशों में करने के उपाय खोजे। कई विश्लेषकों का मत है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था आने वाले समय में संकट में पड़ सकती है। इसलिए भारत को चाहिए कि अपने निर्यात दूसरे देशों में बढ़ाने के प्रयास करे, जिससे अमेरिकी सरकार द्वारा आयात कर लगाने अथवा अमेरिकी अर्थव्यवस्था के संकट आने के कारण हमारे ऊपर परेशानी न आए। ट्रंप की कवायद डी-ग्लोबलाइजेशन या बि-वैश्वीकरण की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत से बड़ी मात्रा में पूंजी का पलायन ही रहा है। ऐसे में भारत को चाहिए कि वैश्वीकरण के रास्ते विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के पीछे भागने के स्थान पर अपनी पूंजी को बाहर जाने से रोकने के लिए उचित उपाय करे। यदि हमने इस संभावित चुनौती का सही तरीके से समाधान तलाश लिया तो ट्रंप द्वारा लगाए गए आयात कर हमारे लिए वरदान साबित हो सकते हैं।

(लेखक अर्थशास्त्री हैं)
response@jagran.com

भाषा पर भड़काने वाली राजनीति

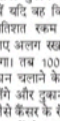

कृपाशंकर चौबे

स्टालिन भारतीय भाषाओं को आपस में लड़ाने और अंग्रेजी को आधिपत्य जमाए रखने का अवसर ही दे रहे हैं?

हिंदी के विरुद्ध माहौल बनाते स्टालिन। फाइल

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और द्रमुक नेता एमके स्टालिन हिंदी विरोध के लिए हद से ज्यादा आगे बढ़ गए हैं। वह अब हिंदी के खिलाफ उसकी बोलियों को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है, 'अन्य राज्यों के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कभी सोचा है कि हिंदी ने कितनी भारतीय भाषाओं को निगल लिया है? भोजपुरी, अवधी, ब्रज, बुंदेली, गढ़वाली, कुमाऊंनी, मगही, मारवाड़ी, मालवी, छत्तीसगढ़ी, संथाली, अंगिका, हो, खरिया, खोरठा, कुरमाली समेत कई अन्य अब अस्तित्व के लिए हांफ रही हैं। एक अखंड हिंदी पहचान के लिए जोर देने से प्राचीन मातृभाषाएं खत्म हो रही हैं। यूपी और बिहार कभी भी सिर्फ हिंदी के गढ़ नहीं थे। उनकी असली भाषाएं अब अतीत की निशानी बन गई हैं। तमिलनाडु इसका विरोध करता है।' कहने की जरूरत नहीं कि स्टालिन का यह वक्तव्य भड़काने वाला है। स्टालिन द्वारा हिंदी पर लगाया गया यह आरोप पूरिलकुल निरर्थक है, क्योंकि हिंदी क्षेत्र की इन बोलियों-भाषाओं के सम्मिलित रूप को ही हिंदी कहा जाता है। इनसे प्राप्त जीवनशक्ति से हिंदी फलती-फूलती है। ठेठ हिंदी का ठाठ उसकी बोलियों के सौंदर्य से निर्मित होता है।

हिंदी समाज एक साथ अपनी जनपदीय भाषा जैसे भोजपुरी, अवधी, ब्रज, बुंदेली, गढ़वाली, कुमाऊंनी, मगही भी बोलता है और हिंदी भी। लिखने-पढ़ने का अधिकांश कार्य वह हिंदी में जरूर करता है। इसीलिए राजभाषा अधिनियम के अनुसार उन्हें 'क' श्रेणी में रखा गया और दस राज्यों में बंटने के बावजूद उन्हें 'हिंदी भाषी' कहा गया। भोजपुरी, राजस्थानी, अवधी, ब्रज आदि हिंदी के अभिन्न अंग हैं। इन बोलियों एवं उपभाषाओं की समृद्धि से हिंदी को और हिंदी की समृद्धि से उसकी उपभाषाओं एवं बोलियों को लाभ होता रहा है। जब हिंदी को स्वीकार्यता बढ़ रही है, तब स्टालिन जैसे नेता उसके घर को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। सूचना-संचार में हिंदी का हस्तक्षेप तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया के तमाम देश भारत जैसे बड़े बाजार के निमित्त हिंदी को अपने भविष्य का रास्ता मान रहे हैं। हिंदी के घर को बांटकर और समाज में विभेद पैदा कर स्टालिन खाई खोदने का काम कर रहे हैं।

इसके पहले उन्होंने संस्कृत का भी बेतुका विरोध किया था। इसी तरह वह यह दुष्प्रचार भी कर रहे हैं कि त्रिभाषा फार्मूला दरअसल हिंदी थोपने की कोशिश है। क्या ऐसे ब्रायन देकर स्टालिन भारतीय भाषाओं को आपस में लड़ाने और अंग्रेजी को आधिपत्य जमाए रखने का अवसर नहीं दे रहे हैं?

हिंदी थोपने का नाहक आरोप लगाने वाले स्टालिन को यह बोध होना चाहिए कि भारतीय भाषाओं को खतरा अंग्रेजी से है। हिंदी का तमिल या किसी भारतीय भाषा से कोई झगड़ा नहीं। यह नहीं भूलना चाहिए कि सभी भारतीय भाषाओं में एक सहकार संबंध रहा है। भारतीय भाषाओं एवं राज्यों को अलग-अलग खंडों में बांटे जाने के बावजूद भारत अपने संस्कृतिक संदर्भों के कारण एक सूत्र में बंधा है। भारतीय भाषाओं के सहकार संबंध से तमिल कवि सुब्रह्मण्य भारती भलीभांति परिचित थे। इसीलिए वह हिंदी के प्रबल पक्षधर थे। वह तमिल समाचार पत्र 'इंडिया' के संपादक थे और उसमें वह एक पृष्ठ हिंदी को देते थे। 'इंडिया' के 15 दिसंबर, 1906 के अंक में उन्होंने लिखा था, 'तीस करोड़ लोगों में से आठ करोड़ से अधिक लोग हिंदी बोलते हैं। महाराष्ट्र से लेकर बंगाल के लोग हिंदी आसानी से समझ लेते हैं। तमिलभाषी, तेलुगुभाषी थोड़ा सा परिश्रम करेंगे तो हिंदी सीख सकते हैं।'

केंद्र सरकार 2022 से सुब्रह्मण्य भारती के जन्मदिन 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाती है। इसके अलावा भारतीय भाषाओं के संबंध को बल देने के लिए तीन वर्षों से काशी तमिल संगमम का आयोजन सफलतापूर्वक किया जा रहा है। लगता है इन आयोजनों से स्टालिन की बेचैनी बढ़ी है। तमिलनाडु में सत्ता विरोधी माहौल भी है। कदाचित स्टालिन ने इसीलिए भाषा के पुराने हथियार का उपयोग शुरू किया है। तमिलभाषी क्षेत्र में भाषा को राजनीति का हथियार बनाने का प्रयोग दशकों पुराना है। 1937 में मद्रास सरकार के प्रमुख के रूप में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने हाईस्कूल स्तर पर हिंदुस्तानी को अनिवार्य विषय बना दिया तो उसके खिलाफ उग्र आंदोलन शुरू हो गया था।

आत्मसम्मान आंदोलन के नेता ईवी रामास्वामी नायकर यानी पेरियार ने गिरफ्तारी दी थी। इनमें पेरियार की छात्राछाया में ही पनपे सीएन अन्नादुरई और करुणानिधि जैसे नेता भी थे। करुणानिधि की राजनीति हिंदी विरोधी आंदोलन में हुई उनकी गिरफ्तारी से ही चमका। इस आंदोलन का प्रभाव दक्षिण के अन्य हिस्सों में भी दिखा, मगर उसकी तीव्रता और विस्तार तमिलनाडु जैसा नहीं था।

संविधान के अनुसार 1965 में हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित होना था। तब अंग्रेजी संघ की सहयोगी राजभाषा नहीं रह जाती, किंतु उसके कुछ दिन पूर्व ही मद्रास में सी. राजगोपालाचारी की स्वतंत्र पार्टी और अन्नादुरई की द्रमुक के नेतृत्व में तमिलभाषियों ने राजभाषा के रूप में हिंदी का विरोध करते हुए हिंसक आंदोलन शुरू कर दिया। यह वही राजगोपालाचारी थे, जिन्होंने कभी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के पक्ष में न केवल वक्तव्य दिया था, बल्कि मद्रास की सरकार के प्रमुख के तौर पर हिंदी को लागू भी किया था। तब से नाहक हिंदी विरोध की राजनीति वहां जारी है। यह देश की एकता के लिए घातक है।

(लेखक महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा में प्रोफेसर हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

इच्छाओं का संजाल

इच्छा का अर्थ है-कुछ पाने की अभिलाषा। इच्छा जीवन के लिए वरदान साबित हो सकती है एवं अभिशाप भी। इच्छा हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होगी अथवा हानिकारक, यह हमारे अंतर्मन पर निर्भर है। प्रायः इच्छा को शत्रु के रूप में देखा जाता है, किंतु इच्छाएं सदैव हानिकारक नहीं होतीं। यदि हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रण एवं सकारात्मकता का कवच पहना दें तो निःसंदेह वही इच्छाएं कहीं न कहीं हमारे आत्मविकास एवं आत्मोन्नति का मार्ग भी प्रशस्त करेंगी।

मन में उठने वाली इच्छा के साथ कौनस भाव संयुक्त है, इस पर ही उसके प्रभावों एवं परिणामों की आधारशिला निर्मित होती है। यदि इच्छा के साथ शांति एवं अपेक्षारहित कर्म करने का भाव जुड़ा हुआ है, तो वह निश्चित रूप से हमारे व्यक्तित्व का विकास करके उसे प्रगति के उच्चतम शिखर तक ले जाएगी, किंतु यदि वही इच्छा बेचैनी एवं उत्कंठा के भाव से घिरी हुई है, तो निश्चित रूप से वह हमारे अंतर्मन की शांति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न करेगी। इसका परिणाम यह होगा कि हम अपने किसी भी कार्य की पूर्णता के साथ संपन्न कर पाने में अक्षम एवं असमर्थ हो जाएंगे।

इच्छाएं पूर्णता को प्राप्त करते ही अंतर्मन के भीतर एक संजाल निर्मित करने लगती हैं। एक इच्छा से अन्य इच्छाओं की उत्पत्ति होने लगती है। यह स्थिति हमें अशांति की ओर ले जाती है। हमें इच्छाओं के इस संजाल को अनंत की ओर बढ़ने से रोकना चाहिए, क्योंकि यदि यह संजाल बढ़ता गया तो अंतर्मन अनंत इच्छाओं से घिर जाएगा। ऐसी दशा में हम जीवन के वास्तविक आनंद को भोगने से वंचित रह जाएंगे। जब इच्छाओं पर नियंत्रण की लगाम लगी होगी एवं उनका स्वरूप अभिसारी होगी तो वे हमारे लिए लाभदायक होंगी। यदि वे नियंत्रणमुक्त होंगी एवं अपसारी भाव की समावेशित किए होंगी तो वे हमारे लिए हानिकारक होंगी।

प्रेरणा अवस्थी

मियावाकी पद्धति से पर्यावरण संरक्षण

रेजाना मिश्रा

प्रदूषण नियंत्रित करने के साथ-साथ यह पद्धति स्थानीय जैवविविधता को भी संरक्षित करने में मददगार सिद्ध होती है

महाकुंभ के अवसर पर प्रयागराज को हरभरा बनाने के लिए मियावाकी पद्धति का प्रयोग किया गया। प्रशासन का पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यह एक सकारात्मक कदम है। जापान में विकसित इस पद्धति के अंतर्गत पौधों को उनकी प्राकृतिक वृद्धि दर, मिट्टी की गुणवत्ता और जलवायु के अनुसार चुना जाता है, ताकि पौधे न केवल जल्दी विकसित हों, बल्कि लंबे समय तक हरियाली प्रदान कर सकें। इस प्रक्रिया में पौधों के बीच की दूरी का खास ध्यान रखा जाता है, जिससे पौधे आपस में प्रतिस्पर्धा करते हुए तेजी से बढ़ें और घना वन क्षेत्र तैयार हो सके। इससे न केवल वायु में मौजूद कार्बन डाईआक्साइड की मात्रा कम होती है, बल्कि शहर के तापमान में भी संतुलन बना रहता है। बड़े आयोजन के दौरान भीड़ के कारण उत्पन्न प्रदूषण को नियंत्रित करने में यह पहल अत्यंत प्रभावी सिद्ध हो सकती है। प्रयागराज में इसे अपनाकर लोगों को त्वरित हरियाली का अनुभव कराने का प्रयास किया गया।

यदि मियावाकी पद्धति को अपनाया जाए, तो यह न केवल शहरी प्रदूषण को कम करने में सहायक होगी, बल्कि शहरों में हरित आवरण के विस्तार का एक आदर्श माडल भी प्रस्तुत करेगी। प्रदूषण नियंत्रित करने के साथ-साथ यह तकनीक स्थानीय जैवविविधता को भी संरक्षित करने में मददगार सिद्ध होती है, जिससे शहर में रहने वाले जीव-जंतुओं के लिए भी अनुकूल वातावरण बनता है। हरा-भरा शहर लोगों के जीवन स्तर में सुधार करता है। साफ-सुथरे वातावरण में रहने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कम होती हैं और लोगों में ताजगी का अनुभव होता है। हरित शहरों का आकर्षण निवेशकों और पर्यटकों दोनों में बढ़ता है, जिससे आर्थिक विकास की संभावनाएं भी उजागर होती हैं। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान इस तरह की पहल से न केवल शहर की छवि में निखार आया, बल्कि स्थानीय लोगों में भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति नई ऊर्जा का संचार हुआ।

हालांकि इस तरह के प्रयासों में कुछ चुनौतियां भी सामने आती हैं। महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन के दौरान पौधों की सही देखभाल और निरंतर सिंचाई सुनिश्चित करना प्रशासन के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। यदि पौधों का समय-समय पर उचित रख-रखाव नहीं किया गया, तो उनके विकास पर प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए इस पद्धति के सफल क्रियान्वयन के लिए स्थानीय प्रशासन को तकनीकी विशेषज्ञों के साथ मिलकर एक दीर्घकालिक योजना बनानी होगी। नियमित निरीक्षण, जल प्रबंधन के आधुनिक तरीके और स्थानीय समुदाय का सहयोग इस प्रयास को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रयागराज में मियावाकी पद्धति का सफल प्रयोग भविष्य के लिए एक आदर्श माडल प्रस्तुत करता है, जिसे अन्य शहर भी अपनाने में रुचि दिखा सकते हैं।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

न्याय में देरी अन्याय

संपादकीय आलेख 'जानी-पहचानी सुस्ती' न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति व्यवस्था पर चिंता जाहिर की है। सर्वोच्च न्यायालय चाहता है कि लाखों की संख्या में लंबित मामलों का निपटारा कछुए की चाल से न हो, अपितु न्याय को अपेक्षित गति प्रदान करने हेतु अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति से भी उसे परहेज नहीं है, किंतु उच्च न्यायालय इस दिशा में कोई खास या उल्लेखनीय पहल नहीं कर रहे। यह वाकयन में चिंतनीय है। न्याय में देरी किसी अन्याय से कम नहीं। रिक्त पदों को अस्थायी रूप से भरने की मंशा यही है कि किसी के साथ अन्याय न हो। इतिहास गवाह है कि 'तारीख पे तारीख' के चक्कर में लोगों की पीढ़ियां बदल जाती हैं। इसलिए न्याय तंत्र में नियुक्ति की व्यवस्था को बदलने की महती आवश्यकता है। लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ न्याय तंत्र है। इसे मजबूत बनाने की जरूरत से इन्कार नहीं किया जा सकता। न्याय में देरी का फायदा उठाकर अपराधी वर्षों तक समाज का हिस्सा बने रहते हैं और फिर किसी अपराध का डर हमेशा बना रहता है। न्यायिक प्रणाली का मुस्तैद रहना और त्वरित गति से कार्य करते रहना इसलिए भी जरूरी है कि लोगों का विश्वास बना रहे, उन्हें तसल्ली मिलती रहे कि एक जगह है, जहां उन्हें इंसाफ मिलेगा। उनकी आवाज सुनी जाएगी। स्थायी भर्ती में लंबी प्रक्रिया से हो रही देरी का खामियाजा न्याय की गुहार लगाने वाले को भुगतना पड़ रहा है। इसके अभाव में लाखों मामले वर्षों तक विचाराधीन बने हैं। आखिर व्यवस्था में कब सुधार होगा? कब त्वरित न्याय मिलेगा? यह प्रश्न अपने आप में विचारणीय है। अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति की अनुमति देने के बावजूद अब तक नियुक्ति नहीं होना, वास्तव में जिम्मेदारों की उदासीनता और लापरवाही का प्रत्यक्ष प्रमाण है। न्याय तंत्र को सुधारने की नीयत ठीक हो तो फिर न्याय में देरी का सवाल ही पैदा नहीं होगा। अन्यथा न्याय मिलना औपचारहीन रह जाएगा।

मोहित सोनी, कुर्सी, मध्य प्रदेश

सही कदम

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आठ मार्च को दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली महिलाओं को प्रतिमाह 2,500 रुपये वितरित करने की घोषणा को मुफ्त की रेवड़ी बांटने की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, बल्कि इसे अंत्योदय की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। जहां सीढ़ी के अंतिम सोपान पर खड़े व्यक्ति को सहायता देने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या कोई अन्य पेंशन पाने वाली या सरकार की अन्य किसी योजना की लाभार्थी महिलाओं को लाभ नहीं मिलेगा। केवल गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली 21 से 60 वर्ष की महिलाएं ही इस योजना में पंजीकरण हेतु आवेदन कर सकती हैं। पंजीकृत महिलाओं को ही इस योजना में शामिल किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने इस वर्ष 5,100 करोड़ रुपये का प्रविधान किया है। प्रतिमाह 2,500 रुपये के हिसाब से प्रतिवर्ष प्रति महिला 30,000 देय होंगे। एक अनुमान के अनुसार दिल्ली में ऐसी महिलाओं की संख्या 17 लाख है।

धर्मेंद्र नाथ रस्तोगी, गाजियाबाद

होली उमंग और उत्साह का प्रतीक

भारत त्योहार और पर्वों की संस्कृति का देश है। इसमें हर माह कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। ये त्योहार मानव-समाज की उमंगों एवं अरमानों के प्रतीक हैं। मनुष्य स्वाभाविक होता है, आशा ही उसे प्रसन्न और कार्यशील रखती है। इसलिए आशाओं को जीवित और प्रचंड रखने के लिए वह पर्व, त्योहार आदि उत्सव मनाता रहता है। त्योहारों में मानव जाति को संस्कार और विचार देने की एक अंतरधारा छिपी रहती है। होली का त्योहार अपने ढंग का अनोखा और निराला त्योहार है। अन्य त्योहारों में देव-मूर्तियों की पूजा होती है, परंतु इसमें किसी मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है। यह त्योहार बुराइयों के विध्वंस का प्रतीक है। यह गुलाल-अबीर उड़ाने-लगाने का त्योहार है। इसके मूल में भी मानव जाति की समानता, भाईचारा और एक-दूसरे के संग हर्ष-उल्लास मनाने की भावना निहित है।

कांतिलाल मांडोत, नई दिल्ली

मेलबाक्स

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर सारगर्भित पत्र अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *सब अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संकलन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

चिंतन

धमकी देकर देश को दहशत में डालने वालों पर नकेल जरूरी

भारत की विभिन्न धमकी मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कभी स्कूल, कभी रेलवे स्टेशन तो कभी एयरलाइंस की फ्लाइटों को बम से उड़ाने की धमकी मिलना आम बात हो गई है। कौन भूल सकता है जब बीते साल अक्टूबर में एक साथ 95 फ्लाइटों को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिससे पूरे देश में दहशत फैल गई। अब सोमवार को एक बार फिर मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही एअर इंडिया की फ्लाइट एआई 119 को बम से उड़ाने की धमकी मिली। 8 घंटे 37 मिनट की उड़ान के बाद फ्लाइट को मुंबई डायवर्ट कर दिया गया। फ्लाइट में 19 क्रू मेंबर्स समेत 322 यात्री सवार थे। फ्लाइट के वॉशरूम में एक नोट मिला, जिसमें बम की धमकी दी गई थी। सुरक्षा प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए रास्ते से ही विमान को वापस मुंबई लाने का फैसला किया गया। विमान 10:25 बजे मुंबई पहुंचा। जब तक जांच पूरी नहीं हुई यात्रियों, सुरक्षा एजेंसियों समेत देश के बड़े हिस्से में दहशत का माहौल रहा। न जाने कौन फैला रहा है इस तरह की दहशत। देश की प्रत्येक एयरलाइन की घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को एक सप्ताह के भीतर बम से उड़ाने की धमकियां मिली हैं। इससे खलबली मचना स्वाभाविक है। इससे दहशत तो फैलती ही है साथ में हवाई यात्रा का टाइम टेबल गड़बड़ा जाता है। कितनी ही फ्लाइट जांच के लिए रोक दी जाती हैं। यात्रियों को भारी असुविधा होती है। वे समय पर अपने गंतव्य पहुंच नहीं पाते या कनेक्टिंग फ्लाइट मिस कर जाते हैं। इन धमकियों के पीछे कौन है और उसका क्या उद्देश्य है? अनेक एजेंसियां इसका पता लगाने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ खास नहीं निकल पा रहा है। सोशल मीडिया और ई-मेल के माध्यम से विमान में धमाका करने की धमकी देना आम बात होती जा रही है। आखिर ये कितने शातिर लोग हैं जो इतने दिनों से जांचकर्ताओं की पकड़ में नहीं आए। उड़ान में खलल डालकर उसे रोक देना उनका उद्देश्य मालूम पड़ता है। उनकी धमकी वाकई गंभीर है या खोखली इसका अंदाजा कैसे लगाया जाए। कुछ धमकियां तो ऐसी उड़ान को लेकर थीं जो पूरी हो चुकी थीं। वैसे तो हर उड़ान के पहले विमान और उसके सिस्टम की पूरी तरह जांच की जाती है फिर भी धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ऐसी धमकियां विमानन क्षेत्र की मजबूती की परीक्षा ले रही हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियों को ऐसे शरारती तत्वों को यथाशीघ्र खोज निकालना होगा। इस तरह का अपराध करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसी धमकियां देने वाले में सिरफिरे, मानसिक रुग्ण के अलावा कोई ऐसा यात्री भी हो सकता है जो उड़ान में विलंब करवाना चाहते हैं। यह भी देखना होगा कि ऐसी धमकी के पीछे कोई एक व्यक्ति है या कोई समूह! कॉल या ई-मेल कहां से आया, इसका तुरंत पता लगाकर शरारती तत्व को पकड़ा जाना चाहिए। साइबर सुरक्षा एजेंसियां ऐसा कर सकती हैं। अनेक डिजीटेक टूल हैं जिनसे पता लगाया जा सकता है कि कौन से शरारती तत्व यह करतूत कर रहे हैं। सोशल मीडिया कंपनियों के पास भी पता लगाने के संसाधन हैं कि कौन से फेक अकाउंट से इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं। यह भी संभव है कि इस तरह की धमकी बाहर देश से आ रही हों। जांच एजेंसियों पर इस पर भी नकेल कसने की जरूरत है। इस मामले को अब सरकार को टॉप प्रायरिटी में रखते हुए इसकी सघन जांच करानी चाहिए, ताकि भारत की एयरलाइंस और लोगों को इससे छुटकारा मिल सके।

सियासत

आलोक शुक्ला

प्रस्तावित लोकसभा क्षेत्रों के परिसीमन को लेकर टकराव

भारत में इस समय 2026 में प्रस्तावित लोक सभा क्षेत्रों के परिसीमन पर काफी टकराव चल रहा है। परिसीमन एक संवैधानिक अनिवार्यता है, परन्तु दक्षिण भारत में इसका भारी विरोध हो रहा है। भारत का संविधान कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के वोट का मूल्य एक बराबर होना चाहिए। इसीलिए लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं में जनसंख्या के आधार पर सीटों की संख्या का निर्धारण किया जाता है। परिसीमन के द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण भी किया जाता है। भारत में वर्ष 1951, 1962 एवं 1972 में परिसीमन किया गया था। इसके अनुसार एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 10 लाख की जनसंख्या है। आपातकाल के दौरान संविधान (42 वां संशोधन) अधिनियम, 1976 पारित हुआ जिसके द्वारा वर्ष 2000 के बाद की जनगणना तक के लिए लोक सभा में सीटों की संख्या को फ्रीज कर दिया गया। सन् 2002 में वाजपेयी की सरकार ने लोक सभा सीटों की संख्या पर फ्रीज को 2026 तक के लिए बढ़ा दिया था। प्रस्तावित परिसीमन को लेकर सबसे बड़ी चिंता यह है कि इससे दक्षिण भारत के राज्यों में लोक सभा की सीटें कम हो जाएंगी। दक्षिण का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा और राष्ट्रीय निर्णयों में उनकी भूमिका कम होती जाएगी। दक्षिण में उत्तर की तुलना में विकास अधिक हुआ है। दक्षिण की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, स्वास्थ्य, शिक्षा और अधोसंरचना सभी क्षेत्रों में दक्षिण अधिक विकसित है। इसी कारण दक्षिण में जनसंख्या नियंत्रण बेहतर हुआ है और वहां की जनसंख्या अनुपातिक रूप से उत्तर की अपेक्षा बहुत कम हो गई है। केन्द्रीय करों की वसूली में दक्षिण का अनुपात उत्तर की तुलना में कहीं अधिक है। दक्षिण को लगता है कि यह उनके साथ अन्याय है। उनका कहना है कि दक्षिण के राज्य कब तक उत्तर की अक्षमता का बोझ उठाते रहेंगे। लोक सभा में दक्षिण का प्रतिनिधित्व वर्तमान में 24% है, यह इस परिसीमन के बाद घटकर 19% हो जाएगा। हाल ही में नागपटनम में तामिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इसी बात को रेखांकित करने के लिए लोगों से अधिक बच्चे पैदा करने का आह्वान तक कर डाला। गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कहा है कि परिसीमन से दक्षिण भारत के किसी भी राज्य की एक भी सीट कम नहीं होगी। परन्तु उनकी बात का कोई खास असर दक्षिण भारत के राज्यों में नहीं हो रहा है। उन्हें लगता है कि भी जनसंख्या के आधार पर किए गए परिसीमन में दक्षिण के राज्यों की सीटों में आनुपातिक कमी आएगी।

2026 के जनसंख्या प्रोजेक्शन के आंकड़ों के आधार पर अनुमान है कि इस परिसीमन से उत्तर प्रदेश की सीटों की संख्या वर्तमान 80 से बढ़कर 143 हो जाएंगी और बिहार की सीटों की संख्या वर्तमान 40 से बढ़कर 79 होगी। वहीं तमिल नाडु की वर्तमान 39 सीटों में केवल 10 सीटों की ही वृद्धि होगी। तामिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने 5 मार्च को परिसीमन के मुद्दे पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी जिसमें 60 से अधिक दलों ने भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी ने इस बैठक का बहिष्कार किया। इस बैठक में दक्षिण के राज्यों को 2026 की जनसंख्या के आधार पर प्रस्तावित परिसीमन का विरोध करने के लिए संगठित होने का आह्वान किया गया और 1971 की जनगणना के आधार पर परिसीमन करने की मांग की गई। भारत में 2011 की जनगणना के बाद कोई जनगणना नहीं हुई है। 2021 की जनगणना कोविड महामारी के कारण स्थगित कर दी गई थी। इस कारण हमारे पास जनसंख्या के आधिकारिक आंकड़े ही नहीं हैं। अभी तक सरकार ने इस बात की घोषणा नहीं की है कि अगली जनगणना कब होगी। कई पार्टियां जातिगत जनगणना की मांग भी कर रही हैं। नए परिसीमन का संबंध लोक सभा में महिला आरक्षण के लागू होने से भी है। नए संसद भवन में 888 सीटें बनाई गई हैं। यह भी इस बात का संकेत है कि नए परिसीमन में लोक सभा की सीटें बढ़ने की संभावना है। लंबे समय के सुधारों के रूप में भारत को शायद वित्तीय शक्तियों के विकेंद्रीकरण के बारे में भी सोचना होगा। केन्द्र द्वारा एकत्रित किए जाने वाले करों में राज्यों का हिस्सा बढ़ाने पर भी विचार करना चाहिए। ऐसा करने से लोक सभा में कम प्रतिनिधित्व वाले राज्यों को भी अपने विकास का पूरा मौका मिलेगा और वे शायद परिसीमन की कुछ कम चिंता करेंगे। संवैधानिक विशेषज्ञ और सभी राजनीतिक दल यदि मिलकर इस समस्या का हल खोजेंगे, तो कोई न कोई हल जरूर मिलेगा। टकराव और अलगाव की राजनीति से देश का भला नहीं हो सकता।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

प्रदूषित नदियों पर सियासत नहीं समाधान की जरूरत

विचार

डॉ. संजय शुक्ला

भारत जैसे धार्मिक मान्यता वाले देश में नदियां सदैव ही आस्था का केंद्र रही हैं लेकिन अब यह सियासी रार और विवाद का जरिया भी बन रहा है। बीते दिनों प्रयागराज में देश की सर्वाधिक धार्मिक महत्व वाली गंगा के तट पर संपन्न महाकुंभ के दौरान इस नदी में डुबकी लगाने की परंपरा और इसके पानी की शुद्धता पर काफी राजनीतिक आरोप - प्रत्यारोप हुआ। महाकुंभ के दौरान ही केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 'सीपीसीबी' के एक रिपोर्ट ने इस विवाद में घी डालने का काम किया जिसमें बताया गया कि प्रयागराज में गंगा और यमुना के पानी में अपशिष्ट जल प्रदूषण 'फेकल कोलिफॉर्म' का स्तर स्नान के लिए उपयुक्त नहीं है।

बोर्ड के इस रिपोर्ट पर खूब सियासी तलवार भांजे गए लेकिन उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तरप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सीपीसीबी के रिपोर्ट को एक सिरे से खारिज कर दिया। दूसरी ओर देश के अनेक विश्वविद्यालयों के साइंटिस्ट और पर्यावरणविद् भी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के इस रिपोर्ट पर बंटे नजर आए। अलबत्ता राजनीति से इतर इस बात में कोई संदेह नहीं है बल्कि देश में गंगा-यमुना सहित अधिकांश नदियों का पानी मानव स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित नहीं है। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रदूषण की वजह से देश की 328 नदियों का पानी सेहत के लिहाज से हानिकारक है। इन नदियों के पानी में मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रेट, क्रोमियम, लेड जैसे घातक रसायन और कोयला, चूना ,तांबा और लोहा जैसे हैवी मेटल्स पाए गए हैं। देश की प्रदूषित नदियों की सूची में छत्तीसगढ़ के महानदी, शिवनाथ, हसदेव, खारुन और इंद्रावती आदि नदियां शामिल हैं।

गौरतलब है कि भारत में धार्मिक मान्यता के अनुसार महाकुंभ की परंपरा हजारों वर्षों से रही है लेकिन इस महाकुंभ में जिस तरह से राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला चला उससे इस महापर्व की आस्था और मर्यादा को भी चोट पहुंचाया है। देश में जारी कमंडल और मंडल-2 की राजनीति के मद्देनजर यह महाकुंभ धार्मिक ध्रुवीकरण और तुष्टिकरण के सियासत में उलझते नजर आई। आलम यह था कि जहां एक ओर एक राजनीतिक पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अपने आपको इस महापर्व से दूर रखा तथा इसके किसी भी चूक पर सियासी वार का मौका नहीं छोड़ा वहीं दूसरी ओर दक्षिणपंथी पार्टी और संगठन महाकुंभ के राजनीतिक लाभ लेने से नहीं चूके। इंटरनेट क्रांति के वर्तमान दौर ने महाकुंभ और गंगा के प्रदूषण पर मचे रार को खूब हवा दिया। सोशल मीडिया पर इस महापर्व के बारे में तमाम सच्ची- झूठी खबरें, फोटो और वीडियो वायरल किए गए जिस पर सरकार ने भी सख्ती दिखाया लेकिन नतीजा सिफर रहा।

हाल ही में संपन्न दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान यमुना का प्रदूषण एक बार फिर से चुनाव का मुद्दा बना। भाजपा और कांग्रेस जहां यमुना के दूषित पानी और प्रदूषण पर आम आदमी पार्टी 'आप' के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पर लगातार हमलावर रही वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल ने भी हरियाणा के भाजपा सरकार पर यमुना के पानी में जहर मिलाने का आरोप जड़ दिया। गौरतलब है कि हर साल उत्तर भारतीयों के प्रमुख पर्व 'छठ पूजा' के दौरान दिल्ली की जीवनरेखा यमुना की सफेद झागदार तस्वीरें देश ही नहीं बल्कि दुनिया के मीडिया में सुर्खियां बटोरती है। विडंबना है कि हमारे सियासी दल हर चुनाव में यमुना की इस बेबसी पर घड़ियाली आंसू बहाकर वोट बटोरने का साधन बनाती है लेकिन आज तक कोई भी सरकार यमुना का भाग्य नहीं बदल पाई।

मोक्षदायिनी गंगा जिस पर देश की 40 फीसदी आबादी निर्भर है के पानी को जहां माइक्रोप्लास्टिक दूषित कर रही है तो यमुना में रासायनिक प्रदूषण के कारण केवल झाग ही दिखाई देते हैं। माइक्रोप्लास्टिक में सिंगल यूज प्लास्टिक के जहरीले केमिकल शामिल होते हैं जो सेहत के लिए काफी नुकसानदायक होते हैं। देश में सदियों से गंगा और यमुना ही नहीं बल्कि सभी नदियों के प्रति आस्था और सम्मान का भाव रहा है। इन्हें नदियों के तट पर कुंभ, महाकुंभ , धार्मिक और सांस्कृतिक मेले-मड़ाईयों का आयोजन होते रहा है तो मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्युपर्यंत सभी कर्मकांड नदियों के गोद में ही होता है। यह कहना बेमानी नहीं होगी कि मानव सभ्यता का विकास इन्हीं नदियों के तट पर हुआ है लेकिन इन नदियों के प्रति सर्वाधिक असभ्यता और अनुदारता आज का सभ्य समाज प्रदर्शित कर रहा है।

विचारणीय है कि पहाड़ों और जंगलों के गोद से निकलने वाली गंगा और यमुना शुभ्र और धवल होती है लेकिन यही नदियाँ मैदानी इलाकों में आती है तो आधुनिक सभ्यता और मशीनी विकास का कचरा समेट कर कालिमा में बदल जाती है। आलम यह कि प्रयागराज आते-आते मोक्षदायिनी गंगा का जल आचमन के लायक भी नहीं रह जाता है। इधर सरकारों के तमाम कोशिशों और योजनाओं के बावजूद गंगा दिनोंदिन मैली होती जा रही है। दरअसल इसके पृष्ठभूमि में प्रमुख कारण सरकारों और प्रशासनिक अमले में दृढ़ इच्छाशक्ति का आभाव, सफाई योजनाओं में भ्रष्टाचार व गुणवत्ता में कमी और सामुदायिक सहभागिता तथा जागरूकता में कमी है। बहरहाल गंगा-यमुना सहित अन्य नदियों में बढ़ते प्रदूषण के लिए इन नदियों के किनारे बढ़ती आबादी, शहरीकरण, उद्योग, कृषि में प्रयुक्त होने वाले कीटनाशक और उर्वरक, अपशिष्ट जल का प्रवाह और धार्मिक व सामाजिक आचरण जिम्मेदार हैं।

बहरहाल ऐसा नहीं है कि देश की सरकारों ने मैली होती नदियों की सफाई की सुध नहीं ली लेकिन नतीजा आशाजनक नहीं है। साल 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने गंगा की सफाई के लिए पहला गंगा एक्शन प्लान लागू किया, साल 2009 में यूपीए सरकार ने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन अथॉरिटी बनाई गई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में 'नमामि गंगे' जैसी महत्वाकांक्षी योजना का आगाज किया था। अलबत्ता योजना के अंतर्गत अभी तक जितना काम हुआ है वह उत्साहवर्धक नहीं है और न ही सरकार के दावों के अनुरूप है।

अलबत्ता क्या हम ऐसे भारत की कल्पना कर सकते हैं जहां नदियां न हों गंगा और यमुना न हो, जहां क्षिप्रा और नर्मदा न हो, जहां गोदावरी और ब्रम्हपुत्र न हो, जहां महानदी और शिवनाथ न हो। बिलाशक यह कल्पना बेमानी है लिहाजा नदियों पर सियासत नहीं बल्कि इन्हें साफ रखने की दिशा में सोचना होगा। आखिरकार नदियों के कल-कल में ही जीवन का कल यानि भविष्य है। बहरहाल मरती नदियां कैसे जी उठती है? इसका उदाहरण लंदन की टेम्स नदी है जिसे 'डेड रिवर' घोषित कर दिया गया था जिसमें जलीय जीव-जंतु भी जीवित नहीं रह सकते थे लेकिन ब्रिटेन सरकार और समाज की दृढ़ इच्छाशक्ति ने इस नदी को दुनिया का सबसे सुंदर और साफ नदी का तमगा दिला दिया।

यह उदाहरण भारत के लिए भी प्रेरणा बन सकता है बशर्ते देश के राजनीतिक दल नदियों पर सियासत का कीचड़ फेंकने की जगह समाधान की दिशा में विचार करें। सरकारों का भी दायित्व है कि वह नदियों के सफाई के लिए लागू एक्शन प्लान के भ्रष्टाचार मुक्त और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति प्रदर्शित करे वहीं नागरिक समाज का भी दायित्व है कि वह नदियों के प्रति उदार और स्व- अनुशासित हों तभी देश की नदियां अविरल और निर्मल होंगी।

करेंगे दान तो बनेंगे समृद्ध और खुशहाल!

संकलित

दर्शन

एक विवेकशील प्राणी होने के नाते मनुष्य से त्याग की अपेक्षा स्वाभाविक है। वास्तव में मानव का पूर्ण विकास ही त्याग द्वारा संभव है। जो दूसरे के लिए जितना अधिक त्याग कर सकता है, वह उतना ही महान समझा जाता है। राजा हरिश्चंद्र को हम आज भी उनके त्याग के लिए ही तो स्मरण करते हैं। महर्षि दधीचि ने तो एक विराट लक्ष्य के लिए अपनी देह का ही त्याग कर दिया था। वास्तव में हमारे समृद्ध इतिहास में कई विभूतियां तो केवल अपनी त्याग भावना के लिए ही विख्यात हुई हैं। त्याग की भावना का विकास करने के लिए सभी धर्मों में दान की महिमा बताई गई है। कहा जाता है धन का दान करने से धन शुद्ध होता है। आवश्यक नहीं है कि मात्र धनी व्यक्ति ही दान करने में सक्षम हैं, क्योंकि उनके पास किसी वस्तु का अभाव नहीं है। दान की भावना जाग्रत होने पर आप पाएंगे कि आपके पास भी एक अक्षय भंडार है। मात्र धनदान या अन्नदान ही दान नहीं है। हो सकता है कोई व्यक्ति धनहीन हो, परंतु उसके पास एक स्वस्थ एवं निरोग शरीर हो। क्या ऐसे लोगों के लिए श्रमदान विकल्प नहीं है? उनके आसपास कितने अशक्त लोग मिल जाएंगे, जिनकी वे अपनी शारीरिक ऊर्जा से सेवा कर सकते हैं। किसी के कार्य में हाथ बंटा लेना भी श्रमदान है। विद्यादान या ज्ञानदान को तो उत्तम में सर्वश्रेस्तम माना गया है। किसी निर्धन बच्चे को निःशुल्क पढ़ा देना भी तो दान ही है। आप किसी भी प्रकार से अभावग्रस्त की सहायता कर सकते हैं, शरीर, मन, बुद्धि, धन और भाव सब उपकरण हैं।

जब कोई झूठा आरोप लगे तो धैर्य न छोड़ें

संकलित

प्रेरणा

द्वारका में एक सूर्य भक्त था सत्राजित। उसे सूर्य देव ने स्यमंतक नाम की चमत्कारी मणि दी थी। ये मणि रोज बीस तोला सोना उगलती थी। एक दिन श्रीकृष्ण ने सत्राजित से कहा कि आप ये मणि राजकोष में देंगे तो इससे मिले धन से प्रजा की अच्छी देखभाल हो सकेगी। सत्राजित ने श्रीकृष्ण को मणि देने से मना कर दिया। इस घटना के कुछ दिन बाद सत्राजित के भाई प्रसेनजित ने मणि चुरा ली। प्रसेनजित मणि लेकर जंगल में भाग गया। जंगल में एक शेर ने प्रसेनजित को मार दिया और खा गया। मणि जंगल में ही गिर गई। सत्राजित को जब प्रसेनजित और अपनी मणि नहीं मिली तो उसने श्रीकृष्ण पर आरोप लगा दिया कि कृष्ण ने ही मेरी मणि चुराई है और मेरे भाई की हत्या कर दी है। श्रीकृष्ण पर चोरी और हत्या का कलंक लग गया। श्रीकृष्ण आरोप को गलत साबित करने के लिए जंगल की ओर चल दिए। जंगल में श्रीकृष्ण को शेर के पैरों के निशान दिखे।श्रीकृष्ण समझ गए कि प्रसेनजित को शेर ने मार दिया है और मणि यहीं कहीं गिर गई है। श्रीकृष्ण मणि खोजते हुए एक गुफा में पहुंच गए। गुफा में जामवंत रहते थे। श्रीकृष्ण ने मणि मांगी तो जामवंत ने नहीं दी। इसके बाद दोनों का युद्ध हुआ। युद्ध में श्रीकृष्ण जीत गए। इसके बाद जामवंत ने मणि श्रीकृष्ण को दे दी और अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भी भगवान के साथ कर दिया। द्वारका लौटकर श्रीकृष्ण ने वह मणि जामवंत से लेकर सत्राजित को दे दी और पूरी सच्चाई बता दी।

अंतर्मन

आज की पाती

अनिद्रा रोग की जकड़ में 2037 का भारत

पाश्चात्य जीवन शैली की नकल में वर्तमान भारतीय संस्कृति इतनी भ्रष्ट व बेहाल हो चुकी है कि भरोसा नाम की कोई चीज ही नहीं बची। भारत सारी दुनिया में विश्व गुरु बनने की राह पर प्रगतिशील है, मगर विकास यात्रा के नाम पर विदेशों का कचरा भी भरा जा रहा है। इस बदलते हुए वातावरण में आदमी का जीवन स्तर पहले से ज्यादा बेहतर हुआ, मगर हम असली-नकली का अंतर करने में फेल हो रहे हैं। हर माल का ड्यूलीकेट पहुंच गया है। आज के दौर में हर इनसान का आहार तक नकली हो गया है, फिर धर्म की रक्षा कौन करेगा? नई-नई बीमारियां फैल रही हैं, कोरोना के बाद अब आशंका है कि अनिद्रा की बीमारी वैश्विक महामारी का रूप धारण कर लेगी। वर्ष 2037 तक भारत भी इससे प्रभावित होगा, अतः इसकी तैयारियां के लिए अभी से सरकार योजना का निर्माण शुरू हो जाना चाहिए। *-प्रकाश सोनकर, गरियाबंद*

ट्रेंड

रक्षा क्षेत्र में प्रतिबद्धता

लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एलसीए) के लिए पहला टिपर फ्लाइटलेस हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) को सौंपा गया। यह तेजस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की प्रगति और रक्षा क्षेत्र में सटीकता की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

-राजनाथ सिंह, रक्षामंत्री

पौधरोपण में योगदान दें

प्रतिदिन पौधरोपण के संकल्प के तहत मैं आज अंधाधार स्थित स्मार्ट सिटी पार्क में पौधा रोपा। पेड़-पौधे प्रकृति की अनमोल धरोहर व पर्यावरण के संरक्षक हैं। आप भी विभिन्न अवसरों पर पौधरोपण कर धरती को हरा-भरा बनाने में योगदान दें।

-विष्णुदेव साय, केंद्रीय कृषि मंत्री

वोटर लिस्ट में गड़बड़ी

महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों को लेकर मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक महीने से अधिक हो गया है। मगर चुनाव आयोग ने लेकर सुलझ आयोग ने हमने जो मांगे की थीं, वे अब तक पूरी नहीं की गई हैं। लगता आज भी वैसे ही बने हुए हैं।

-राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद

भारतीय टीम को बधाई

भारतीय क्रिकेट टीम ने फाइनल में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी को जीतकर मां भारती का मान बढ़ाया है। इस ऐतिहासिक सफलता के लिए पूरी टीम को बधाई!

-रिजेजू सिंह, बीकानेर

करंट अफेयर

उ. कोरिया ने समुद्र में दागी कई बैलिस्टिक मिसाइलें

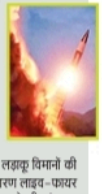

दक्षिण कोरिया की सेना ने दावा किया है कि उत्तर कोरिया ने सोमवार को कई बैलिस्टिक मिसाइलें समुद्र में दागी है। दक्षिण कोरिया और अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू होने के कुछ घंटों बाद यह मिसाइलें दागी गयीं। उत्तर कोरिया इस अभ्यास को अतिक्रमण के पूर्वाभ्यास के तौर पर देखता है।

दक्षिण कोरिया के जवाइंट चीफस ऑफ स्टाफ ने बताया कि उत्तर कोरिया के झांगझे प्रांत से मिसाइल दागी गयीं, लेकिन उन्होंने यह खुलासा नहीं किया कि मिसाइलें कितनी दूर तक गईं। दक्षिण कोरिया और अमेरिकी सैन्य बलों ने अपना वार्षिक फ्रीडम शील्ड कमांड पोस्ट अभ्यास शुरू किया है जो ग्यारह दिनों तक चलेगा।

हालांकि, इससे पहले दक्षिण कोरिया की वायुसेना के दो लड़ाकू विमानों की गलती से नागरिक क्षेत्र में बमबारी करने की घटना के कारण लाइव-फायर प्रशिक्षण को रोक दिया गया था। दक्षिण कोरिया ने इस मामले की जांच की। उत्तर कोरिया ने इन सैन्य अभ्यासों की कड़ी निंदा करते हुए एक सरकारी बयान में इसे खतरनाक बताया।

ऑफ बीट

सिक्स-पैक एब्स हासिल करना कठिन क्यों है

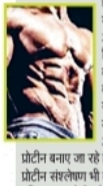

बहुत से लोग कुछ ऐसा हासिल करने की उम्मीद में जिम जाना शुरू करते हैं, जिसे लंबे समय से स्वास्थ्य और फिटनेस के पैमाने के रूप में देखा जाता रहा है और वह है सिक्स-पैक एब्स अर्थात पेट की उभरी हुई मांसपेशियां। किसी भी मांसपेशी के निर्माण के लिए, आपको उच्च प्रोटीन युक्त आहार खाने के साथ-साथ नियमित रूप से वजन प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। वजन प्रशिक्षण मांसपेशी प्रोटीन संश्लेषण नामक प्रक्रिया को बढ़ावा देकर काम करता है। चूंकि प्रोटीन हमारी मांसपेशियों के निर्माण खंड हैं, मांसपेशी प्रोटीन संश्लेषण यह सुनिश्चित करता है कि पुराने प्रोटीन जो टूट जाते हैं और हटा दिए जाते हैं, उन्हें बदलने के लिए लगातार नए प्रोटीन बनाए जा रहे हैं। जब आप प्रोटीन युक्त भोजन खाते हैं तो मांसपेशियों में प्रोटीन संश्लेषण भी बढ़ जाता है। लेकिन यदि आप पहले से कुछ वजन प्रशिक्षण करते हैं, तो यह वृद्धि अधिक होगी और यदि आपने कोई व्यायाम नहीं किया है तो उसकी तुलना में लंबे समय तक रहेगा। यदि आप वजन प्रशिक्षण करते हैं और प्रति भोजन कम से कम 20 ग्राम प्रोटीन खाते हैं, तो यह मांसपेशी प्रोटीन संश्लेषण को अधिकतम करता है।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से **hbcgpati@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

कोई भी तानाशाह व आक्रमणकारी हथियारों के बल पर जनता को हमेशा बंदी बनाकर नहीं रख सकता। -जे माइकल स्ट्रैंजिन्स्की

एफएओ की हालिया रिपोर्ट में गेहूं और धान के उत्पादन में बढ़ोतरी की जो संभावनाएं व्यक्त की गई हैं, वे वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिहाज से अहम हैं। लेकिन इन आंकड़ों का संदेश यही है कि सरकारें, किसान व उपभोक्ता मिलकर सुनिश्चित करें कि यह प्रचुरता हर थाली में भोजन के रूप में भी दिखे।

अनाज और संदेश

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) की हालिया रिपोर्ट में गेहूं और धान के वैश्विक उत्पादन को लेकर जो संभावनाएं व्यक्त की गई हैं, वे वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ खाद्य सुरक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण हैं। ऐसे वक्त में, जब एक तरफ भयभीत करने वाले मौसमी बदलाव और वैश्विक युद्धों की वजह से आपूर्ति मुंहबाएं बाधित हैं, तो दूसरी तरफ, अमेरिका द्वारा पारस्परिक टैरिफ लागू किए जाने की घोषणा ने भी पूरी दुनिया को अनिश्चय में डाला हुआ है, तब एफएओ की रिपोर्ट में गेहूं के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में एक फीसदी की बढ़ोतरी और वैश्विक धान उत्पादन के भी इस वर्ष रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने का अनुमान राहत देता है। अच्छी बात यह है कि गेहूं और धान जैसे बुनियादी अनाजों की आपूर्ति में वृद्धि से कीमतों में स्थिरता बनी रह सकती है, जिससे उपभोक्ताओं को भी यकीनन राहत मिलेगी। रिपोर्ट की यह टिप्पणी उल्लेखनीय है कि लगातार जारी संघर्ष और असुरक्षा की स्थितियां गंभीर खाद्य असुरक्षा को जन्म दे रही हैं। ऐसे में यह सुनिश्चित किया जाना बेहद जरूरी है कि इस उत्पादन का लाभ खासकर उन 45 देशों, जिनमें एशिया के नौ देश शामिल हैं, तक सही ढंग से पहुंचे। एफएओ की ताजा रिपोर्ट हाल ही में जारी विश्व बैंक व अमेरिका के इडाहो विश्वविद्यालय की उस रिपोर्ट की भी पुष्टि करती है, जिसके अनुसार 1960 के दशक से ही दुनिया भर में कृषि उपज में लगभग समान दर से वृद्धि जारी है। इससे पिछले कुछ दशकों से जताई जा रहीं उन चिंताओं पर भी विराम लगेगा, जो बताती थीं कि बढ़ती आबादी की जरूरतों के मद्देनजर दुनिया भर में फसलों के उत्पादन में कमी या स्थिरता आने के आसार हैं। भारत, जो दुनिया के अग्रणी गेहूं और धान उत्पादकों में से एक है, के लिए भी ये आंकड़े महत्वपूर्ण हैं। वैश्विक उत्पादन में वृद्धि का असर देश के निर्यात, किसानों की आय और सरकारी खरीद नीतियों पर पड़ता ही है। उत्पादन में वृद्धि उत्साहजनक है, लेकिन खासकर भारत के संदर्भ में देखें, तो

अनियमित मानसून, हीट वेव और जल संकट गेहूं व धान उत्पादन को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में सरकार को समुचित जल प्रबंधन, उच्च गुणवत्ता वाले बीज और आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देना होगा। बढ़ता उत्पादन भारतीय संदर्भ में भंडारण और वितरण तंत्र की खामियों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत को भी इंगित करता है, क्योंकि हर साल लाखों टन अनाज व्यवस्थागत खामियों के चलते बर्बाद होता है। लिहाजा एफएओ की रिपोर्ट में आंकड़ों से बढ़कर एक संदेश है। सरकारों, किसानों व उपभोक्ताओं को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि यह प्रचुरता हर थाली में भोजन, कम भुखमरी और भावी पीढ़ियों के लिए सक्षम धरती के रूप में भी दिखे, तभी इसका स्थायी महत्व होगा।

आखिर औरंगजेब पर गुस्सा क्यों?

कोई भी समझदार व्यक्ति इस्लामी आक्रांताओं के कृत्यों के लिए वर्तमान भारतीय मुसलमानों को जिम्मेदार नहीं ठहराएगा। परंतु तब के आक्रमणकारियों से स्वयं को जोड़कर उनका गुणगान करना क्या स्वीकार्य हो सकता है?

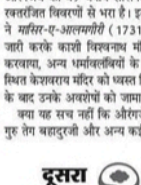

बलबीर पुंज
भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष एवं पूर्व राज्यसभा सदस्य

क्या किसी भी सभ्य समाज के लिए मुगल आक्रांता औरंगजेब, तानाशाह हिटलर और गांधीजी का हत्यारा गोडसे गौरव हो सकते हैं? जब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र में विधायक अबू आसिम आजमी ने औरंगजेब का महिमामंडन किया, तब वह केवल अपना व्यक्तिगत मत ही प्रकट नहीं कर रहे थे। उनका वक्तव्य भारतीय उपमहाद्वीप में व्याप्त विषाक्त मानस का न केवल प्रतिनिधित्व कर रहा था, अपितु इसने हिंदू-मुस्लिम संबंधों में शताब्दियों से चले आ रहे तनाव के कारणों को भी कुरेद दिया। यह चिंतन ही समरसता, बहुलतावाद, पंथनिरपेक्षता व सह-अस्तित्व युक्त समाज को सीधी चुनौती है। इसी मानसिकता के कारण भारत का रक्तरंजित विभाजन हुआ और पाकिस्तान-बांग्लादेश अस्तित्व में आए?

आजमी और उनके मानसबंधुओं के अनुसार, 'औरंगजेब क्रूर शासक नहीं था। उसकी लड़ाई राजकाज के लिए थी, न कि मजहबी। उसने कई हिंदू मंदिर बनवाए।' इस्लामी वादशाहों की आत्मकथाओं और समकालीन इतिहासकारों द्वारा कलमबद्ध वृत्तांतों से स्पष्ट है कि आठवीं शताब्दी के बाद भारत में मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा तलवार के बल पर स्थानीय लोगों का धर्मांतरण, नरसंहार, शोषण, पुजास्थलों का विध्वंस और उनके मानबिंदुओं का अपमान-अपविश्वीकरण-इस्लामी दृष्टिकोण से गर्व योग्य कृत्य थे। इसलिए औरंगजेब का 49 वर्षीय शासनकाल कोई अपवाद नहीं था। इतिहास ऐसे रक्तरंजित विवरणों से भरा है। इस्लामी दरबारी मोहम्मद साकी मुस्तैद खान ने *मासिर-ए-आलमगीरी* (1731) में लिखा था कि औरंगजेब ने फरमान जारी करके काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद का निर्माण करवाया, अन्य धर्मावलंबियों के जबरन धर्मांतरण का आदेश दिया, मथुरा स्थित केशवराय मंदिर को ध्वस्त किया और जोधपुर में कई मंदिरों के विध्वंस के बाद उनके अवशेषों को जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफना दिया।

क्या यह सच नहीं कि औरंगजेब ने इस्लाम नहीं अपनाने पर नौवें सिख गुरु तेग बहादुरजी और अन्य कई सिखों की हत्या करवाई, तो वीर छत्रपति

संभाजी महाराज को अमानवीय यातनाएं देकर मारा? यदि मजहबी पक्ष छोड़ भी दें, तो एक व्यक्ति के रूप में औरंगजेब कैसा था? सत्ता-लिप्सा में जहां उसने अपने पिता शाहजहां को कैद किया, वहीं अपने तीनों भाइयों-दारा शिकोह, शाहशुजा और मुराद की निर्मम हत्या करवा दी। क्या ऐसा क्रूर-हृदयविहीन व्यक्तित्व किसी भी सभ्य समाज के लिए आदर्श हो सकता है? यह तीक्ष्ण है कि मुस्लिम आक्रांताओं ने अथाह संपत्ति लूटने के इरादे से भारत पर हमले किए, परंतु इनके पीछे मजहबी प्रेरणा भी थी। इतिहास में इसके कई प्रमाण हैं, जिनमें से एक वर्ष 1398 में भारत पर हमला कर हजारों-लाखों निरपराधों को मारने वाला तैमूर है। बकौल *तुजुक-ए-तैमूरी* में तैमूर ने कहा था, 'मेरे हिंदुस्तान आने के दो उद्देश्य हैं। पहला-काफिरों से जिहाद करना और सवाब कमाना। दूसरा-काफिरों की दौलत लूटना, क्योंकि यह मुसलमानों के लिए मां के दूध की तरह जायज है।' सोचिए, देश के एक प्रसिद्ध फिल्मी परिवार ने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा है।

क्या इस्लामी आक्रांताओं और हिंदू-सिख शासकों में संघर्ष केवल सत्ता का था? इस पर दावा किया जाता है कि मुस्लिम शासकों के दरबारों में हिंदू और हिंदू-सिख शासकों के दरबारों में मुस्लिम थे। यदि इस कुतर्क को मानें, तो अंग्रेजों के लिए लड़ने वाले अधिकांश सैनिक और क्रांतिकारियों को फांसी पर लटकाने वाले कौन थे? जलियांवाला बाग में जनरल डायर के आदेश पर निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाने वाले अंग्रेज नहीं थे। क्या यह कहना ठीक होगा कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम देश की आजादी के बजाय सत्ता का संघर्ष था? बार-बार दोहराया जाता है कि मुगलों ने मंदिरों का निर्माण करवाया। संभव है कि कुछ मामलों में ऐसा हो। परंतु क्या इससे उनके असंख्य अपराध मिट जाते हैं? आक्रामणकारी ब्रितानियों ने भी अपनी औपनिवेशिक रणनीति के अंतर्गत कुछ मंदिरों के निर्माण-जीर्णोद्धार होने दिए। वे देश में रेल और टेलीग्राफ लेकर आए, तो बिना किसी स्थानीय पूजास्थल को ध्वस्त किए भव्य भवनों का निर्माण करवाया। इन सबके बावजूद अंग्रेजों की भूमिका एक कुटिल विदेशी आक्रमणकारियों की थी, जिन्होंने भारत की प्रज्ञा और अगाध संपदा को बेदर्दी से नष्ट किया।

इस्लामी आक्रांताओं के यशगान में एक भ्रामक तर्क यह भी है कि यदि वे इतने ही क्रूर और मजहबी थे, तो देश में लाखों मंदिर और करोड़ों हिंदू कैसे बचे? मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारतीय उपमहाद्वीप से इस्लाम-पूर्व संस्कृति व उसके प्रतीकों को मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इसमें वे आंशिक रूप से सफल भी हुए। बीते एक हजार वर्षों में भारतीय उपमहाद्वीप के जिन क्षेत्रों में सनातन संस्कृति का ह्रास हुआ, वहां बहुलतावाद, पंथनिरपेक्षता व सह-अस्तित्ववाद ने दम तोड़ दिया। हिंदू-बौद्ध-सिख विहीन अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश इसके ज्वलंत प्रमाण हैं। यदि खंडित भारत का हिंदू चरित्र आज भी अक्षुण्ण है, तो इसका श्रेय महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, राणा सांगा, महाराजा छत्रसाल, सिख गुरुओं की परंपरा से लेकर अनेकों वीरों और साधु-संतों को जाता है, जिन्होंने भारत के अस्तित्व की रक्षा हेतु निरंतर प्रतिकार किया। क्या कोई बता सकता है कि उत्तर-पश्चिम भारत के शत्त-प्रतिशत प्राचीन मंदिर अपने मूल स्वरूप में क्यों नहीं हैं? यहां जो भी पुरातन पूजास्थल हम देखते हैं, उसके भवन सतत सांस्कृतिक पुनरुद्धार के कारण 200-250 वर्ष पुराने हैं।

जिस वैचारिक नींव पर पाकिस्तान खड़ा है, उसकी और मुस्लिम आक्रांताओं की प्रेरणा एक है। पाकिस्तानी स्कूली पाठ्यक्रमों में इस्लामी आक्रांता मुहम्मद बिन कासिम को 'पहला पाकिस्तानी', तो सिंध को पहला 'इस्लामी प्रांत' बताया जाता है, क्योंकि कासिम ने वर्ष 711-12 में हिंदू राजा दाहिर द्वारा शासित तत्कालीन सिंध पर हमला किया था। इसी मानसिकता के कारण पाकिस्तान में मिसाइलों-युद्धपोतों के नाम-गजनी, गौरी, बाबर, अब्दाली, टीपू सुल्तान को समर्पित हैं। कोई भी समझदार व्यक्ति इस्लामी आक्रांताओं के कृत्यों के लिए वर्तमान भारतीय मुसलमानों को जिम्मेदार नहीं ठहराएगा। परंतु क्या आज के मुसलमानों को इस्लामी आक्रमणकारियों से स्वयं को जोड़कर इस पर गौरव करना चाहिए? यदि हिटलरवादियों-यहूदियों के आपसी संबंध मधुर नहीं हो सकते और गांधीजी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की बड़ाई से क्रोध उत्पन्न होता है, तो भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात करने वाले औरंगजेब जैसे क्रूर आक्रांताओं का गौरवगान कोई सभ्य समाज कैसे स्वीकार कर सकता है?

edit@amarujala.com

जीवन धारा

जोसेफ मर्फी

अवचेतन मन सुझाव के प्रति बहुत ग्रहणशील होता है। जब सकारात्मक विचार अवचेतन क्षेत्र में उतरते जाते हैं, तो ये अपनी तरह के फल देते हैं तथा आप संतुलित, शांत और सद्भावनापूर्ण बन जाते हैं।

जिससे डरते हैं, वही करें भय खत्म हो जाएगा

मेरे एक विद्यार्थी को व्यावसायिक सम्मेलन के वार्षिक समारोह में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था। उसने मुझे बताया कि हजार लोगों के सामने भाषण देने के बारे में सोचकर ही वह दहशत में आ गया था, जिनमें कई विशेषज्ञ भी शामिल थे। उसने अपने डर पर इस तरह विजय पाई- कई रातों तक वह लगभग पांच मिनट तक कुर्सी पर शांति से बैठा। उसने खुद से धीरे से और सकारात्मक रूप से कहाः मैं इस डर पर विजय पाने वाला हूं। मैं इस पर अभी विजय पा रहा हूं। मैं संतुलन और विश्वास से बोलता हूं। इस तरीके से उसने मस्तिष्क के एक निश्चित नियम से कार्य करवाया। जब समय आया, तो उसने अपने डर पर विजय पाते हुए बहुत शानदार भाषण दिया।

अवचेतन मन सुझाव के प्रति बहुत ग्रहणशील होता है। यह सुझाव द्वारा नियंत्रित होता है। जब आप अपने मस्तिष्क को स्थिर कर लेते हैं और शिथिल हो जाते हैं, तो आपके चेतन मन के विचार आपके अवचेतन में उतर जाते हैं। यह प्रक्रिया पतासरण जैसी ही है, जिसमें छिद्र वाली झिल्लियों द्वारा विभाजित द्रव आपस में मिल जाते हैं। जब ये सकारात्मक बीज या विचार अवचेतन क्षेत्र में उतरते जाते हैं, तो वे अपनी तरह के फल देते हैं तथा आप संतुलित, शांत और सद्भावनापूर्ण बन जाते हैं। कहा गया है कि डर लोगों का सबसे बड़ा शत्रु है। डर ही सफलता, बीमारी और कमजोर मानवीय संबंधों का कारण होता है। लाखों-करोड़ों लोग अतीत, भविष्य, बुढ़ापे, पागलपन और मौत से डरते हैं। लेकिन डर आपके दिमाग का एक विचार है। यानी आप अपने ही विचार से डरे हुए हैं। कोई छोटा बच्चा डर के मारे दहशत में आ सकता है, जब उसका साथी कहता है कि बिस्तर के नीचे एक राक्षस है, जो रात में उसे पकड़ लेगा। लेकिन जब माता-पिता लाइट जलाकर दिखाते हैं कि कोई राक्षस नहीं है, तो उसका डर दूर हो जाता है। बच्चे के दिमाग का डर उतना ही असली था, जितना कि असली राक्षस होने पर होता।

उसके मन के झूठे विचार का उपचार हो गया। जिस चीज का उसे डर था, वह मौजूद ही नहीं थी। इस तरह से आपके अधिकांश डर वास्तविक नहीं होते हैं। वे महज दुष्ट छायाओं का समूह होते हैं और छायाएं असली नहीं होती हैं। इसलिए वह काम करें, जिससे आप डरते हों। उन्नीसवीं सदी के महान दार्शनिक और कवि राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा था, 'जिस काम से आप डरते हों, उसे पूरा करें, डर की मौत तय है।' एक समय में भी श्रोताओं के सामने खड़े होकर भाषण देने से बुरी तरह घबराता था। मैंने इमर्सन की सलाह पर अमल करके इस डर पर विजय पाई। अंदर से कांपने के बावजूद मैं श्रोताओं के सामने बोलने लगा। धीरे-धीरे मेरा डर कम होने लगा और आखिरकार मैं इसमें आनंद लेने लगा। इसके बाद तो यह स्थिति आ गई कि मैं भाषण देने के लिए उत्सुक होने लगा। मैंने वह काम किया, जिसे करने से मैं डरता था और डर की मौत तो होनी ही थी।

डर को ललकारें

जीवन में जिस चीज से भी डर लगे, अपने भीतर जोर से कहो, मैं तुम पर विजय पाने वाला हूं। मन की शक्तियों से तुम पर विजय पा लूंगा। अगर पानी से डर लगता है, तो पानी में उतर जाओ। तैरना सीखो। पानी पर विजय पाने के लिए अपनी आंतरिक शक्तियों का प्रयोग करो। ये आंतरिक शक्तियां आत्मविश्वास से भर देंगी और आप अपने लक्ष्य को पा लेंगे।

सूत्र

दूसरा पहलू

भारत में पहली बार हुई गणना के अनुसार देश के आठ राज्यों की 28 नदियों में 6,327 डॉल्फिन का पता चला है।

देश में दुर्लभ डॉल्फिन का बढ़ता कुनबा

भारतीय नदियों में जलीय जीव 'डॉल्फिन' की संख्या में वृद्धि की सुखद खबर चर्चाओं में है। इससे उम्मीद जगी है कि लोग अब दुर्लभ डॉल्फिन को किताबों, टीवी और यूट्यूब के अलावा वास्तविक रूप से भारतीय नदियों में ही साक्षात दीदार कर सकेंगे। देश के आठ राज्यों की 28 बड़ी नदियों में कराए गए सर्वेक्षण-2024 से कुल 6,327 डॉल्फिनों के होने का पता चला है। उत्तर प्रदेश की नदियों में सर्वाधिक 2,397 डॉल्फिन मौजूद हैं। एक सुखद खबर यह है कि डॉल्फिनों की संपूर्ण संख्या में 20 प्रतिशत मादा डॉल्फिन हैं, जिनसे अगले कुछ वर्षों में डॉल्फिन की संख्या में और इजाफा होने की उम्मीद जगी है।

रमेश ठाकुर

इस आकर्षक और दुर्लभ किस्म की मछली के दीदार के लिए लोग विदेश तक जाते हैं और बड़ी रकम देकर उसे देखते हैं, लेकिन अब भारत में भी आसानी से इनके दीदार हो सकेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय वन्य बोर्ड की 71वीं बैठक हुई, जिसमें उन्होंने डॉल्फिन गणना की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर यह सुखद खबर देशवासियों से साझा की। डॉल्फिन की गणना के लिए 8,500 किलोमीटर से अधिक जलीय क्षेत्र का परीक्षण किया गया। इस कार्य में वन्य बोर्ड के 1,200 कर्मचारियों ने सहभागिता निभाई, जिस पर 25 करोड़ रुपये का खर्च आया। डॉल्फिन की गणना भारत में पहली बार कराई गई है। भारत सरकार ने सन 2009 में गंगा डॉल्फिन को 'राष्ट्रीय जलीय जीव' घोषित किया था। उत्तर प्रदेश के अलावा, भारत में 2,220 डॉल्फिन पाई गईं। वहीं, पश्चिम बंगाल में 815, तो असम में 635 डॉल्फिन मौजूद हैं।

प्रयागराज में हाल में संपन्न हुए महाकुंभ के दौरान भी कई श्रद्धालुओं को डॉल्फिन के दर्शन हुए। गणना में त्रिवेणी संगम में करीब 96 डॉल्फिन बताई गई हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 'गंगेय डॉल्फिन' को राज्य का जलीय जीव घोषित किया हुआ है। मुंबई के समुद्र में डॉल्फिनों की संख्या अच्छी हुआ करती थी, लेकिन गणना में संख्या उतनी नहीं आई, जितने की उम्मीद थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक, वहां डॉल्फिनों का अवैध शिकार सबसे ज्यादा किया जाता है। इस अदृभुत जलीय जीव को बचाने के लिए शिकारियों पर अंकुश लगाने के साथ ही नदियों को साफ करना होगा, जल प्रदूषण पर नियंत्रण करना होगा और पानी में मीठेपन की मात्रा बढ़ाने के लिए नई आधुनिक तकनीकों को अपनाना होगा।

उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 2,397 डॉल्फिन मिली हैं। प्रयागराज में हाल में संपन्न हुए महाकुंभ के दौरान भी कई श्रद्धालुओं को डॉल्फिन के दर्शन हुए, क्योंकि गंगा में त्रिवेणी संगम में करीब 96 डॉल्फिन बताई गई हैं।

आंकड़े

अरबपति

दुनिया भर में पैसे वालों की संख्या बढ़ रही है। ताजा आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका अरबपतियों के मामले में सबसे ऊपर है।

अमेरिका	813
चीन	406
भारत	200
जर्मनी	132
रूस	120

अरबपतियों की संख्या | स्रोत: Forbes Billionaires List 2024

स्वामी आत्मप्रसाद गृहस्थ जीवन जी रहे थे। कुछ समय बाद सब त्याग कर गुरु की सेवा में पहुंचे। अंत में उन्होंने कुंभ के अवसर पर प्रयाग में समाधि लगा ली।

शिवोऽहम की ध्वनि

स्वामी आत्मप्रसाद उदासीन का जन्म पंजाब के होशियारपुर जिले के अहियारपुर नामक नगर में हुआ था। बचपन से ही उन्हें संत-महात्माओं के सत्संग से प्रेम था। कुंभ के अवसर पर वह हरिद्वार गए और वहां उन्होंने सच्चखंड-साधुबेलातीर्थ के द्वितीय गद्दीधर स्वामी हरिप्रसाद महाराज के दर्शन किए।

स्वामी हरिप्रसाद महाराज के उपदेशों का उन पर इतना प्रभाव पड़ा कि वह उन्हीं की सेवा में रहने का विचार करने लगे। लेकिन संयोग नहीं बना और किसी कारण से उन्हें घर लौट आना पड़ा। घर आकर स्वामी आत्मप्रसाद गृहस्थ जीवन का पालन करने लगे। कुछ समय बाद संसार के बंधन से विमुक्त होने के लिए उनके मन में ऐसी उत्कट अभिलाषा जगी कि वह सब मोह त्याग कर स्वामी हरिप्रसाद जी महाराज की सेवा में पहुंचे। गुरुदेव ने उनकी सेवा, सुशीलता आदि से प्रसन्न होकर उन्हें उदासीन-संप्रदाय की विधि अनुसार दीक्षा दी। दीक्षित हो जाने के बाद स्वामी आत्मप्रसाद गुरुदेव की आज्ञा लेकर ऋषिकेश पहुंचे और वहां उन्होंने कई वर्षों तक तितिक्षापूर्वक योगाभ्यास किया। वहां स्वामी आत्मप्रसाद जी सिंधी महात्मा नाम से प्रसिद्ध हुए। स्वामी जी ने चारों धाम और सातों पुरियों की यात्रा की। स्वामी जी फिर सक्खर लौटे और अपने गुरु के कहने पर कई लोगों की मदद की। अंत में स्वामी जी कुंभ के अवसर पर एक बार प्रयाग पहुंचे और वहीं पर 'शिवोऽहम्' की ध्वनि करते हुए समाधि लगा ली।

अंतर्यात्रा
संकलित

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 17 दिसंबर, 1965

जासूसी कर रहे पाकिस्तानी विमान को मार गिराया

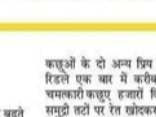

पाकिस्तानी विमान मार गिराया

भारतीय वायुसेना ने भारतीय प्रदेश में घुसे एक पाकिस्तानी ऑस्टर विमान को गोली मारकर गिरा दिया। विमान भारतीय प्रदेश में जासूसी कर रहा था। प्रदेश में घुस कर हमारे ठिकानों की फोटो ले रहा था।

देर से ही सही, शुरू तो हुआ अरिबाडा

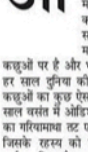

धरती के बढ़ते तापमान से समुद्री जल भी अछूता नहीं है और गरम जल के कारण ओलिव रिडले कछुओं के नैसर्गिक पर्यावास व भोजन पर असर पड़ा है।

पंकज चतुर्वेदी

पर्यावरण

आधा फरवरी बीतने के बाद ही मौसम गरम होने लगा था, तो जीव प्रेमियों के माथे पर चिंता की लकीरें आ गईं, कहीं इस साल हम 'चमकार' के साक्षी बनने से तो न रह जाएंगे? मान्यता है कि धरती का अस्तित्व कछुओं पर है और भारत में ओडिशा के समुद्री तट पर हर साल दुनिया की दुर्लभ प्रजाति के ओलिव रिडले कछुओं का कुछ ऐसा ही विलक्षण समागम होता है। हर साल वसंत में ओडिशा के समुद्र तट पर केंद्रपाड़ा जिले का गरियामाथा तट एक ऐसी घटना का साक्षी बनता है, जिसके रहस्य को सुलझाने के लिए दुनिया भर के पर्यावरणविद और पशु प्रेमी बेचैन हैं।

हजारों किलोमीटर की यात्रा कर लाखों कछुए यहां अंडे देने के लिए आते हैं। मादा अंडे देकर फिर समुद्र यात्रा पर निकल जाती हैं। कोई 50 दिन बाद इन अंडों से निकले बच्चे उसी समुद्री मार्ग से फिर हजारों किलोमीटर दूर अपनी मां के पास चले जाते हैं। यही नहीं ये शिशु कछुए लगभग 30 साल बाद जब प्रजनन के योग्य होते

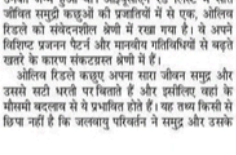

हैं, तो ठीक उसी जगह पर अंडे देने के लिए आते हैं, जहां उनका जन्म हुआ था। आईयूसीएन रेड लिस्ट में सात जीवित समुद्री कछुओं की प्रजातियों में से एक, ओलिव रिडले को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। ये अपने विशिष्ट प्रजनन पैटर्न और मानवीय गतिविधियों से बढ़ते खतरे के कारण संकटग्रस्त श्रेणी में हैं।

ओलिव रिडले कछुए अपना सारा जीवन समुद्र और उससे सटी धरती पर बिताते हैं और इसीलिए यहां के मौसमी बदलाव से ये प्रभावित होते हैं। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि जलवायु परिवर्तन ने समुद्र और उसके जैविक जगत पर भीषण कुप्रभाव डाला है। धरती के बढ़ते तापमान से समुद्री जल भी अछूता नहीं है और गरम जल के कारण ओलिव रिडले कछुओं के नैसर्गिक पर्यावास और भोजन पर असर पड़ा है। समुद्र का जलस्तर बढ़ने से समुद्री कछुओं को अंडे देने के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढना मुश्किल हो सकता है। सबसे बड़ी बात मौसम के बदलाव से कछुओं में लैंगिक असमानता भी उपज रही है। भ्रूण के विकास के दौरान तापमान यह निर्धारित करता है कि अंडे से नर कछुआ निकलेगा या मादा। उच्च तापमान के कारण मादा कछुआ अधिक पैदा होती हैं, जबकि नर कम तापमान के कारण। इसलिए ओलिव रिडले के समुद्र तटों पर रेत के घरौंदे का तापमान बढ़ने से अंडे से निकले बच्चों का लिंग अनुपात लगभग पूरी तरह से मादा हो सकता है। नतीजतन, भविष्य में कछुओं की प्रजनन में समस्या हो सकती है।

यह आश्चर्य ही है कि ओलिव रिडले कछुए हजारों किलोमीटर की समुद्र यात्रा के दौरान भारत में ही गोवा, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश के समुद्री तटों से गुजरते हैं, लेकिन अपनी वंश-वृद्धि के लिए वे अपना आवास बनाने के लिए ओडिशा के समुद्र तटों की रेत को ही चुनते हैं। समंद रहे कि दुनिया भर में ओलिव रिडले कछुए के घरौंदे महज छह स्थानों पर ही पाए जाते हैं और इनमें से तीन स्थान ओडिशा में हैं। ये कछुए कोस्टारिका में दो व मेक्सिको में एक स्थान पर प्रजनन करते हैं। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले का गरियामाथा समुद्री तट दुनिया का सबसे बड़ा प्रजनन-आशियाना है। इसके अलावा रुसिकलया और देवी नदी के समुद्र में मिलनस्थल इन कछुओं के दो अन्य प्रिय स्थल हैं। एक मादा ओलिव रिडले एक बार में करीब डेढ़ सौ अंडे देती है। ये चमत्कारी कछुए हजारों किलोमीटर की यात्रा के बाद समुद्री तटों पर रेत खोदकर अंडे रखने की जगह बनाते हैं। इस प्रक्रिया को 'मास नेस्टिंग या अरिबाडा' कहते हैं। ये अंडे 60 दिनों में टूटते हैं और उनसे छोटे-छोटे कछुए निकलते हैं। ये नन्हे जीव रेत पर घिसटते हुए समुद्र में उतर जाते हैं। एक लंबी यात्रा के लिए इस विश्वास के साथ कि ये वंश-वृद्धि के लिए फिर से ठीक इसी स्थान पर आएंगे-30 साल बाद।

इस साल ओडिशा के तट पर कछुओं का आगमन कुछ देर से 5 मार्च को गत हुआ। एक रात में ही लगभग 78 हजार मादा कछुओं ने अपने घरौंदे बनाकर अंडे देना शुरू कर दिया। यह क्रम करीब दस दिन चलेगा। बदलते मौसम से तो कछुए परेशान हैं ही, इनको सबसे बड़ा नुकसान मछली पकड़ने वाले ट्रॉलरों से होता है। बीते चार महीनों में ओडिशा के वन विभाग ने 299 मछुआरों को नियम विरुद्ध प्रतिबंधित क्षेत्र में मछली पकड़ने के आरोप में गिरफ्तार भी किया। प्रतिबंधों के बावजूद क्लीकेल और चाईलैंड के ट्रॉलर, तो खुलेआम मछलियों के साथ ही कछुओं का शिकार कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त 'फेनगुई' के बढ़ते प्रचलन ने भी कछुओं को शामत ला दी है। बहुत से अध्ययन बता रहे हैं कि ओलिव रिडले की प्रजनन क्षमता और जीवित रह जाने वाले जीवों की संख्या हर साल घट रही है। कछुए पृथ्वी की पारिस्थितिकी के संतुलन में अहम भूमिका निभाते हैं, वैसे भी ओलिव रिडले कछुए प्रकृति की चमत्कारी नियामत हैं। अभी उनका रहस्य अनसुलझा है। मानवीय लापरवाही से यदि इस प्रजाति पर संकट आ गया, तो प्रकृति पर क्या विपदा आ सकती है? इसका किसी को अंदाजा नहीं है।

हिन्दुस्तान
1936 से
निर्भय • निष्पक्ष • निर्बाध

सावधानी का समय

चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारतीय क्रिकेट टीम की जीत के बाद मध्य प्रदेश के महू में जो तनाव पैदा हुआ, वह दुखद भी है और शर्मनाक भी। क्रिकेट में सबकी अपनी-अपनी पसंद होती है, पर देश की टीम जब खेल रही हो, तो पूरे संयम के साथ हमारा व्यवहार होना चाहिए। किसी देश की टीम का समर्थन अपनी जगह है, पर अपने देश की टीम का विरोध तो कोई भी नागरिक करना नहीं चाहेगा। महू में भारत की जीत के बाद निकले जुलूस पर जो पथराव हुआ, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। पुलिस ने उचित ही कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। निश्चित रूप से पुलिस यह भी जांच करेगी कि क्या विजय जुलूस ने जीत की खुशी में अपनी कानूनी सीमाओं का उल्लंघन किया था? अगर विजय जुलूस पर पथराव की मंशा देश विरोध से प्रेरित थी, तो दोषियों को छोड़ना नहीं चाहिए। देश की खुशी पर दुखी होने वालों की खबर लेने और सही राह पर लाने में कोई बुराई नहीं है। हां, इस पूरे प्रकरण या अपराध को सांप्रदायिक दृष्टि से देखना न केवल कानूनी दृष्टि से देखने और यथोचित सुधार लाने की जरूरत है।

सावधान रहना चाहिए कि इन दिनों किसी भी घटना को सांप्रदायिक चश्मे से देखने की परिपाटी को खूब खाद-पानी मयस्सर हो रहा है। मिसाल के लिए, दिल्ली के गांधीपुर में एक युवक की हत्या को सांप्रदायिक नजरिए से देखा जा रहा है। सांप्रदायिक कोण की वजह से तनाव ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे मामलों में पुलिस को पूरी सक्रियता के साथ दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। किसी की हत्या जघन्य अपराध है और दोषी को सख्त सजा मिलनी चाहिए। कानून-व्यवस्था संभालने वाली तमाम एजेंसियों को ध्यान रखना होगा कि अपराधी जिम्मेदार हैं, उनके परिवार या समुदाय या मजहब नहीं। तत्काल अपराधियों को जाति या धर्म देखने की जो बदनीयत मजबूत हो रही है, उससे अंततः समाज का नुकसान ही है। समस्या यह है कि संप्रदायों को अगर हमने ज्यादा महत्व दिया, तो फिर अपराध हमारे लिए महत्वहीन हो जाएंगे। यह भी अपराधी को सजा केवल अपराध के लिए मिले, किसी जाति या धर्म से उसके तालुक्क या संविधान की नजर में कोई मायने नहीं है। अपराधियों के संप्रदाय को महत्व देने का खामियाजा अंततः समाज को चुकाना पड़ता है। संप्रदाय का नाम लेकर बड़े-बड़े अपराधी नाना प्रकार के गलत कामों में लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है, मुसीबत के समय उनका संप्रदाय उनकी मदद करेगा।

> किसी भी अपराधी को सजा केवल उसके अपराध के लिए मिले, किसी जाति, समुदाय या धर्म से उसके तालुक्क का संविधान की नजर में कोई मायने नहीं है।

अफसोस, एक और तनाव इन दिनों राजनीन बनाम होली का बनाया जा रहा है। यह बेशक है कि जुमे के दिन ही होली है। यह सबके लिए खुशी का अवसर होना चाहिए। होली इस देश की एक खूबसूरती है। सूफी दरगाहों में भी होली गाने और खेलने की परंपरा किसी न किसी रूप में रही है। इस देश में असंख्य लोग मिलकर ईद और होली मनाते आए हैं, पर जो लोग किसी त्योहार का विरोध करने लगे हैं, उनकी निंदा होनी चाहिए। यह भी कहा जा रहा है कि जुम्मा साल भर आता है, पर होली एक बार। दरअसल, यह याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। होली पर कहा जाता है कि बुरा न मानो होली है, पर इसकी आड़ में किसी को जबरन रंग लगाना प्रशंसनीय नहीं है। दूसरी ओर, रंग लग जाने पर बहुत नाराज हो जाने की भी तारीफ नहीं की जा सकती। असल त्योहार तो तभी है कि हम एक दूसरे का आदर करें। परस्पर आदर की मंशा होगी, तो हर मौका खुशगवार हो जाएगा।

हिन्दुस्तान JinduStan | 75 साल पहले 11 मार्च, 1950

काश्मीर का नया प्रस्ताव

काश्मीर के बारे में भारत और पाकिस्तान के बीच गतिरोध जारी है। संयुक्त राष्ट्रीय कमीशन इस नतीजे पर पहुंच गया था कि वह आगे के लिए कोई ठस्ता नहीं निकाल सकता और इसलिए उसने अपनी जिम्मेदारी को सारी बातों सुरक्षा परिषद् के सामने रख दी थी। अब गतिरोध को खत्म करने और आगे बढ़ने का आगे बढ़ाने का दायित्व सुरक्षा परिषद् पर है। सुरक्षा परिषद् के सामने चार राष्ट्रों- ब्रिटेन, अमरीका, नार्वे और क्यूबा ने एक प्रस्ताव पेश किया है। इस प्रस्ताव में भारत और पाकिस्तान से कहा गया है कि वे पांच महीने के भीतर विसैन्यकरण के कार्यक्रम की कार्यान्वित करें। इस विसैन्यकरण का आधार जनरल मैकनाटन के प्रस्ताव के सिद्धांतों को बनाया जाने अथवा उन सिद्धांतों में रोक दिया जाने का है। जो दोनों पक्षों को मान्य नहीं। प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्रीय कमीशन को खत्म करने और उसके स्थान पर व्यक्ति को संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतिनिधि नियुक्त करने की तजवीज की गई है। यह विसैन्यकरण का कार्यक्रम बनाने में मदद देगा और उस कार्यक्रम पर अमल होने की देखभाल भी करेगा। विसैन्यकरण संबंधी समझौतों की व्याख्या भी करेगा। यह भारत और पाकिस्तान तथा सुरक्षा कौंसिल के बीच संबंध स्थापित किए जा सकेंगा, जिनसे कश्मीर का विवाद जल्दी और स्थायी तौर पर हल होने में मदद मिलेगी। सुरक्षा परिषद् इसके प्रस्ताव पर पाकिस्तान को विचार कर लेने दे और ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रस्ताव के आधार पर ऐसा सुलह निकल आयेगा, जिससे मौजूदा गतिरोध समाप्त होकर समस्या को हल करने की दिशा में आगे कार्यवाई संभव हो सकेगी।

काश्मीर के भविष्य का निर्णय जनमत संग्रह द्वारा किया जाये, इस बात पर दोनों पक्ष सहमत हैं। किन्तु जनमत संग्रह के लिए विसैन्यकरण आवश्यक है, जिससे ऐसी परिस्थितियां पैदा हो सकें कि काश्मीर के लोग बिना किसी डर या कुछ कहने के भविष्य के बारे में अपनी राय दे सकें। विसैन्यकरण किस क्रम से किया जाये, इसी बारे में भारत और पाकिस्तान के बीच गहरा मतभेद पैदा हो गया था। भारत की ओर से कहा गया था कि न केवल पाकिस्तान की फौजें कश्मीर से हटाई जाएं, बल्कि आजाद कश्मीर फौजों को भी निःशस्त्र और भंग किया जाये, ...जो एक प्रकार से पाकिस्तान की फौज का ही अंग है।

www.livehindustan.com

कनाडा में कार्नी के हाथों में कमान

विवेक काटजू | पूर्व राजनयिक

जस्टिन ट्रूडो के समय कनाडा और भारत के रिश्ते बहुत खराब हो गए थे। अब मार्क कार्नी को नया प्रधानमंत्री चुना गया है, क्या दोनों देशों के रिश्तों में प्रभावी सुधार होगा?

कनाडा की लिबरल पार्टी ने जस्टिन ट्रूडो के उत्तराधिकारी के रूप में मार्क कार्नी को चुन लिया है और वह अब नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ट्रूडो के शासनकाल में कनाडा और भारत के रिश्ते बहुत ही खराब हो गए थे। कनाडाई प्रधानमंत्री ने बेहद गैर-जिम्मेदाराना रीयायत का और सेंसर में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का दोष भारतीय 'एजेंट' पर मढ़ दिया था। स्वाभाविक ही भारत ने उस दावे को नकार दिया और यह बार-बार कहा कि यदि कनाडा के पास ठोस सबूत हों, तो भारत सरकार इस मामले को देख सकती है। दोनों देशों के रिश्ते पिछले साल अक्टूबर में एक प्रकार से टूट गए थे, जब सिंगापुर में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल को कैनेडा कनाडा के उच्चायुक्तियों से हुई, जिसमें कनाडा ने फिर से भारत पर उंगलियां उठाई और बात यहां तक पहुंच गई कि कनाडा के वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ ने *वॉशिंटन पोस्ट* जैसे चर्चित अखबार में भारतीय गृह मंत्री को भी आरोपेत के घेरे में लेने की कोशिश की। इन सबकी वजह से मामला काफी गंभीर हो गया था।

बहरहाल, अभी घटती लोकप्रियता के कारण जस्टिन ट्रूडो को पद छोड़ना पड़ा और अब कार्नी को नया प्रधानमंत्री चुना गया है, लेकिन सवाल यही है कि कनाडा और भारत के रिश्तों में क्या अब सुधार होगा और ट्रूडो के गलत कदमों से कार्नी पीछे हटेंगे? हां, अगर वह ऐसा करना चाहें, तो उन्हें इस बात से नजर मदद मिलेगी कि तमाम प्रयासों के बावजूद कनाडा की पुलिस निज्जर हत्याकांड मामले को अदालत में नहीं ले जा पाई और सुबूत यह भी है कि निज्जर भारतीयों की हिरासत में लिया गया था, उनको जमानत पर रिहा कर दिया गया है।

वास्तव में, कार्नी की प्राथमिकताओं में कनाडा-भारत द्विपक्षीय रिश्ते शायद ही इस समय ज्यादा महत्व रखेंगे। वहां आगामी अक्सूबर तक राष्ट्रीय चुनाव होने हैं और विपक्षी कंजरवेटिव पार्टी की लोकप्रियता यह कानून के दायरे में किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछली कंडिस सरकार ने इस स्थल को एएसआई के संरक्षण में दे दिया था।

सतारा से चाजपा सांसद उदयनराजे भोसले ने औरंगजेब मजार को हटाने की मांग की थी। महाराष्ट्र से गाय विधायक अबू आसिम आजमी द्वारा मुगल बादशाह औरंगजेब की प्रशंसा में की गई टिप्पणी से हाल ही में विवाद खड़ा हो गया था।

के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। निम्नांतर प्रारूप में सादे कागज पर टाइप किया हुआ आवेदन जिसमें विस्तृत शैक्षणिक, व्यावसायिक योग्यता और अनुभव के साथ पूर्ण वांयोद्वारा दिया गया हो की शक्ति, अवर सचिव, संस्कृति मंत्रालय, कमरा सं. 333-ए, सी विंग, तीसरी मंजिल, शास्त्री भवन, डॉ. राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली-110001 को पंजीकृत/स्पीड पोस्ट द्वारा इस प्रकार भेजें कि वह ईमल्लाईमेट न्यूज में इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से सात दिनों की अवधि के भीतर उन तक पहुंच जाए। सरकारी विभाग/स्वायत्त संगठनों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत व्यक्ति उचित माध्यम से अपने आवेदन जमा करें। आवेदन प्रारुप एवं पद हेतु आवश्यक भर्ती नियमों सहित सम्पूर्ण विवरण संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट http://www.indiaculture.nic.in पर उपलब्ध हैं।

सीबीसी 09101/11/0024/2425

पारसा मानदंड (आयु, अनुभव, वांय प्रोफाइल आदि), रिक्ति विवरण, आवेदन शुल्क एवं अन्य विवरण के लिए बीक की वेबसाइट **https://bank.sbi/web/careers/current-openings** पर लॉग ऑन करें, नहीं आवेदन तथा आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। आवेदन करने और शुल्क भेजने से पहले सुनिश्चित कर लें कि आपके पास एक वैध ईमेल आईडी है जिसे विस्तृत विज्ञापन पढ़ें. कोई अन्य पूछताछ करने के लिए कृपया **"CONTACT US" - "Post Your Query"** लिंक के माध्यम से हमें लिखें, जो बैंक की ऑफिशल वेबसाइट **(https://bank.sbi/web/careers/post-your-query)** पर उपलब्ध है.

- **आवेदन ऑनलाइन जमा करने और शुल्क का भुगतान करने की तिथि: 05.03.2025 से 26.03.2025 तक.**

स्थान: मुंबई
दिनांक: 05.03.2025

महाप्रबंधक (आरसी एंड पीएम)

मॉरीशस के साथ और मधुर होंगे भारतीयों के रिश्ते

भारवती मुखर्जी | पूर्व राजदूत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह मॉरीशस यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नई गति और शक्ति प्रदान करेगी।

नवोनवंद्र रामगुलाम को मॉरीशस का प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरीशस यात्रा सम्पन्नहुइए। यह दोनों देशों को एक सूत्र में बांधने वाले आपस रिश्तों को दर्शाती है। मॉरीशस का चुनिंद देशों में है, जिसने स्वतंत्र भारत के 1948 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए, तब यह देश स्वतंत्र नहीं हुआ था।

वे द्विपक्षीय संबंध साझा इतिहास, जनसांख्यिकी और संस्कृति पर आधारित हैं। द्वीप की 12 लाख आबादी में से भारतीय मूल के लोगों की संख्या लगभग 70 प्रतिशत है। कुल आबादी में 52 प्रतिशत हिंदू हैं और अधिकांश लोग भोजपुरी एवं हिंदी बोलते या समझते हैं। शायद इसी कारण से इस द्वीप राष्ट्र में पवित्र रमायणी एवं आध्यात्मिक संस्कृति का अनुभव भारत से भी कहीं ज्यादा मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। दोनों देशों के बीच संबंधों का एक उल्लेखनीय उदाहरण है ब्रैंड वेंसित, जो मॉरीशस के दक्षिण-पश्चिम में स्थित एक पहाड़ी द्वीप है, जिसे हिंदू रंगा तालाब के नाम से जानते हैं और शिवमंदिर एवं प्रसाद पर चढ़ाने के लिए प्रसिद्ध है।

आज भारत और मॉरीशस के बीच स्थायी सांस्कृतिक और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों को अनेक संस्थानों और माध्यमों से पोषित किया जाता है, जो मॉरीशस विरासत को संरक्षण और बढ़ावा देते हैं। भारत-मॉरीशस संबंधों को नए आयाम उत्कृष्ट उदाहरण गीत गवई की मधुर धुनों में देखा जा सकता है, जिसे 2016 में यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी गई है। गीत गवई भोजपुरी लोक गीतों की एक परंपरा है, जिसे शादियों, त्योहारों और विशेष अवसरों पर प्रस्तुत किया जाता है। यदि किसी को यहां दुनिया के 12 संगीतमय प्रस्तुतियों का आनंद लेने का अवसर मिलता है, तो वह यहां बैठे-बैठे आह, बलिया, छपरा या बनारस घूम आता है, जहां से सम्मानीय गिरमिटिया लोग यहां आए थे।

पटना में स्थापित मॉरीशस के राष्ट्रीयता विवसाघर रामगुलाम की प्रतिमा, शतनीयों को व केवल दोनों देशों की साझा धरोहर की याद दिलाती है, बल्कि एक स्वतंत्रता के विशेष मुद्दों में से कांधती है। भूमिक भाग की संस्कृति और सभ्यता अत्यधिक जटिल व विविधतापूर्ण है, इसलिए भारत के विकास के साथ-साथ आप्रवासी भारतीयों की भूमिका के बारे में विचारों में भी कई बदलाव आए हैं। एक आम और व्यापक स्वीकृत धारणा है कि भारतीयों के लिए संपूर्ण विश्व एक परिवार है। यह विचार भारत की सबसे बड़ी संपदा है, जो 'सॉफ्ट पावर' के रूप में भारत के निर्माण में शामिल है।

1901 में डच्चन से शुरूई जाने वाला गांधीजी संक्षिप्त अवधि के लिए मॉरीशस में रुके थे और उनके इस दौरे से यहां परिवर्तन की प्रक्रिया को गति मिली थी, जिसके परिणामस्वरूप मॉरीशस में समान अधिकारों के लिए राजनीतिक संघर्ष शुरू हुआ। जब मॉरीशस ने 1968 में उपनिवेशवाद की बेड़ियों को तोड़ा, तो उसने गांधीजी की श्रद्धांजलि अर्पित करने और अपनी महत्वपूर्ण ने पहिन्द संबंधों का उल्लेख मनाने के लिए 12 मार्च को मॉरीशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे, जिसमें भारतीय वायु सेना की आकाश गंगा टीम सहित भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी भी भाग लेगी। बताया जाता है कि इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के सिलसिले में भारतीय नौसेना का एक जहाज भी मॉरीशस का दौरा करेगा। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच अनेक समझौतों पर हस्ताक्षर होने हैं और साथ ही, अनेक विकास परियोजनाओं की नींव रखी जाएगी। इन सबसे मॉरीशस भारत के जुड़ाव को बल मिलेगा। वाकई, दोनों देशों के संबंधों का भविष्य उज्ज्वल है।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

सच्ची विनयशीलता

धार्मिक व्यक्ति वास्तव में वह नहीं है, जो चोगा या लंबोटी पहनता है, जो दिन में एक बार भोजन करता है, जिसने विधि-निषेध के अनगिनत द्वार ले रखे हैं। धार्मिक व्यक्ति वह है, जो अपने अंतर में सरल है, जो कुछ बनने की फिराक में नहीं है। ऐसे मन में अबाधगामी ज्ञानशक्तिला होती है, क्योंकि वहां कोई अवरोध नहीं, कोई भय नहीं है, किसी लक्ष्य की ओर बढ़ना नहीं है। ऐसा मन अनुकंपा को, ईश्वर को, सत्य को अथवा जो भी नाम आपदें, जो इशल करने में सक्षम होता है। परंतु यथार्थ के पीछे दौड़ने वाला मन सरल नहीं है। वह मन, जो दूढ़ रहा है, टटोल रहा है, विश्वस्त है, सरल नहीं है। जो मन अंदरा या बाहर से किसी भी अधिकारपूर्ण रवाब के सांचे में ढाला गया प्रयत्न करवा है, संकल्पशील नहीं हो सकता।

जब मन वास्तव में संवेदनक्षम होता है, यानी अपने साथ घटित होने वाली तमाम प्रक्रियाओं के प्रति सावधान होता है; कुछ होने या बनने के लिए अपने को किसी सांचे में नहीं ढाल रहा होता, केवल तभी वह सत्य को ग्रहण करने की क्षमता रखता है। जब मन तथा हृदय सरल अतएव संवेदनशील हो जाते हैं, किसी प्रकार के रवाब, निंदा या अशंसा के नहीं, तब हम देखेंगे कि हमारी समस्याएं बड़ी सरलता से हल हो जा सकती हैं। वे किताबी भी जटिल क्यों न हों, उन्हें हम एक नई दृष्टि, अलग ढंग से देख पाएंगे। वर्तमान समय में सरलता की आवश्यकता है। ऐसे व्यक्तियों की, जो इस बहारी विक्षोभ, आंतरिक, विशेषभाव का नए ढंग से, सर्जनात्मक तरीके से सामना करने की क्षमता रखते हैं, न कि वाग्मियों अथवा दक्षिणमंत्रियों विद्वानों के बारे में। यदि आप सरल नहीं हैं, तो आप इसका सामना नवीन रूप से नहीं कर पाते।

जब मन वास्तव में संवेदनक्षम होता है, कुछ होने या बनने के लिए अपने को किसी सांचे में नहीं ढाल रहा होता, केवल तभी वह सत्य को ग्रहण करने की क्षमता रखता है।

स्वयं की समझता में जाल होना अत्यधिक आवश्यक है। उसी से सरलता, विश्वसीलता आती है, जो न तो सदृष्ण है, न कोई अभ्यास। वह मन, जो अपने को विनय बनाता है, विनम्र नहीं होता। जब सच्ची विनयशीलता होती है, प्रयत्न से प्राप्त की हुई नहीं, तभी जीवन की समस्याओं का सामना किया जा सकता है, क्योंकि तब व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं रह जाता, तब वह सिर्फ अपनी कठिनाइयों व अपने महत्व के नगदेपने से नहीं देखता, वह समस्या को सीधे-सीधे देख पाता है और तभी वह उसका समाधान कर सकता है।

जे कृष्णमूर्ति

धर्मध्वज प्रधान | केंद्रीय शिक्षा मंत्री

भारत को गुलाम बनाने के लिए आक्रांताओं ने सबसे बड़ी चोट हमारी ज्ञान परंपरा पर की थी। आज जब हम विकसित भारत का निर्माण कर रहे हैं, तो हमें अपनी ज्ञान परंपरा के पुनर्जागरण के साथ-साथ उसे आधुनिक विज्ञान, अनुसंधान और नवाचार से भी जोड़ना होगा।

ऑनलाइन गेमिंग से कई तरह के फायदे

ऑनलाइन गेमिंग के तमाम तरह के नुकसान बताए हमारे हैं, लेकिन इसके कुछ फायदे भी हैं। दिक्कत बस यही है कि इसकी नकारात्मकता का ज्यादा शोर मचाया जाता है, जिससे आम धारणा इसके खिलाफ बनने लगती है। मगर यह वास्तव में किसके काम की चीज है, यह नहीं जानता है, जो इस तरह के खेल खेलता है। हर इंसान अपनी रुचि कुछ विशेष हासिल करना चाहता है। यह गलत भी नहीं, क्योंकि इसी की बदौलत तो मानव समाजका का विकास हुआ है। अगर विकास के किसी पायदान पर इंसान संतुष्ट हो गया होता, तो आज हम चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाते। पैसों का भी यही मामला है। पूंजि हम भौतिक सुख में रहते हैं, इसलिए पैसे कमाने की हमेंम आकांक्षा होती है। ऐसे में, ऑनलाइन गेम हमारी काफी मदद कर सकते हैं। यहां से कई लोगों ने पैसे कमाए हैं। जरूरतमंदों को इससे काफी सहारा मिला है।

सिर्फ यही नहीं। ऑनलाइन गेम समस्या-समाधान, दैमनकें और हमारी रचनात्मक सोच को भी प्रोत्साहित करते हैं। यहां हम जीतने की तमन्नाहैं खुद बनाते हैं, जिससे हमारी कल्पना की उड़ान नई ऊंचाई पर पहुंच सकती है। यहां हम इस तरह के खेल तो नहीं होते, जो एक ही इस्तीफाम में सीमित होते हैं। जो भारतीय में सैकड़ों सैकड़ों साल पहले से खेले जाते हैं। ऐसे नकारात्मकता से हमें दूरी बनाकर रखनी चाहिए।

फेसबुक पर शेयर दरअसल कोई रंग ही नहीं है। कह सकते हैं कि अगर कोई रंग नहीं है तो खेलना, तो अपने कौशल का डंका पूरी दुनिया में बजा सकते हैं।

ऑनलाइन गेम लोगों की जीत और हार को शालीनता से संभालना सिखा सकता है। यह अनुभव उनको बेहतर खिलाड़ी बनने में मदद पहुंचाता है। इंटरनेट की दुनिया में क्रिकेट या ताश से जुड़े खेल तो नहीं होते, कई ऐसे ऑनलाइन गेम हैं, जो भारतीयों में मौलिक रुचि पैदा करते हैं। जो भारतीयों में मदद्दार मानने जाते हैं और खेलने हैं। हमें यह भी पता होना चाहिए कि अच्छाई और बुराई समय होती है, लेकिन अगर हम अपना और अपने समाज का भला चाहते हैं, तो हमें अच्छाई को स्वीकार करना चाहिए। ऑनलाइन गेम को लेकर भी हमें इसी तरह की सोच रखनी चाहिए। इसकी नकारात्मकता से हमें दूरी बनाकर रखनी चाहिए।

रंजीत कुमार, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम
ऑनलाइन गेमिंग

राष्ट्रीय आपदा बनते जा रहे ऐसे खेल

आज का युग तकनीक का युग है, जहां हर हाथ में स्मार्टफोन की चमक और हर मन में सपने डिजिटल दुनिया का सम्मोहन फैला है। यह चकाचौंध भरी दुनिया सुख-सुविधाओं का भारी खजाना तो लेकर आई है, मगर गहन अंधेरे भी अपने साथ लेकर आई है। इन अंधेरों में सबसे भयावह है ऑनलाइन गेमिंग का जाल, जो एक तरह की सट्टेबाजी है और भारतीय समाज व अर्थव्यवस्था पर कहीं बादलों की तरह छा गया है। तकनीक के अनियंत्रित विस्तार और डिजिटल प्लेटफॉर्मों की सहज उपलब्धता ने इस अवैध धंधे को चरम तोड़ में एक सुनियोजित और विशाल उद्योग में तब्दील कर दिया है। यह महज गैरकानूनी कारोबार नहीं, बल्कि एक ऐसी त्रासदाना बीमारी है, जो हमारे सामाजिक ताने-बाने को चुपचाप खोखला कर रही है और आर्थिक स्थिरता को खतरनाक के कगार पर खड़ी है।

स्थिति की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अक्सर से दिसंबर 2024 के महज तीन महीनों में ऑनलाइन सट्टेबाजी मंचों पर करीब 1.6 अरब से ज्यादा जिजिट दर्ज की गईं। यह आंकड़ा उस विनयशकारी हकीकत का माहन एक झरोखा है, जो इस उद्योग के राक्षसी आकर और प्रभाव को उजागर करता है। एक तरीके समूह के अनुसार, ऑनलाइन गेमिंग का यह अवैध उद्योग प्रतिवर्ष 8.3 लाख करोड़ रुपये से अधिक के लेन-देन को पार कर चुका है और 30 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। यह बात देश की प्रगति में योगदान देने के बजाय घाले बाजार में समा रहा है। पूरा वर्ग, जो देश का चालक है, इस दल के चंगुल में फंसकर अपनी ऊर्जा और संभावनाओं को नष्ट कर रहा है। लिहाजा, अगर अब भी इसे नहीं रोका गया, तो आने वाली पीढ़ियां इसकी कीमत चुकाएंगी।

इस मायाजाल से बाहर निकलने के लिए एक व्यापक रणनीति की आवश्यकता है। नागरिक समाज में जागरूकता फैलाने और लोगों को इस लत से बचाने के लिए प्रयास करने होंगे। स्कूलों और कॉलेजों में इसके दुष्परिणामों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। साथ ही, उन प्रभावशाली हस्तियों पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जो अपने रसूक के लिए इसका प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। यह एक युद्ध है, जिसको जीतने के लिए हर स्तर पर संकल्प और संयम की जरूरत है। जाहिर है, यह केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हम सबकी सामूहिक जवाबदेही है कि हम इस का चलिए हैं, इस दल के चंगुल से फंसकर अपनी ऊर्जा और संभावनाओं को नष्ट कर रहा है। लिहाजा, अगर अब भी इसे नहीं रोका गया, तो आने वाली पीढ़ियां इसकी कीमत चुकाएंगी।

हिन्दुस्तान
1936 से
निर्भय • निष्पक्ष • निर्बाध

धर्मक्षेत्र

राग-रंग से परे होकर रंग जाना ही होली है

जीवन में राग-रंग की बहुत अहमियत है। इनके बिना जीवन न केवल सूना, बल्कि बेमजा भी होता है। फाल्गुन के महीने में ही जीवन और प्रकृति में उल्लास छाने लगता है, जो होली पर अपने चरम पर होता है। होली न सिर्फ बाहर से बल्कि भीतर से भी रंग जाने की सीख देती है

अध्यात्म

सद्गुरु

सृष्टि महज एक खेल है- राग और रंगों का। फाल्गुन के महीने में यह खेल अपने चरम पर होता है, प्रकृति के मनोहारी व लुभावने रूप को निहार कर जीवों के भीतर राग हिलोरें लेने लगता है। ये भीतर की हिलोरें, जब बाहर प्रकट होती हैं भी व्यक्ति हों, लेकिन अगर आप लाल कपड़े पहनकर आते हैं तो लोगों को यही लगेगा कि आप जोश से भरपूर हैं, भले ही आप हकीकत में ऐसे न हों। इस तरह लाल रंग के कपड़े आपको अचानक जोशीला बना देते हैं।

देवी (चेतना का नारी स्वरूप) इसी जोश और उल्लास का प्रतीक है। उनकी ऊर्जा में भरपूर कंपन और उल्लास होता है। देवी से संबंधित कुछ खास किस्म की साधना करने के लिए लाल रंग की जरूरत होती है।

नीला रंग सबको सम्मोहित करके घालने का रंग है। आप देखेंगे कि इस जगत में जो कोई भी चीज बेहद विशाल और आपको समझ से परे है, उसका रंग आमतौर पर नीला है, चाहे वह आकाश हो या समुद्र। जो कुछ भी आपको समझ से बड़ा है, वह नीला होगा. क्योंकि नीला रंग सब कुछ को अपने में समेट लेता है। आप जब पूरा आकाश देखते हैं और सारा-सारा समुद्र देखते हैं, तो आप भी नीले हो जाते हैं। अगर आपके पीछे मौजूद कोई चीज नीली है, तो आप भी नीले हो जाते हैं। आपके भीतर कोई पूर्वाग्रह होता ही नहीं। आप जहां भी होते हैं, उसी का हिस्सा हो जाते हैं। लेकिन किसी

होली पर विशेष

-लगातार लंबे समय तक काले रंग के कपड़े पहनते हैं और तरह-तरह की स्थितियों के संपर्क में आते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी ऊर्जा कुछ ऐसे घटने-बढ़ने लगेगी कि वह आपके भीतर के सभी भावों को सोखा लेगी और आपको मानसिक हालत को बेहद अस्थिर और असंतुलित कर देगी। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह हैं, जहां एक विशेष कंपन और शुभ ऊर्जा है तो वहां पहनने के लिए सबसे अच्छा रंग काला है क्योंकि ऐसी जगह से शुभ ऊर्जा ज्यादा-से-ज्यादा आत्मसात होती है।

सफेद गायी श्वेत दरअसल कोई रंग ही नहीं है। कह सकते हैं कि अगर कोई रंग नहीं है तो रंग पहनते हैं तो लोग जान जाते हैं कि यह संन्यासी है। भगवा या गेरुआ रंग आज पक्का रंग है और आज ज्ञान-प्राप्ति का सूचक है। जो लोग आध्यात्मिक पथ पर होते हैं, वे उच्चतम पक्का रंग पहनना चाहते हैं इसलिए ये इस रंग को पहनते हैं।

राग का अर्थ है- रंग। रंग से जो परे है, वह रंगहीन नहीं, पारदर्शी है। वैराग्य का मतलब है कि आप न तो कुछ रखते हैं और न ही कुछ परावर्तित करते हैं, सारी आप पारदर्शी हो गए हैं। अगर आप पारदर्शी हो गए हैं तो आपके पीछे की कोई चीज अगर लाल है, तो आप भी लाल हो जाते हैं। अगर आपके पीछे मौजूद कोई चीज नीली है, तो आप भी नीले हो जाते हैं। आपके भीतर कोई पूर्वाग्रह होता ही नहीं। आप जहां भी होते हैं, उसी का हिस्सा हो जाते हैं। लेकिन किसी

राज्यसभा : भाजपा सदस्य ने उठाया आशा वर्करों का मुद्दा

सरकार से इस दिशा में उचित कदम उठाने का आह्वान किया

नई दिल्ली (एसएनबी)। भाजपा की रेखा शर्मा ने सोमवार को राज्यसभा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत नियुक्त आशा कार्यकर्ताओं को होने वाली समस्याओं पर चिंता व्यक्त की और सरकार से इस दिशा में उचित कदम उठाने का आह्वान किया।

उच्च सदन में बृन्दावन के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने कहा, आशा कार्यकर्ता ग्रामीण और समुदायिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की रीढ़ हैं। वे गर्भवती महिलाओं से लेकर बुजुर्गों तक की देखभाल करती हैं। उन्होंने कहा, आशा कार्यकर्ताओं को पैदल, स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली बीच और महत्वपूर्ण लंबे क्षेत्र आवश्यक सामाजिक मुद्दा लगभग भी नहीं मिलती है, जिस कारण वे वित्तीय रूप से भी असुरक्षित हो जाती हैं।

आप के अलोक मिलन ने बरीबता क्रम की मुद्दों में सांसदों को नौवें रखे जाने का मुद्दा उठाया और सरकार से अनुरोध किया कि उन्हें मौजूदा 21वें स्थान से हटाकर सम से कम महत्वपूर्ण स्थान पर किया जाए।

महाकुंभ से प्रयागराज बना विश्व पर्यटन केंद्र

- विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ने से पर्यटन उद्योग की उम्मीद जगी
- कोविड के बाद बढ़ने लगी है विदेशी पर्यटकों की संख्या
- 167 देशों के लिए उपलब्ध है ई वीजा सुविधा

■ संजय टुटेजा
नई दिल्ली। एसएनबी

महाकुंभ में विश्व पटल पर प्रयागराज ने पर्यटन मंत्रालय के रूप में पहचान बनाई है और महाकुंभ के दौरान यहां आये विदेशी पर्यटकों की संख्या ने पर्यटन उद्योग की उम्मीदें बढ़ा ही हैं। हालांकि देश में विदेशी पर्यटकों की संख्या अभी भी कोविड से पूर्व की स्थिति तक नहीं पहुंची है लेकिन हाल ही में जिस तरह विदेशी पर्यटकों की आवाजाही में तेजी आई है उससे पर्यटन उद्योग को राहत मिली है। देश के पुनिए राज्यों को छोड़कर अधिकतर राज्यों में विदेशी पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई।

कोरोना महामारी के बाद से ही देश का पर्यटन उद्योग संकट से दौर में है लेकिन महाकुंभ ने देश के पर्यटन उद्योग की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। प्रयागराज में 45 दिनों तक चले महाकुंभ के दौरान करीब 55 लाख विदेशी पर्यटक पहुंचे, यह केवल प्रयागराज और उत्तरप्रदेश को ही उपलब्धि नहीं रही बल्कि विदेशी पर्यटकों की यह संख्या देश के लिए भी बड़ी उपलब्धि रही। वर्ष 2019 में हुए कुंभ के दौरान प्रयागराज में लगभग 10.3 लाख विदेशी पर्यटक आए थे। यदि वर्ष 2024 का आंकड़ा देखा जाये तो यह पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में विभिन्न पर्यटन स्थलों पर कुल 65 करोड़ पर्यटक पहुंचे, जिनमें 23 लाख विदेशी थे जबकि वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या 16 लाख रही, जबकि 2022 में 6.5 लाख पर्यटक आए। महाकुंभ 2025 में प्रयागराज ने विश्व पर्यटन मानचित्र पर एक मजबूत और प्रतिष्ठित उपस्थिति दर्ज कराई, जिसमें लगभग 67 करोड़ श्रद्धालु संगम में पवित्र डुबकी लगाने के लिए शहर आए जिनमें 55 लाख विदेशी थे। सरकार के आंकड़े बताते हैं कि महाकुंभ में 73 देशों के राजनियक और 116 देशों के विदेशी श्रद्धालु शामिल हुए।

दरअसल कोरोना महामारी संकट के बाद से केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय लगातार विदेशी पर्यटकों का आकर्षित करने का प्रयास कर रहा था। इसके लिए मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु जैसी घोषणाएं करने के साथ साथ पहले इंडिया अभियान, अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट व भारत पर्व जैसे आयोजन भी किये गये। सरकार के इन प्रयासों का हालांकि विदेशी पर्यटकों की संख्या पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं दिखाई दिया लेकिन प्रयागराज में महाकुम्भ विदेशी पर्यटकों की संख्या की दृष्टि से एक बड़ा कारक जरूर बना।

महाकुंभ में आये अनेक विदेशी पर्यटकों ने भारत के अन्य पर्यटन स्थलों का भी प्रभाव किया उनसे महाकुंभ का अवसर भारत के लिए विश्व के पर्यटकों को भारत की संस्कृति दिखाने का प्रमुख अवसर तो बना ही साथ ही जहां प्रयागराज का वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान मिली वहीं भारत भ्रमण को लेकर भी विदेशी पर्यटकों में आकर्षण बढ़ा है।

पर्यटन मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि देश में कुछ चुनिंदा राज्यों को छोड़कर अधिकतर राज्यों में विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ी है और इनकी संख्या पीरि पीरि कोरोना से पूर्व की स्थिति में पहुंच रही है। पर्यटन से जुड़े उद्योगों का कहना है कि महाकुंभ का आयोजन पर्यटन उद्योग को गति देने में महत्वपूर्ण भद्दरयार साबित होगा।

एनआरएचएम घोटाला : ईडी ने करोड़ों की संपत्ति कुर्क की

- ये अचल संपत्तियां लखनऊ और वाराणसी में स्थित हैं

नई दिल्ली (एसएनबी)। ईडी ने उत्तर प्रदेश में एनआरएचएम घोटाले के सिलसिले में पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत 89.84 लाख रुपये की चल और अचल संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। कुर्क की गई संपत्तियों में एपके पांडे और एके शुक्ला के नाम पर 68.62 लाख रुपये मूल्य की 7 बैंक जमा राशि, निरामा पांडे के नाम पर 10.16 लाख रुपये मूल्य की एक मकान संपत्ति और एसएन गुप्ता के नाम पर 11.06 लाख रुपये मूल्य की एक संपत्ति शामिल है। इन सभी संपत्तियां लखनऊ और वाराणसी में स्थित हैं।

ईडी ने वर्ष 2012 में सीबीआई द्वारा आईपीसी 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न अनुसूचित धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। यह आरोप लगाया गया था कि एस के पांडे एस के डिप्टीकमिश्नर के मालिक, एके शुक्ला वर्ष एक कंपनी के मालिक, निरामा पांडे जब गाजियाबाद में मालिक, एस एन गुप्ता श्याम मेडिकल एजेंसी और अन्य ने वर्ष 2005 से 2011 के बीच सरकारी नियमों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए सरकारी अस्पतालों के लिए एनआरएचएम आईटी आदेश प्राप्त करने के लिए लिता सरगानी, गाजीपुर, जौनपुर और पंदोली के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के साथ एक आपराधिक साजिश रची।

अनमोल वचन

जीवन की जड़ संयम की भूमि में जितनी गहरी जमती है और सद्व्यवहार का जितना जल दिया जाता है उतना ही जीवन हरा-भरा होता है और उसमें ज्ञान का मधुर फल लगता है
-दीनानाथ दिनेश

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • मंगलवार • 11 मार्च • 2025
www.rashtriyasahara.com

संपादकीय 8

editpagesahara@gmail.com

यूं ही नहीं है विवाद

संभल में होली और जुमे की नमाज दोबारा एक साथ पड़ने के कारण जो विवाद का विषय पूं ही नहीं बना हुआ है। हालांकि संभल के सीईओ अनुज चौधरी के बकाया को आधार बनाकर कई पार्टियों, नेता और मीडिया का एक वर्ग आलोचना कर रहा है। साथ के बरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने तो यहां तक कह दिया कि ऐसे लोग जब सरकार बदलेगी तो जेल में होंगे। बीजी को बुद्ध और दादा तक की संज्ञा दे दी गई है।

मुस्लिम संगठनों सहित अनेक मुस्लिम नेताओं ने तो उनके विकास ऐसा अभियान पलता दिया है मानो वे संभल में आति नहीं वाकिब अशांति के कारण बन चुके हैं। क्या वाकई अनुज चौधरी ने संभल दिया है जिससे उनके विरुद्ध इस तरह का माहौल बन पाहिए? सामान्य और दर देखें तो होली और जुमे की नमाज एक ही दिन हो रही है तो निश्चित रूप से प्रशासन का दायित्व दोनों को शांतिपूर्वक संपन्न कराने की है। कोई एकपक्षीय बयान देकर किसी समुदाय को नाराज करे तो उसके लिखा आवाज उठनी चाहिए। किंतु क्या वाकई संभल का माहौल ऐसा ही है? इसमें जुड़े दोनों पक्षों को समझे बगैर हम कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दे सकते। निस्संदेह, भारत में 116 करोड़ से बीछ ज्यादा हिन्दू और 22 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं तो दोनों को मिलजुल कर ही रहना है। यह दोनों समुदायों की जिम्मेवारी है कि वे एक दूसरे को समझाएं, सोहदाबाजी का ध्यान रखी हुए तथा अपने उत्सवों के मनाने के अनुसार देखा आचरण करें जिससे समस्याएं पैदा नहीं हो।

इसी तरह पुलिस प्रशासन का दायित्व हर हाल में शांति कायम बनाए रखने का पूर्वोपाय करना है। अगर कहीं समस्या पैदा हुई तो पुलिस प्रशासन के लिए उसे देना कठिन होता है। अनुज चौधरी का बयान इसी के संदर्भ में था। साथ ही कि उनके बयान को दो पक्षों को निकाल कर संगाय पैदा कर दिया गया और यही बताते हैं कि कुछ लोग किस तरह देश में सांप्रदायिक तनाव, हिंसा पैदा करना चाहते हैं। यह वर्ग योगी आदित्यनाथ सरकार एवं नरेन्द्र मोदी सरकार के विरुद्ध माहौल बनाने के लिए झूठ का नैरेटिव चला रहा है। अनुज चौधरी के बयान को देखे तो उसमें यह पंक्ति है कि जुमे की नमाज दोनों में होगी। इसमें कहीं भी किसी को नीचा दिखाने का भाव नहीं है। उन्होंने कहा, वह सात साल से शहरी सेवायें की अधिकारी होती हैं और यह जमीनी सेवायें की अधिकारी होती हैं। उन्होंने कहा, वह सात साल से शहरी होता है। मालीहाल ने कहा, मेट्रो संपर्क कराते हैं और उन्हें रोज मेट्रो से आना जाना होता है। उन्होंने कहा, वह सात साल से शहरी सहायोग नहीं मिला।

फिर निशाने पर मंदिर

अमेरिका में मंदिरों को बार-बार निशान बनाने की घटना बावर्ड लकलीफदेह है। लास एंजिल्स में तथाकथित 'खालिस्तानी जनमत संग्रह' से कुछ दिन पहले कैलिफोर्निया के पिनो हिल्स स्थित स्वामीनारायण मंदिर पर आपत्तिजनक संदेश लिखकर इसे क्षतिग्रस्त कर दिया। दरअसल, ऐसी घृण्ता पहली बार नहीं की गई है। पहले भी मंदिरों पर इस तरह के हमले हुए हैं। आतातायी तत्व नफरत को हर हाल में फैलाना चाहते हैं। साथ ही हिन्दू समुदाय के विरोध में अपना सक्कुछ छांक देना चाहते हैं। हालांकि किंदेन मंत्रालय ने इस कायराना और घृणित कृत्य की कड़ी भर्त्सना की है, साथ अमेरिकी सरकार को भी इस मामले में सख्ती दिखाने होगी। ऐसी घटनाओं से सनातनियों के पर उन्हें ठेसें के बीच रिश्तों में खटास आएगी। क्योंकि कहने हुई इस तरह की हरकतों में किसी तरह की कोई कार्रवाई भी नहीं की गई है और न किसी तरह की कोई जांच कार्याई नहीं है। गौरतलब है कि अमेरिका की ही नहीं। कनाडा में भी पिछले साल नवम्बर के महीने में क्रैम्पटन शहर में हिन्दू सभा मंदिर के सामने खालिस्तानी घरमर्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारी जबरन परिसर में घुस गए थे और मंदिर प्रशासन के कार्यकर्ता और श्रद्धालुओं पर हमला बोल दिया था। उन्होंने महिलाओं व बच्चों को भी बेरहमी से पीटा था। यही नहीं, खालिस्तानी अलगाववादियों ने मंदिर परिसर के पास मंदिर प्रशासन और भारतीय उच्चायोग की हरफ से मिलकर लगाए गए बीजा शिविर को भी निशान बनाया था। उस दौरान इसकी कड़ी निंदा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने की थी। बहरहाल, चाहे अमेरिका हो, कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया; हर जगह हिन्दू समुदाय और उनके पवित्र स्थलों को बेदर्दी से नुकसान पहुंचाने की साजिश होती रही है। हास्यास्पद है कि इन सब घटनाओं को लेकर संबंधित सरकार का रवैया भी ठाल्ही दिखाता है। उन्होंने की जानी चाहिए कि अपराधियों पर कानूनी में कुछ अलग हटकर काम करेगी और हिन्दुस्तान की भावनाओं की कद्र करेगी।

चिंता/बलदेव राज भारतीय

विचारों का प्रदूषण खत्म हो

जिस प्रकार विश्व एक स्वस्थ तन के तांने बाने को नष्ट कर उसे मिट्टी कर देता है, उसी प्रकार विचारों विषाद एक स्वस्थ मन को रोगग्रस्त कर तन मन के साथ जीवन को भी नष्ट कर देते हैं। हम जब भी प्रदूषण की बात करते हैं, तो प्रायः हमारे मन में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मिट्टी के प्रदूषण की छविया उभरती हैं, लेकिन इन सबसे अधिक खतरनाक और विनाशकारी प्रदूषण यदि कोई है, तो वह है-विचारों का प्रदूषण!

विचारों के प्रदूषण का मतलब है, मानव मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले नकारात्मक विचार हैं। ये विचार मानसिक और नैतिक गिरावट का कारण बनते हैं। ये विचार व्यक्ति के मन को प्रभावित करते हैं, जिससे वह पूरा समाजिक तंत्र-जाने को नष्ट कर सकता है। जिस प्रकार वायु प्रदूषण सांस लेने योग्य शुद्ध वायु को जहरीला बना देता है, उसी प्रकार विचारों का प्रदूषण समाज के नैतिक और सांस्कृतिक वातावरण को दूषित कर देता है। इससे समाज में नकारात्मकता, कटुता, असहिष्णुता, और अपराध जैसी समस्याएं जन्म लेती हैं। मानुष अपने विचारों से ही महान बनते हैं और वे गिरिन भी होते हैं। विचारों का यह प्रदूषण किसी एक दिन में उत्पन्न नहीं होता, बल्कि धीरे-धीरे यह समाज की मानसिकता में घर कर लेता है। इसके कई कारण हो सकते हैं जैसे मीडिया में सनसनी का पान, पहले संकुक्त परिवारों में बच्चों को नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जाती थी, लेकिन आधुनिक समाज में संयुक्त परिवारों का विघटन हो चुका है। माता-पिता के पास बच्चों के लिए समय नहीं है, और नैतिक शिक्षा की विभिन्नदारी केवल स्कूलों पर छोड़ दी जाती है। दूसरा प्रमुख कारण वैश्वमान सोशल मीडिया है। यह विल्कभी और अन्य माध्यमों के सामने के सामने के सामान्य अलगेलगा और हिंसा का बहुत प्रभाव विचारों को दूषित कर रहा है। इस प्रदूषण का सबसे प्रभावी समाधान नैतिक शिक्षा, संस्कारों का उत्थान, और समाज में सकारात्मक वातावरण का निर्माण है। जिस प्रकार भगवान बीरान ने वहा-दूषण जैसे राक्षसों का संहार किया था, उसी प्रकार हमें भी दूषित विचारों का नाश करके समाज को नैतिकता की ओर अग्रसर करना होगा।

यूं ही नहीं है विवाद

संभल में होली और जुमे की नमाज

■ अवधेश कुमार

फलवाला है, अर्थात् अवाहीं है और फलवाला की तरह स्पष्ट बोलता है। उन्होंने भी लगभग वही बातें कीन्हीं जो अनुज चौधरी ने कहा। इस तरह अनुज चौधरी का बकाया योगी आदित्यनाथ सरकार के विपरीत की ही अभिव्यक्ति है। यह साथ है कि इसके पहले भी होली और जुमे का मामला एक दिन हुआ है। किंतु यह कहने वाले भूल जा रहे हैं कि जिन लोगों या क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी है वहां कई बार यह शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है कई बार अशांति पैदा हुई, हिंसा हुए, दंगे भी हुए।

आप दंगों के इतिहास का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि इनमें से बड़ी संख्या में हिन्दू जुलसों या महापर्वुगों दिवसों के दिन या उसके पहले हुए रहे। पिछले 3 वर्षों में हिन्दू धर्म ने जुड़ी शोभा यात्राओं, महापर्वुगों तिथियों के दिन पत्थरबाजी, आगजनी, हमले और गड़बड़ियां किया हुए हैं। क्या हम पिछले वर्ष 24 नवम्बर को संभल में हुई हिंसा भूल गए? अदालत न्यायालय के आदेश से सर्वेक्षण टीम वहां आई थी, कहीं दूसरी तरफ सालों बीत जाने के बावजूद मंदिर पर खतरा कहीं को कहा से सिद्धनी टीर पर खतरा कहीं को कहा से सिद्धनी टीर पर खतरा कहीं को कहा से सिद्धनी टी